वार्षिक रिपोर्ट
1981-82

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट

1981-82

17-बी, श्री अरविन्द मार्ग नई दिल्ली-110016

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-9362
DOC, No.....
Date.....8-12-96

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
	आभार ज्ञापन	(v)
	विहंगावलोकन	1
भाग—1	नीति आधार के उद्देश्य और अंग	
	उद्देश्य	9
	परिषद्	10
	कार्यकारिणी समिति	11
	वित्तीय समिति	11
	कार्यक्रम सलाहकार समिति	12
भाग—2	कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की समीक्षा	
	क. वर्ष 1981-82 के दौरान चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम	13
	ख. अनुसंधान और अध्ययन	21
	ग. अंतर्राज्यीय वीक्षण	27
	घ. कार्यक्रम नियोजन तथा क्रियान्वयन के लिए परामर्शकारी बैठक	28
	ङ. संकाय परिचर्चा समूह	30
	च. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	33
	छ. अतिथिगण	34
	ज. पुस्तकालय और प्रलेखन सेवा	34
	झ. प्रकाशन	36
भाग—3	सलाहकारी, परामर्शकारी तथा सहायता सेवा	
	1. राष्ट्रीय	41
	2. उप राष्ट्रीय	42
	3. अंतर्राष्ट्रीय	43

संकाय सदस्यों के वेतनमानों में संशोधन तथा उनके पदों में परिवर्तन करने पर उप समिति 45
संकाय तथा अकादमिक सहायता का पुनर्गठन 46
कार्य शक्तियां (बल) 47
समितियां 47
प्रशासन का पुनर्गठन 47
संकाय और अन्य स्टाफ का सुदृढ़ीकरण 48
सेवाकालीन प्रशिक्षण 48
स्टाफ परिवर्तन 49
छात्रावास 50
निर्माण कार्यक्रम 51
अन्य आधारिक संरचनायें 52
वित्त 53

अनुबंध

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम 54
2. अतिथिगण 102

परिशिष्ट

1. नीपा की परिषद् के सदस्यों की सूची 111
2. नीपा की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची 117
3. नीपा की वित्तीय समिति के सदस्यों की सूची 119
4. कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची 121
5. नीपा का संकाय और अनुसंधान स्टाफ 124
6. 1981—82 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट 125

आभार ज्ञापन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, केन्द्रीय तिबतन स्कूल प्रशासन, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी तथा राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा संस्थान के क्रियाकलापों में ली गई रुचि तथा सहयोग के लिए इन सभी का आभारी है। संस्थान उन विभिन्न विशेषज्ञों का भी आभारी है जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर संस्थान के अनेक कार्यक्रमों के संचालन में अतिथि वक्ताओं/विशेषज्ञों के रूप में काम करके संस्थान को सहयोग दिया। नीपा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना संस्थान, पेरिस, सांख्यिकी का यूनेस्को कार्यालय, पेरिस, एशिया तथा ओशीनिया में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक तथा संयुक्त राष्ट्र एशिया तथा पेसिफ़िक विकास केन्द्र, कोलालम्पुर, क्षेत्रीय विकास का संयुक्त राष्ट्र केन्द्र, एशिया तथा पेसिफिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संघ तथा भारत में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक प्रतिष्ठान द्वारा संस्थान के कुछ कार्यक्रमों के संचालन में दिए गए सहयोग के लिए हृदय से उनके प्रति आभारी है।

विहंगावलोकन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान की, जिसे पहले शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के नाम से जाना जाता था, स्थापना भारत सरकार द्वारा, शिक्षा आयोग (1964-66) तथा 1969 में योजना आयोग के 'शैक्षिक योजना, प्रशासन तथा मूल्यांकन कार्यकारी दल' की सिफारिश पर शिक्षा मंत्रालय तथा समाज कल्याण के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 1970 को की गई थी। संस्थान के उद्देश्य है : शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान करना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करना तथा राज्यों और केन्द्र के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना और अन्य देशों, विशेषकर एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग करना।

यह संस्थान, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त संस्थान है। मूलत: इसका पंजीकरण 31 दिसम्बर, 1970 को शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के नाम से किया गया था। 31 मई, 1979 को इसे दोबारा नए नाम से पंजीकृत कराया गया। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय संस्थान की अप्रैल 1981 से मार्च 1982 तक की अवधि की प्रमुख गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

संस्थान से अपना ध्यान संस्थान के अंदर तथा बाहर के वरिष्ठ शिक्षाविदों और प्रशासकों से विस्तृत परिचर्चाओं के आधार पर अपनी क्रियाकलापों की एक परिप्रेक्ष्य योजना बनाने के कार्य पर केन्द्रित किया है। यह अनुभव किया गया कि संस्थान के कार्यक्रम को सुदृढ़ करने तथा उसका नया अभिविन्यास करने की प्रक्रिया में नियोजित आर्थिक विकास के लक्ष्यों और उद्देश्य से सामान्य रूप से तथा छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों से विशेष रूप से संबद्ध करने पर बल दिया जाना चाहिए। यह देखा गया कि योजना के उद्देश्यों की और अधिक उपलब्धि के साधन के रूप में शैक्षिक नियोजन और प्रशासन में परिशोधन की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। परिप्रेक्ष्य योजना में संस्थान के क्रियाकलापों और कार्यक्रमों को चरणबद्ध रूप से विकसित करने के लिए रूपरेखा

तैयार की गई है। इन क्रियाकलापों में से कुछ सातवीं पंचवर्षीय योजना तक चलते रहेंगे। लघु अवधि के अभिविन्यास कार्यक्रमों के सेट से भिन्न देश में समग्र रूप से शैक्षिक नियोजन और प्रशासन पर मुख्य रूप से प्रभाव डालने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए छह महीने की अवधि वाले पूर्व आगमन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया गया और वर्ष 1982-83 से इन्हें प्रारम्भ करने के लिए उचित तैयारियां की गईं। शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों की अन्तर्राज्यीय वीक्षण की भी व्यवस्था की गई। संस्थान द्वारा राज्यीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर अनेक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। राज्यीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर प्रशिक्षण क्षमताओं का निर्माण करने के लिए क्षेत्रीय यूनिटों को स्थापित करने की संभावना का पता लगाया गया।

वर्ष के दौरान संस्थान को अनुसंधान क्रियाकलापों और अनुसंधान को प्रशिक्षण से संबद्ध करने पर प्रमुख रूप से बल दिया गया। संस्थान ने पहले से लिए गए अनुसंधान अध्ययनों को पूरा करने के अतिरिक्त अनेक नए अध्ययन प्रारम्भ किए। इनमें से कुछ अध्ययनों के परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारक हो सकते हैं।

संस्थान केन्द्रीय और राज्य सरकारों, संस्थानों तथा शैक्षिक नियोजन और प्रशासन में लगे कार्मिकों को परामर्शता तथा अकादमिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता रहा है।

संस्थान की अकादमिक (शैक्षिक) आधारिक संरचना को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया गया तथा परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत संस्थान द्वारा हाथ में लिए गए विविध तथा विकसित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए संकाय और प्रशासन का पुनर्गठन किया गया।

परिप्रेक्ष्य योजना

संस्थान की कार्यकारिणी समिति की 2 मई, 1981 में हुई सातवीं बैठक के निर्णय के अनुसार नीपा की पंचवर्षीय योजना की जांच करने के लिए तथा छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए कार्यक्रमों के पुनर्गठन समेत अगले दस वर्षों की परिप्रेक्ष्य योजना को प्रस्तावित करने के लिए निदेशक, नीपा की अध्यक्षता में एक छोटे समूह का गठन किया गया। इस समूह में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित थे—प्रो० रईस अहमद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, श्री जी० के० अरोड़ा, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव, श्री जे० ए० कल्याणकिष्णन, वित्तीय सलाहकार तथा संयुक्त सचिव (योजना), शिक्षा मंत्रालय और

संस्कृति, डा० एस० एन० सराफ, परामर्शदाता (शिक्षा), योजना आयोग, श्री एस० सत्यम, संयुक्त सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, श्री जे० वीराराघवन, कार्यकारी निदेशक, नीपा, डा० आर० पी० सिंहल, परामर्शदाता, नीपा तथा श्री एम० आर० कोलहातकर, संयुक्त सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय। इस समिति की बैठक 4 अगस्त, 1981 को आयोजित की गई। समिति ने संस्थान के परिप्रेक्ष्य योजना के प्रारूप को सामान्य रूप से सहमति प्रदान की और निदेशक को कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के लिए योजना को प्रस्तुत करने से पहले उसमें पहले की गई परिचर्चा के संदर्भ में आवश्यक सुधार करने का अधिकार प्रदान किया। संस्थान के परिप्रेक्ष्य योजना प्रारूप में तदनुसार अपेक्षित संशोधन करके उसे कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के लिए 3 सितम्बर, 1981 को हुई आठवीं बैठक में प्रस्तुत किया गया। कार्यकारिणी समिति ने संस्थान द्वारा तैयार की गई परिप्रेक्ष्य योजना को सामान्य स्वीकृति प्रदान की। इस योजना में संस्थान के भविष्य विकास जो 270.47 लाख रुपये की कुल लागत सहित छठी पंचवर्षीय योजना के आगे तक चलने वाला है, की व्यापक मार्गदर्शी रेखायें प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त मांग की तुलना में भारत सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 115 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है और 155.47 लाख की कमी रखी गयी है जिसे योजना के मध्य अवधि मूल्यांकन के समय पूरा किया जाएगा।

परिपेक्ष्य योजना के प्रमुख अंश इस प्रकार हैं :

—चूँकि जिला शिक्षा अधिकारी जिले के कठिन स्तर पर शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन का प्रभारी होता है, संस्थान के प्रमुख कार्यक्रमों में उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूर्व प्रस्तावना की गई।

—संस्थान के अनुसंधान घटक पर तथा अनुसंधान को प्रशिक्षण से संबद्ध करने पर अधिक-से-अधिक बल दिया जाना। इस संबंधी में संस्थान ने संस्थागत लागत, शिक्षा की वैकल्पिक विधियों तथा विषयस्तरीय और समस्तरीय अनुबंधता की संभावना पर फोकस करते हुए गुड़गांव के निकटवर्ती जिले में क्षेत्रीय अध्ययन प्रारंभ किए।

—लागत बांटने के आधार पर राज्य सरकारों तथा राज्य में चुने हुए अनुसंधान संस्थानों से त्रिपक्षीय प्रबंध स्थापित कर राज्य स्तरीय यूनिटों का विकास किया जाएगा। कुछ राज्यों जैसे केरला, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश ने ऐसे यूनिटों की स्थापना में रुचि दिखाई है।

—संस्थान में एक अच्छे प्रलेखन केन्द्र का निर्माण किया जहां राज्य अधिनियम, संहिता, तर्कयुक्त निर्णय तथा नीतियों और कार्यक्रमों पर अन्य दस्तावेजों

सहित अनेक कानूनी दस्तावेज एकत्रित किए जा सकें और संदर्भ के लिए रखे जा सकें।

—सूचना और अनुभव के समाशोधन केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए संस्थान में पाँच सदस्यों, जो देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हों, द्वारा चलाए जाने वाले 'उप-राष्ट्रीय पद्धति' समूह का निर्माण।

—जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए पत्रिका सहित संस्थान का विस्तृत प्रकाशन कार्यक्रम।

—ऊपर दिए गए कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने के लिए संस्थान की अकादमिक आधारिक संरचना का सुदृढ़ीकरण।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान संस्थान ने भिन्न-भिन्न अवधि वाले अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की। यह कार्यक्रम संवर्ग आधारित होने के साथ-साथ विषय-अभिविन्यासी भी थे। स्कूल प्रशासकों और कालिज प्रधानाचार्यों आदि के लिए सतत नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त संस्थान ने पहली बार देश भर के केन्द्रीय विद्यालय संस्थान के नए नियुक्त प्रधानाचार्यों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संस्थान के सहयोग से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय तिबतन स्कूल प्रधानाचार्यों ने भी भाग लिया। इसी प्रकार देश के विभिन्न भाग में स्थित परमाणु ऊर्जा स्कूलों के प्रधानाचार्यों और उप-प्रधानाचार्यों के लिए स्कूल प्रबन्धन पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी के सहयोग से भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, बम्बई में किया गया।

संस्थान ने पांडीचेरी में स्कूलों के मुख्याध्यापकों तथा निरीक्षण अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया तथा दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कुछ संगोष्ठियों की व्यवस्था करना रिपोर्टाधीन वर्ष के कार्यक्रमों की विशेष विशेषता थी। उदाहरण के लिए, गैर-मौद्रिक आगत पर बल देते हुए शैक्षिक विकास के लिए संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर एक उपयोगी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जनसंख्या शिक्षा तथा विकास पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें सारे देश के शिक्षा आयुक्तों तथा लोक शिक्षा (स्कूल) निदेशकों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर भी वर्ष के दौरान विशेष ध्यान दिया गया। लम्बे समय की शिक्षा योजना पर जनवरी, 1982 को एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 11 विभिन्न एशियाई देशों से 21 सदस्यों तथा पाँच प्रेक्षकों ने भाग लिया।

वर्ष के दौरान आयोजित 29 कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

कोटि और कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या	कार्यक्रम-दिवसों की संख्या	कार्यक्रम-व्यक्ति-दिन
1. स्कूल शिक्षा का प्रबंध (7 कार्यक्रम)	165 (25 प्रतिशत)	71	11,715 (31 प्रतिशत)
2. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (3 कार्यक्रम)	81 (12 प्रतिशत)	31	2,511 (7 प्रतिशत)
3. उच्च शिक्षा का प्रबन्ध (पांच कार्यक्रम)	119 (18 प्रतिशत)	76	9,044 (24 प्रतिशत)
4. विशेष कार्यक्रम (8 कार्यक्रम)	243 (36 प्रतिशत)	32	7,776 (21 प्रतिशत)
5. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (8 कार्यक्रम)	38 (6 प्रतिशत)	62	2,356 (6 प्रतिशत)
6. पत्राचार कार्यक्रम (1 कार्यक्रम)	18 (3 प्रतिशत)	240	4,320 (11 प्रतिशत)
कुल	664	512	37,772

लक्षदीप को छोड़कर शेष सब राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लिया। बाहर के देशों में अफगानिस्तान, बंगला देश, चीन, नेपाल, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाईलैण्ड तथा संयुक्त राज्य अमरीका ने इसमें भाग लिया।

अनुसंधान और अध्ययन

परिप्रेक्ष्य योजना में अनुसंधान क्रियाकलापों पर अधिक बल देने की दृष्टि से संस्थान ने पहले से लिए हुए अध्ययनों को पूरा करने के अतिरिक्त अनेक नए अनुसंधान अध्ययन प्रारम्भ किए। वर्ष के दौरान किए गए तथा प्रारम्भ किए गए अध्ययन नीचे दिए गए हैं—

1. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 9 राज्यों में सर्वव्यापकता के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन पर अध्ययन।

2. हरियाणा के लिए शैक्षिक मानकों के विकास पर अध्ययन।

3. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक नियोजन, मॉनिटरिंग तथा सांख्यिकी की पद्धति तथा उनकी संगठनात्मक व्यवस्था पर अध्ययन।

4. नीपा में जनसंख्या शिक्षा क्रियाकलाप।

5. गुड़गांव में शिक्षा की लागत।

6 व 7. आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिए जाने पर अध्ययन।

8. शैक्षिक रूप से कुछ प्रगतिशील राज्यों तथा पिछड़े हुए राज्यों में निरीक्षण अभ्यास और प्रपत्र पर अध्ययन।

9. विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन (क्षेत्रीय मूल्यांकन) पर अध्ययन।

10. शैक्षिक प्रशासकों की व्यक्तित्व-विशेषताओं का अध्ययन।

11. तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक स्कूल प्रधान अध्यापकों पर अध्ययन।

12. अच्छे जीवन स्तर के लिए कार्य की आकांक्षा (ए ए बी वयू ओ एल)

13. भारत में शैक्षिक व्यय—एक क्षेत्रीय विश्लेषण।

14. भारत के दो राज्यों में शैक्षिक नियोजन और ईक्विटी नियोजन पर तुलनात्मक नीति अध्ययन।

15. ग्राम विकास : नियोजन और प्रशासन' के लिए शिक्षा के संबंधों और घटक यंत्र में किए गए कुछ प्रयोगों का तुलनात्मक अध्ययन।

16. खंड तथा संस्था स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की विधियां और समस्यायें।

17. पुनर्विचार विकास।

18. भारतीय राज्यों में उच्च शिक्षा के वित्तीयन पर गहन अध्ययन।

सलाहकारी, परामर्शकारी और सहायता सेवायें

संस्थान ने शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आग्रह पर तथा उनके सहयोग से अनेक अनुसंधान अध्ययन और कार्यक्रम प्रारंभ किए।

इसके अतिरिक्त संस्थान, केन्द्र और राज्य सरकारों तथा शैक्षिक नियोजन और प्रशासन में लगी संस्थाओं तथा कार्मिकों को अकादमिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन देता चला आ रहा है। संस्थान ने केंद्रीय और राज्यीय स्तर पर विविध उच्च स्तरीय संमेलनों, समितियों तथा कार्यकारी समूह में भाग लिया। जून, 1981 में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के संमेलन में संस्थान के योगदान की विशेष चर्चा की जा सकती है। इस संमेलन में संस्थान ने छठी पंचवर्षीय योजना में शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित मुख्य कार्यों को सूचित करने तथा इस संबंध में नीपा की भूमिका को बताने के लिए एक टिप्पणी प्रस्तुत किया।

संस्थान शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एन० सी० ई० आर० टी०, माध्यमिक शिक्षा के केंद्रीय बोर्ड, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, यूनेस्को तथा यू एस ई एफ आई से सक्रिय रूप से संबद्ध है।

प्रकाशक

प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर 25 अनुलिखित रिपोर्टों के अतिरिक्त रिपोर्ट वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए :—

1. आसाम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल में प्रारंभिक शिक्षा का प्रशासन।

2. बिहार राज्य से संबंधित प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन का हिन्दी अनुवाद।

3. वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) 1980-81।

4. इ पी ए बुलेटिन क्वार्टरली खंड 4 नं० 2 (जुलाई 1981), खंड 4 नं० 3 (अक्तूबर, 1971) तथा खंड 4 तथा खंड 5 नं० 1 (जनवरी तथा अप्रैल, 1982)।

कठिनाइयां

संकाय के लिए नियुक्तियां करने में संस्थान विशेष कठिनाई का अनुभव कर रहा है। संकाय सदस्यों के पदों में परिवर्तन और उनके वेतन मानों में परिशोधन पर डा० मेलकोत्म एस० अदिशेय्या शिक्षा समिति की सिफारिशों पर संकाय सदस्यों के लिए यू जी सी के वेतनमानों की स्वीकृति के लिए संस्थान द्वारा भारत सरकार तक पहुंच की गयी। यू जी सी के वेतनमानों को लागू करने तथा स्टाफ क्वाटरों के निर्माण को पूरा कर लेने पर आशा की जाती है कि संस्थान उच्च प्रतिभाशाली संकाय सदस्यों को नियुक्त कर सकेगा। और उन्हें आवास प्रदान कर सकेगा। संस्थान अपने क्रियाकलापों के विस्तार के कारण कार्यालय स्थान की बहुत कमी अनुभव कर रहा है। यद्यपि अधिकारियों और स्टाफ़ को छोटे कमरों में भेज दिया गया है और वर्तमान कमरों को विभाजित कर दिया गया है फिर भी संस्थान अपने स्टाफ को उचित निवास स्थान प्रदान करने में अत्यधिक कठिनाई अनुभव कर रहा है।

इस रिपोर्ट को चार भागों में विभाजित किया गया। भाग 1, नीति आधार के उद्देश्यों और अंगों पर प्रकाश डालता है, भाग 2, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है, भाग 3, राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सलाहकारी, परामर्शकारी तथा सहायक सेवाओं का विवरण प्रस्तुत करता है तथा भाग 4, प्रशासन और वित्त से संबंधित है।

भाग—1

नीति आधार के उद्देश्य और अंग

शैक्षिक नियोजन और प्रशासन में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्शता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान, जो पहले शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों का राष्ट्रीय स्टाफ कालिज के नाम से जाना जाता था, का पंजीकरण 31 मई, 1979 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत किया गया। संस्थान शैक्षिक नियोजन और प्रशासन सेवाओं तथा अन्य कार्यक्रमों में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार पर विचारों और सूचनाओं के समाशोधन केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

उद्देश्य

संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के वरिष्ठ शैक्षिक अधिकारियों के लिए सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षणों, सम्मेलनों कार्यशालाओं, बैठकों, संगोष्ठियों तथा ब्रीफिंग सत्रों का आयोजन करना;

(ख) अध्यापक प्रशिक्षकों तथा शैक्षिक योजना तथा प्रशासन से संबंधित विश्वविद्यालयों तथा कालेज के प्रशासकों के लिए अभिविन्यास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना;

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में नीति-निर्माण के कार्य से संबद्ध विधायकों सहित अन्य सभी शीर्षस्थ व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा चर्चा-समूहों का आयोजन करना;

(घ) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के विभिन्न पक्षों में अनुसंधान कार्य करना, तत्संबंधी अनुसंधान में सहायता करना, उसे प्रोत्साहित करना तथा इस क्षेत्र

में हो रहे अनुसधान कार्य को समन्वित करना। साथ ही भारत के विभिन्ना राज्यों तथा विश्व के अन्य देशों की योजना तकनीकों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना;

(ङ) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के काम में लगे विभिन्न अभिकरणों, संस्थाओं तथा कार्मिकों का शैक्षिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से मार्गदर्शन करना;

(च) आग्रह किए जाने पर राज्य सरकारों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श-सेवा प्रदान करना;

(छ) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सेवा तथा तत्संबंधी अन्य कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार संबंधी सभी प्रकार के विचारों तथा सूचनाओं के समाशोधन केन्द्र के रूप में काम करना;

(ज) उक्त उद्देश्यों की ही पूर्ति की दिशा में लेखों, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के लेखन, मुद्रण तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना, विशेषकर एक शैक्षिक योजना तथा प्रशासन-पत्रिका का प्रकाशन करना;

(झ) उक्त उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रबंध तथा प्रशासन संस्थाओं और भारत तथा विदेश स्थित अन्य सहबद्ध संस्थाओं सहित अन्य अभिकरणों, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ सहयोग करना;

(ञ) संस्थान के उक्त उद्देश्यों में संवर्धन करने की दृष्टि से अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियां तथा शैक्षणिक पुरस्कार देना;

(ट) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले गणमान्य शिक्षाविदों को सम्मानार्थ अध्येतावृत्तियां प्रदान करना;

(ठ) अन्य देशों, विशेष कर एशियाई प्रदेश के देशों को, आग्रह किए जाने पर शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना तथा उक्त प्रकार के कार्यक्रमों में उनके साथ सहयोग करना।

परिषद्

संस्थान का शिखर-निकाय परिषद् है जिसका प्रधान 'अध्यक्ष' होता है, जिसे भारत सरकार नामित करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान का निदेशक इसका उपाध्यक्ष होता है। परिषद् के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं :

—अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

—भारत सरकार के 4 सचिव (शिक्षा, वित्त, योजना आयोग और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग।

—निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ।

— 6 शिक्षा सचिव (5 राज्य तथा एक संघ शासित क्षेत्र से)

— 6 शिक्षा-निदेशक (5 राज्यों तथा एक संघशासित क्षेत्र से)

— 6 गणमान्य शिक्षाविद्।

—कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान।

—राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संकाय का एक सदस्य।

परिषद् के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 में दी गई है। परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। प्रोफेसर डी० टी० लकदवाला परिषद् के अध्यक्ष है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद् की एक बैठक 24 दिसंबर, 1981 को आयोजित की गई थी।

कार्यकारिणी समिति

कार्यकारिणी समिति, जिसका अध्यक्ष संस्थान का निदेशक होता है, संस्थान के प्रशासन की देखरेख करती है। समिति अपना कार्य वित्त-समिति तथा कार्यक्रम सलाहकार समिति के माध्यम से करती है। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-2 में दी गई है।

वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की तीन बैठकें 2 मई, 1981, 3 सितम्बर, 1981 तथा 8 जनवरी, 1982 को आयोजित की गई।

वित्तीय समिति

अध्यक्ष, संस्थान के निदेशक की पदेन अध्यक्षता के अधीन एक वित्त समिति की नियुक्ति करता है। यह समिति लेखाओं तथा बजट प्रावकलनों की जांच करती है तथा नए व्ययों के बारे में रखे गए प्रस्वाओं के संबंध में कार्यकारिणी समिति को अपनी सिफारिशें पेश करती है। वित्त-समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-2 में दी गई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्त समिति की तीन बैठकें 1 मई 1981, 3 सितम्बर, 1981 तथा 8 जनवरी, 1982 को आयोजित की गई।

कार्यक्रम सलाहकार समिति

प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के संबंध में संस्तुति करने तथा सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को समन्वित करने और संस्थान के कार्य के शैक्षणिक पक्ष की जाँच करने के लिए कार्यकारिणी समिति ने नियम 29 के अधीन 1 अक्तूबर, 1981 से एक कार्यक्रम सलाहकार समिति का गठन किया। संस्थान का रजिस्ट्रार इस समिति के सचिव का कार्य करता है। समिति ने 5 जनवरी, 1982 को अपनी बैठक आयोजित की । पुनर्गठित सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-4 में दी गई है।

भाग—2

कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान के क्रियाकलापों में पर्याप्त वृद्धि हुई। अपने सीमित साधनों के होते हुए संस्थान ने, केंद्रीय तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और एशिया तथा ओशीनिया में शिक्षा के लिए युनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से शैक्षिक योजना तथा प्रबंध के क्षेत्र में नई-नई संकल्पनाओं तथा तकनीकों का प्रसार किया, अनेक प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का आयोजन किया तथा अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए परामर्श सेवाओं की व्यवस्था की :

(क) 1980-81 के दौरान चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

आलोच्य वर्ष के दौरान चलाए गए 34 कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) सामाजिक शिक्षा प्रबंध	:	7 कार्यक्रम
(2) प्रौढ़ शिक्षा	:	4 कार्यक्रम
(3) उच्च शिक्षा प्रबन्ध	:	5 कार्यक्रम
(4) विशेष	:	8 कार्यक्रम
(5) अन्तर्राष्ट्रीय	:	4 कार्यक्रम
(6) पत्राचार्य पाठ्यक्रम	:	1 कार्यक्रम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चलाए गए कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

स्कूल शिक्षा प्रबंध

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	तारीख और अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
1	2	3	4
1.	दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।	अप्रैल 20-25, 1981 (6 दिन)	29
2.	वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों नई दिल्ली के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम।	मई 25-जून 12 1981 (19 दिन)	12
3.	वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों, दिल्ली के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम।	अगस्त 3-21, 1981 (19 दिन)	18
4.	परमाणु ऊर्जा स्कूलों के प्रधानाचार्यों, उप प्रधानाचार्यों आदि के लिए स्कूल प्रबधन पर कार्यशाला। (परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी, बंबई के सहयोग से)।	नवम्बर 2-7, 1981 (6 दिन)	19
5.	केन्द्रिय विद्यालय के प्रधानाचार्यों तथा केंद्रीत तिबतन स्कूलों के सहाचर्यों तथा प्रधानाचार्यों के लिए अभि-विन्यास कार्यक्रम।	दिसम्बर 31, 1981— जनवरी 9, 1982 (10 दिन)	32
6.	पांडिचेरी में स्कूलों के मुख्य अध्या-पकों तथा निरीक्षण अधिकारियों के लिए स्कूल प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम।	फरवरी 8-13, 1982 (6 दिन)	37

1	2	3	4
7.	हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए कार्मिक तथा वित्तीय प्रबंध से संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम।	फरवरी 23-27, 1982 (5 दिन)	8
	कुल	71 दिन	165

कार्यक्रम व्यक्ति दिन : $165 \times 71 = 11,715$

2. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

8.	राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।	अप्रैल 6-11, 1981 (6 दिन)	24
9.	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रथम पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।	जून 22-27, 1981 (5 दिन)	20
10.	जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से)।	नवम्बर, 23-दिसंबर 5, 1981 (13 दिन)	24
11.	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।	जनवरी 18-23, 1982 (6 दिन)	13
	कुल	31	81

कार्यक्रम व्यक्ति दिन : $81 \times 31 = 2,511$

1	2	3	4
		3. उच्च शिक्षा प्रबंध	
12.	शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम, नई दिल्ली (हरियाणा के कालिज प्रधानाचार्यों के लिए)	मई 25-जून 6, 1981 (13 दिन)	24
13.	कालिज के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित पहला अभिविन्यास कार्यक्रम।	नवम्बर 2-21, 1981 (20 दिन)	33
14.	महिला कालिजों के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम।	नवम्बर 30— दिसम्बर 19, 1981 (20 दिन)	24
15.	कालिज प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम।	फरवरी 8-27, 1982 (20 दिन)	33
16.	यू० एस० ई० एफ० आई० बी० की विश्वविद्यालय प्रशासक परियोजना के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका जाने वाले कालिज-प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।	मार्च 29— अप्रैल 1, 1982 (3 दिन)	
	कुल	76	119

कार्यक्रम व्यक्ति दिन : $119 \times 76 = 9,044$

1	2	3	4
	4. विशेष कार्यक्रम		
17.	हरियाणा के लिए शैक्षिक मानकों पर कार्यशाला।	अप्रैल 2-4, 1981 (3 दिन)	33
18.	जम्मू और कश्मीर के जिला तथा तहसील शैक्षिक योजना अधिकारियों के लिए दूसरी प्रशिक्षण संगोष्ठी।	अप्रैल 13-25, 1981 (13 दिन)	29
19.	आश्रम स्कूलों के अध्ययन के डिजाइन से संबंधित विशेषज्ञ संगोष्ठी।	अगस्त 11-12, 1981 (2 दिन)	11
20.	जनसंख्या शिक्षा में प्रशिक्षण से संबंधित विशेषज्ञ संगोष्ठी।	सितंबर 12, 1981 (1 दिन)	12
21.	गैर-मौद्रिक आगमों पर बल देते हुए शैक्षिक विकास के लिए संसाधनों के उचित उपयोग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।	सितंबर 22-25, 1981 (4 दिन)	42
22.	लम्बे समय के शैक्षिक नियोजन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।	दिसम्बर 21-23, 1981 (3 दिन)	19
23.	राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य कार्मिकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।	फरवरी 1-4, 1982 (4 दिन)	25
24.	शिक्षा सचिवों/डी० पी० आई० (स्कूलों) के लिए जनसंख्या शिक्षा में अखिल भारतीय संगोष्ठी।	फरवरी 18-19, 1982 (2 दिन)	72
	कुल	32	243

कार्यक्रम व्यक्ति दिन : $243 \times 32 = 7,776$

1	2	3	4
		5. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	
25.	संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या निदेशकों के लिए भारतीय इतिहास तथा संस्कृति पर कार्यशाला ।	जून 30 जुलाई 16 1981 (17 दिन)	15
26.	श्री मोहम्मद आरनीनल इस्लाम, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय बंगला देश की अध्ययन दौरा ।	अगस्त 5-8, 1981 (4 दिन)	1
27.	यूनेस्को अध्येता श्री फजलुर रहमान खान, बंगला देश के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।	सितम्बर 21— अक्तूबर 17, 1981 (27 दिन)	1
28.	लम्बे समय के शैक्षिक नियोजन पर क्षेत्रीय कार्यशाला ।	जनवरी 12-25, 1982 (14 दिन)	21
		कुल 62	38

कार्यक्रम व्यक्ति दिन : $38 \times 62 = 2,356$

4. पत्राचार पाठ्यक्रम

29.	जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन में पत्राचार तथा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।	अगस्त 1981— मार्च 1982 (240 दिन)	18

कार्यक्रम व्यक्ति दिन ; $18 \times 240 = 4,320$

आलोच्य वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों में 664 व्यक्तियों ने भाग लिया जिनमें शिक्षा-सचिव, शिक्षा निदेशक, राज्यीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के निदेशक, कालिजों के आचार्य और प्रधान आचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा तथा तहसील शैक्षिक योजना अधिकारी, राज्य तथा केन्द्र स्तरों के तथा एन०सी०ई०आर०टी० के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी सम्मिलित हैं।

भाग लेने वालों तथा विविध कोटि के कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम व्यक्ति दिवस का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कोटि	भाग लेने वालों की संख्या	कार्यक्रम दिवस संख्या	कार्यक्रम प्रतिशत
1	2	3	4
1. स्कूल शिक्षा प्रबंध	165 (25 प्रतिशत)	71	11715 (31 प्रतिशत)
2, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	81 (12 प्रतिशत)	31	2511 (7 प्रतिशत)
3. उच्च शिक्षा का प्रबंध	119 (18 प्रतिशत)	76	9044 (24 प्रतिशत)
4. विशेष कार्यक्रम	243 (36 प्रतिशत)	32	7726 (21 प्रतिशत)
5. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	38 (6 प्रतिशत)	62	2356 (6 प्रतिशत)
6. पत्राचार पाठ्यक्रम	18 (3 प्रतिशत)	240	4320 (11 प्रतिशत)
कुल	664	512	37,672

विशेष कार्यक्रमों को छोड़कर स्कूल शिक्षा प्रबंध कार्यक्रम में सबसे अधिक भाग लेने वाले को यथा 165 व्यक्ति जो वर्ष के दौरान भाग लेने वालों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत और कार्यक्रम व्यक्ति दिवसों के 31 प्रतिशत थे। इसके बाद उच्च शिक्षा कार्यक्रमों का नम्बर था जिसमें 119 व्यक्तियों ने भाग लिया, जो भाग लेने वाले कुल व्यक्तियों के 18 प्रतिशत तथा कार्यक्रम व्यक्ति दिवसों के 24 प्रतिशत थे।

सबसे अधिक भाग लेने वाले व्यक्ति जिनकी संख्या 57 थी (14 प्रतिशत) हरियाणा से थे, इसके पश्चात् महाराष्ट्र से 44 (11 प्रतिशत) तथा जम्मू व कश्मीर से 42 (10 प्रतिशत) व्यक्तियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं से भाग लेने वालों की संख्या 106 थी जो भाग लेने वालों की कुल संख्या की 16 प्रतिशत थी। भाग लेने वालों में स्त्रियों की संख्या 100 थी जो कुल संख्या की 15 प्रतिशत है। भाग लेने वालों में पी० एच-डी० प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 102 थी जो भाग लेने वालों की कुल संख्या की 15 प्रतिशत थी।

अफगानिस्तान, बंगला देश, चीन, नैपाल, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलिपीन्स, श्रीलंका तथा थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका से 38 व्यक्तियों ने, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों में भाग लिया।

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

कार्यक्रम मूल्यांकन

प्रत्येक कार्यक्रम में, उसके मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए गठित संचालन समिति संगामी मूल्यांकन करती रहती है। इसमें संकाय के सदस्य तथा भाग लेने वालों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। वे यह देखते हैं कि दिन-प्रतिदिन के अनुभव को देखते हुए उक्त कार्यक्रमों में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए।

कार्योत्तर मूल्यांकन के लिए, भाग लेने वालों को पहले ही दिन प्रोफार्मा बांट दिए जाते हैं ताकि वे शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय उनमें भर कर सत्र के अंतिम दिन से एक दिन पूर्व समन्वयक को लौटा सकें। मूल्यांकन को सहज एवं स्वाभाविक बनाने के कारण भाग लेने वालों से उस पर अपने हस्ताक्षर करने का आग्रह नहीं किया जाता। अंतिम दिन मूल्यांकन सत्र का आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता निदेशक महोदय करते हैं। इस सत्र में भाग लेने वाले सभी लोग शैक्षिक तथा संगठनात्मक सभी मामलों पर निःसंकोच अपने विचार व्यक्त करते हैं।

भविष्य के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम तैयार करते समय संस्थान सहभागियों द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि को ध्यान में रखते हैं। परिणामतः इस वर्ष आयोजित किए गए अनेक पाठ्यक्रमों में पहले की अपेक्षा व्यावहारिक अभ्यास पर अधिक बल दिया गया। संस्थाओं के अध्यक्षों के लिए आयोजित किए जाने वाले अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए नीति-निर्माण, मानव संबंधों आदि जैसे प्रशासनिक पक्षों पर विशेष रूप से कैस-अध्ययन तैयार किए गए। उपर्युक्त क्षेत्रीय दौरों की व्यवस्था भी की गई। हाल ही में हुए विकासों को तथा सहभागियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों की बिषय-वस्तु को समृद्ध बना दिया गया है।

सहभागियों के मूल्यांकन से व्यापक रूप से इस बात का पता चलता है कि उन्हें ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी प्रतीत हुए। शिक्षा संबंधी वास्तविक स्थितियों में उक्त प्रशिक्षण का क्या प्रभाव पड़ा, इस बात का मूल्यांकन करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

ख. अनुसंधान और अध्ययन

संस्थान की परिप्रेक्ष्य योजना में संस्थान के क्रियाकलापों के अनुसंधान भाग पर तथा अनुसंधान को प्रशिक्षण से संबद्ध करने पर अत्यधिक बल दिया गया है। वर्ष के दौरान संस्थान ने पहले से लिए अनुसंधान अध्ययन को पूरा करने के अतिरिक्त नए अनुसंधान अध्ययनों को प्रारंभ किया। संस्थान सारा प्रारंभ किए गए अनुसंधान अध्ययन नीचे दिए गए हैं।

1. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों में सर्वव्यापीकरण के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन का अध्ययन

संस्थान ने शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नौ राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन से संबंधित आनुभविक अध्ययन पूरा कर लिया है। देश के अनामांकित बच्चों में से लगभग 74 प्रतिशत बच्चे इन राज्यों में रहते हैं। आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं। असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल की रिपोर्टें वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई।

भारत के शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों में सर्वव्यापीकरण के कार्यक्रम के संबंध में प्रारंभ शिक्षा के प्रशासन के अध्ययनों के मुख्य निष्कर्षों तथा सुझावों की एक अखिल भारतीय समेकित रिपोर्ट जुलाई, 1981 में नीपा द्वारा प्रकाशित की गई।

दिए गए सुझावों का सबंध निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों से है।

1. स्कूलों की व्यवस्था।
2. सुविधाओं की व्यवस्था—भवन, फर्नीचर तथा उपस्कर।
3. जनगणना और नामांकन।
4. स्कूल में उपस्थित रहना और स्कूल बीच में छोड़ देना।
5. अध्यापकों की व्यवस्था और सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण।
6. निरीक्षण और पर्यवेक्षण।
7. गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र।
8. प्रोत्साहन (प्रेरक)।
9. स्थानीय निकायों की भूमिका।
10. ग्राम शिक्षा समितियां।
11. स्कूल प्रांगण।
12. अध्यापक संगठन।
13. ग्राम, ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन।

2. हरियाणा के लिए शिक्षा के मानकों का विकास करने से संबंधित अध्ययन

हरियाणा सरकार के आग्रह पर संस्थान ने वर्ष 1979 में स्कूल खोले जाने तथा उस कोटि का उनयन किए जाने के लिए अपेक्षित स्कूल स्तर पर शैक्षिक सविधाओं का विस्तार करने तथा उन्हें बनाए रखने के बारे में मानकों का विकास करने से संबंधित अध्ययन का कार्य हाथ में लिया था। संस्थान ने यह आग्रह भी किया था कि यह शिक्षण तथा शिक्षणेतर स्टाफ की व्यवस्था, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, उपस्करों तथा फर्नीचर की व्यवस्था, स्कूल भवन तथा शिक्षा स्टाफ की नियुक्तियों और स्थानांतरण के बारे में भी मानक तैयार करें।

3. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक योजना, मानिटरिंग तथा सांख्यिकी की संगठनात्मक व्यवस्था तथा पद्धति का अध्ययन।

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के आग्रह पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान ने देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का शैक्षिक योजना, सांख्यिकी तथा मॉनिटरिंग की व्यवस्था के अध्ययन का कार्य 1980-81 में हाथ में लिया। 24 राज्यों

तथा संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हो गई है और जम्मू और कश्मीर तथा महाराष्ट्र के रिपोर्ट प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है और उन्हें टीका-टिप्पणी के लिए प्रचालित कर दिया गगा है ।

4. नीपा में जनसंख्या शिक्षा क्रियाकलाप

इस देश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या को हल करने में जनसंख्या शिक्षा के महत्व को मान्यता देते हुए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने यूनेस्को को जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की एक परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य देश में

विकास के लिए किए गए प्रयत्नों में शिक्षा की संभाव्य भूमिका को निभाने के लिए देश मे सम्पूर्ण शैक्षिक पद्धति को तीव्र करना है । यह सुझाव दिया गया कि इस परियोजना के एक भाग के रूप में नीपा को अपने प्रशिक्षण क्रियाकलापों में जनसंख्या शिक्षा सम्मिलित करने के लिए उपबंधित किया जा सकता है । तदनुसार संस्थान द्वारा 'नीपा में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम' शीर्षक पर एक दो-वर्षीय परियोजना तैयार की गई और शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उसका अनुमोदन किया गया है ।

12 सितंबर 1981 को जनसंख्या पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं और अन्य संगठनों ने भाग लिया । इसके पश्चात् 'जनसंख्या और विकास' विषय पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी 18-19 फरवरी, 1982 को आयोजित की गई जिसमें शिक्षा सचिवों, शिक्षा निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया ।

5. गुड़गांव में शिक्षा की लागत

संस्थान ने संस्थागत लागत-शिक्षा की वैकल्पिक विधियों तथा विषम स्तरीय और समस्तरीय अनुबंधता की संभावना पर फोकस करते हुए गुड़गाँव के निकटवर्ती जिले में क्षेत्रीय अध्ययन प्रारंभ किया । इस अध्ययन से संसाधनों के कुशलतापूर्वक उपयोग करने के उपायों को खोज निकालने, शैक्षिक सेवायें प्राप्त करवाने के लिए अनुमानित संसाधनों की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करवाने तथा संस्थाओं का इष्टतम आकार निर्धारित करने में सहायता प्राप्त होगी । इन तथ्यों का स्वाभाविक रूप से शैक्षिक नीति पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा । वर्ष 1979-80 के दौरान 90 से 100 संस्थाओं के अध्ययन से विविध स्तरों पर शिक्षा की संस्थागत लागत का पता चलता है, विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र यथा 2-3 खंड़ों के संदर्भ में ।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 2.20 लाख रु० है।

6. और 7. आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का औद्योगिक प्रशिक्षण

गृह मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित उपरोक्त अध्ययन शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) को संस्थान पर शैक्षिक नीतियों, नियोजन, प्रबंध और मूल्यांकन में अध्ययन के लिए सहायता योजना, के अंतर्गत सौंपा गया। उपरोक्त दोनों अध्ययनों के संचालन के लिए शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ने प्रत्येक योजना के लिए 50,000 रु० की राशि संस्वीकृत की है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश तथा बिहार आदि पाँच राज्यों की समस्याओं का मौके पर अध्ययन करने के पश्चात् दोनों अध्ययन को सितम्बर, 1981 को प्रारम्भ किया गया। आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र का कार्य पूरा हो चुका है और मार्च, 1982 में उनकी अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा चुकी थी।

8. शैक्षिक रूप से विकसित तथा पिछड़े हुए राज्यों में निरीक्षण, अभ्यासों तथा प्रपत्र का अध्ययन

'शैक्षिक नीतियों, नियोजन प्रबंधन और मूल्यांकन में अध्ययनों के लिए सहायता योजना' के अंतर्गत शैक्षिक रूप से विकसित और पिछड़े हुए कुछ राज्यों में निरीक्षण पद्धति और अभ्यास तथा प्रपत्र पर एक नमूना अध्ययन शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने संस्थान के सुपुर्द किया। इस अध्ययन को हाथ में लेने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 50,000 रु० स्वीकृत किए।

आंध्रप्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों को नमूना राज्यों के लिए चुना गया। कुछ जिलों का चयन पूरा हो गया है और राज्यों की परामर्शता से कुछ खंड़ों और संस्थाओं की पहचान की गई।

9. विश्वविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन (क्षेत्रीय मूल्यांकन) का अध्ययन

विविध विश्वविद्यालय में प्रचलित आंतरिक मूल्यांकन (सत्रीय मूल्यांकन) की जांच करने की दृष्टि से तथा कालिजों में सत्रीय मूल्यांकन का एक कार्यकारी पैटर्न बनाने के लिए कालिज के प्रधानाचार्यों को आनुभविक आधार सामग्री प्राप्त करवाने के लिए, डा० (श्रीमती) राधा रानी शर्मा, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी द्वारा उपरोक्त अध्ययन प्रारंभ किया गया। इस अध्ययन की रिपोर्ट उच्च शिक्षा की पत्रिका में प्रकाशन हेतु भेजी जा चुकी है।

10. शैक्षिक प्रशासकों के व्यक्तित्व विशेषताओं का अध्ययन

डा० (श्रीमती) राधा रानी शर्मा, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी ने इस अध्ययन को प्रारंभ किया। इस अध्ययन का उद्देश्य शैक्षिक प्रशासकों के बीच अपेक्षित व्यक्तित्व विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए एक परीक्षण का निर्माण और उसका मानकीकरण है। इस अध्ययन में प्रभावी शैक्षिक प्रशासकों के व्यक्तित्व परिच्छेदिका का अध्ययन भी प्रस्तावित है। अध्ययन प्रगति पर है।

11. तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक स्कूलों के मुख्य अध्यापकों पर अध्ययन

भारत समेत 14 अन्य राष्ट्रों में माध्यमिक स्कूल के मुख्य अध्यापकों की विशेषताओं की जांच करने के लिए शिक्षा कालिज, आयोवा (Iowa) विश्वविद्यालय ने 'तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक स्कूल मुख्य अध्यापक' शीर्षक पर एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की। भारत की ओर से डा० एन० एम० भागिया, अध्येता ने राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोगी के रूप में इस अध्ययन में भाग लिया। अध्ययन प्रगति पर है।

12. अच्छे जीवन स्तर के लिए कार्य की आकांक्षा (AABQOL)

यह अध्ययन प्रो० रामकृष्ण मुखर्जी को यूनेस्को, पेरिस द्वारा सौंपा गया। संस्थान इस अध्ययन के संचालन में प्रो० मुखर्जी को सहयोग दे रहा है। यह अध्ययन शहरी और ग्रामीण व्यवस्था में अच्छे जीवन स्तर के लिए आकांक्षा और कार्य को मापने के लिए एक प्रणालीबद्ध जांच है। दिल्ली और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जांच के क्षेत्र हैं। क्षेत्रीय कार्य में डेढ़ महीना लग जाने की आशा है।

13. शैक्षिक व्यय—एक क्षेत्रीय विश्लेषण

इस परियोजना पर कार्य यूनेस्को सांख्यिकी कार्यालय, पेरिस से एक संविदा के अंतर्गत किया गया। इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं: (1) समग्र रूप से राष्ट्रीय अग्रताओं के संबंध में शैक्षिक वित्त के तंत्र और समस्याओं की जांच और अन्य आर्थिक क्षेत्रों से इसका संबंध, तथा (2) पिछले दस वर्षों में शैक्षिक व्यय के स्थानिक तथा क्षेत्रीय प्रतिरूपों का विश्लेषण। आंकड़े एकत्रित करने तथा उनके सारणीकरण का कार्य प्रगति पर है।

14. **भारत क दो राज्यों में शैक्षिक नियोजन और ईक्विटी योजना पर तुलनात्मक नीति अध्ययन**

इस परियोजना पर कार्य यूनेस्को से एक संविदा के अंतर्गत किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य शैक्षिक वित्तीयन का अध्ययन करना और ईक्विटी के लिए इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करना है। प्रयोजनबद्ध आधार पर दो राज्यों यथा केरला और हरियाणा को इस अध्ययन के लिए चुना गया है। आंकड़े एकत्रित करने तथा उनके सारणीकरण का कार्य प्रगति पर है।

15. **ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा के (घटकों) और सम्बन्धों के लिए कुछ प्रयोगों का तुलनात्मक अध्ययन : नियोजन और प्रशासन तंत्र**

इस परियोजना के लिए निधि की व्यवस्था ए सी इ आई डी, यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक द्वारा की गई है। ग्रामीण विकास योजना तथा प्रशासनिक तंत्र के लिए शिक्षा के घटकों और संबंधों पर किए गए कुछ प्रयोगों का यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि समेकित ग्रामीण विकास में एक तत्व के रूप में शिक्षा को किस प्रकार प्रभावशाली तरीके से तथा न्यूनतम लागत पर प्रारंभ किया जा सकता है। इस संबंध में सूचना विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त की जा रही है।

16. **खंड तथा संस्था स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की प्रणालियां और समस्यायें**

इस परियोजना पर कार्य यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक से एक संविदा के अंतर्गत किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य इस प्रकार है: (i) यह पता लगाना कि भारत में ब्लाक तथा संस्था स्तर पर शिक्षा का प्रशासन किस प्रकार किया जाता है; तथा (ii) शिक्षा के प्रशासन में ब्लाक शिक्षा अधिकारियों तथा स्कूलों के मुख्य अध्यापकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में प्रश्नावली/निरीक्षण सूची, साक्षात्कार सूची को विकसित किया गया है।

17. **पुनर्विचार विकास**

यह अध्ययन प्रो० एस० सी० दुबे, राष्ट्रीय अध्येता द्वारा आई सी एस एस आर परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यह निर्धनता पर एक अंतःशास्त्रीय अध्ययन है जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका से उदाहरण लिए गए हैं। इस सुविचारित व्यापक कार्य में **एशियन ड्रामा** प्रस्तुत किया गया है। अर्थात् एशियाई क्षेत्र का ही अध्ययन किया गवा है परन्तु तीसरे विश्व के परिपेक्ष्य में और

इसमें अधिकारी तंत्र राजनीतिक प्रक्रियाओं और शिक्षा का गहन अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाएगा।

18. भारतीय राज्यों में उच्च शिक्षा के वित्तीयन पर गहन अध्ययन

यह अध्ययन डा० जे० एल० आजाद, वरिष्ठ अध्येता द्वारा आई सी एस आर परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस अध्ययन में क्षेत्रीय आधार पर चुने गए चार राज्यों में उच्च शिक्षा के वित्तीयन की नीतियों, प्रक्रियाओं तथा प्रतिरूपों की तर्कपूर्ण जांच किए जाने का प्रस्ताव है। कालिजों के प्रधानाचार्यों तथा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों को भी विस्तृत आंकड़े-सूचियां/प्रश्नावलियां जारी की गई हैं।

(ग) अंतर्राज्योय वीक्षण

महाराष्ट्र में संपर्क आधारित कार्यक्रम द्वारा स्कूल परिवर्धन के अध्ययन के लिए नीपा द्वारा 8 से 14 फरवरी, 1982 को राज्य में एक अंतर्राज्यीय वीक्षण किया गया।

अंतर्राज्यीय अध्ययन में छह राज्यों ने भाग लिया। इनमें निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं : राजस्थान, बिहार, आंध्रप्रदेश, केरला, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री एस० सत्यम् तथा एन सी ई आर टी के संयुक्त निदेशक डा० टी० एन० धर एक दिन के लिए दल के साथ थे। प्रो० डी० ए० दामोलकर, पूना विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति, जो वर्तमान में भारतीय शिक्षा संस्थान, पूना में आचार्य हैं, सभी दिन दल के साथ थे। महाराष्ट्र राज्य से आठ अन्य अधिकारी थे जिनमें, अध्यक्ष, नगर निगम शिक्षा समिति, बम्बई, शिक्षा अधिकारी बम्बई नगर निगम, बम्बई तथा कुछ मुख्य अध्यापक जो प्रेक्षकों के रूप में कुछ दिनों के लिए दल में सम्मिलत हुए थे।

नीपा का प्रतिनिधित्व डा० आर० पी० सिंहल, परामर्शदाता तथा डा० (श्रीमती) राधा रानी शर्मा, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी ने किया।

दल ने कुल मिला कर महाराष्ट्र के 9 जिलों तथा 25 खंडों का वीक्षण किया और इस प्रकार उन्होंने कुल जिलों का तीसरा भाग पूरा कर लिया। लगभग 35 स्कूल कम्प्लेक्सों के 100 से अधिक स्कूलों का वीक्षण दल द्वारा किया गया।

दल, संपर्क आधारित कार्यक्रम के प्रति व्याप्त जागरूकता तथा उत्साह जो लोगों

में तथा शैक्षिक कार्यकर्ताओं में स्पष्ट दिखाई देते थे, से अत्यधिक प्रभावित हुआ। समग्र रूप से कार्यक्रम ऐच्छिक और गैर-मौद्रिक प्रकार का है। इस कार्यक्रम ने संबंधित सभी व्यक्तियों में वांछित अभिप्रेरणा जागरूक की है।

यह कार्यक्रम श्री वी० चिपलंकर, शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र के नेतृत्व में प्रयोगात्मक आधार पर चारहोली कम्प्लेक्स में एक संचालक परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया। श्री चिपलंकर ने स्वयं ही इस कम्प्लेक्स को 1977-78 में अपने अधिकार में लिया था। तब से यह कार्यक्रम सारे महाराष्ट्र में प्रचलित हो गया है और अब राज्य में लगभग 1200 स्कूल कम्पलैक्स हैं। शिक्षा विस्तार अधिकारी की कोटि के प्रत्येक अधिकारी ने एक-एक स्कूल कम्पलैक्स को अपने अधिकार में ले लिया है।

दल ने यह पाया कि संपर्क-आधारित कार्यक्रम ने महाराष्ट्र में स्कूल संवर्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्कूलों का पृथक्करण टूट चुका है, विद्यार्थियों का नामांकन और उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ है, स्कूल में उपस्थित रहने की दर में तथा स्थानांतरण में संवृद्धि हुई है और पढ़ाने तथा सीखने की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। स्कूल, संगठन तथा प्रबंध स्कूल की आवश्यकताओं के प्रति अब अधिक संवेदनशील हैं और नकद और वस्तु रूप में समुदाय से प्राप्त सहायता से संसाधनों की उपयोगिता में वृद्धि हुई है। एस एस सी परीक्षाओं के परिणामों से भी संवृद्धि का पता चलता हैं।

स्कूलों के श्रेणीकरण के लिए उपस्करों (साधनों) का भी निर्माण किया गया है क्योंकि संपर्क आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्कूल कम्पलैक्सों का मुख्य आधार ऐसे स्कूलों को पहचानना और उनमें सुधार लाना है जिनका निष्पादन निम्न कोटि का है। प्रभावी मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण के लिए अधिकारियों, मुख्य अध्यापकों और अध्यापकों के मूल्यांकन के लिए भी उपस्कर बनाए गए हैं।

व्यापक रूप से इस कार्यक्रम ने स्पष्टतः स्कूल संवर्धन के लिए एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया और इसे स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक सफल नवाचारी कार्यक्रम माना जा सकता है।

(घ) कार्यक्रम नियोजन तथा क्रियान्वयन के लिए परामर्शकारी बैठकें

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले नए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम के विषय में विस्तार और सक्रियात्मक योजनाओं पर चर्चा करने के लिए वर्ष 1981 के दौरान समय समय पर अनेक परामर्शकारी बैठकों की व्यवस्था की गई। इन

बैठकों में, संस्थान के संकाय के अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों और भारत के सुविख्यात अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठनों ने भी भाग लिया। वर्ष के दौरान की गई बैठकें इस प्रकार हैं :—

(i) लम्बे समय की शिक्षा योजना में यूनस्को द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए व्यावसायिक तैयारी करने के लिए बुलायी गई बैठक : जून 8, 1981 ।

(ii) गैर-मौद्रिक आगत पर बल देते हुए शैक्षिक विकास के लिए संसाधनों के उचित उपयोग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए बुलायी गई बैठक।

(iii) 'आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन' तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों को तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण सुविधायें : अगस्त 11 12, 1981.

(iv) जनसंख्या शिक्षा के लिए व्यापक विषय वस्तुओं, पैरामीटरों तथा संप्रत्यात्मक निर्देश आधार पर चर्चा के लिए बैठक : 12 सितम्बर, 1981.

(v) विभिन्न प्रकार के समझौतों में शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए भवन और स्थान मानकों पर चर्चा करने के लिए बैठक : 17 सितम्बर, 1981.

(vi) 'गुड़गांव जिले में शिक्षा प्राप्त करवाने की लागत' शीर्षक पर अध्ययन के लिए बैठक : 30 सितम्बर, 1981 तथा 29 अक्तूबर, 1981.

उपरोक्त बैठकों में हुई चर्चाओं के परिणामस्वरूप विकसित व्यापक विषय तथा कार्यप्रणालियाँ विकसित कार्यक्रमों में परिलक्षित होती हैं और उनका व्यापक ब्यौरा कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप समीक्षा में तथा अनुबंध-I में दिया गया है। शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए भवन और स्थान मानकों पर अध्ययन अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। परामर्शकारी समिति की बैठक में उपरोक्त अध्ययन पर क्रिया योजना के अंतिम रूप में तथापि निम्न-लिखित विषय भी सम्मिलित हैं—

विभिन्न नगर विकास प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली वर्तमान नीतियों तथा अभ्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, शैक्षिक संस्थाओं की स्थान संबंधी आवश्यकताओं

का मूल्यांकन, भवनों और स्थान मानकों का सुझाव तथा स्थानीय समुदाय की निकटवर्ती सुविधाओं में शैक्षिक सुविधाओं के सम्मेलन की विधियां और तकनीकें।

(ङ) संकाय परिचर्चा समूह

वर्ष के दौरान संकाय परिचर्चा समूह की शृंखला प्रारंभ की गई जिसमें संकाय के सदस्यों के अतिरिक्त शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में विदेशों से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया। इन परिचर्चा समूहों की सप्ताहवार आधार पर गठित किया गया और इन्होंने संकाय विकास में अत्यधिक सहायता प्रदान की।

चर्चित विषयों के ब्यौरे के साथ-साथ वक्ताओं के नाम भी नीचे दिए गए हैं :

1.	दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम की समीक्षा डा० सी० एल० सपरा	27 मई, 1981
2.	हरियाणा के लिए शैक्षिक मानकों के विकास पर अध्ययन श्री एम० एम० कपूर डा० (सुश्री) के० प्रेमी	3 जून, 1981
3.	उच्च शिक्षा, राजस्थान के प्रतिलाभ डा० जी० के० भट्ट	10 जून, 1981
4.	1981 की जनसंख्या पर पैनल परिचर्चा : शिक्षा पर प्रभाव	17 जून, 1981
5.	हरियाणा के कालिज प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम की समीक्षा डा० जी० डी० शर्मा	24 जून, 1981
6.	हरियाणा में माध्यमिक स्कूलों के मुख्याध्यापकों के नेतृत्व व्यवहार का अध्ययन तथा उसके सहसंबंध डा० एम० एम० भागिया	1 जुलाई, 1981

7.	आरक्षण नीति के कुछ पक्ष डा० एन० एन० काबरा	8 जुलाई, 1981
8.	शैक्षिक आगमों पर व्यय के स्तरों का प्रभाव डा० सी० डी० पद्मनाभन	15 जुलाई, 1981
9.	महिला शिक्षा और उर्वरता नियंत्रण डा० एम० ए० भटनागर	22 जुलाई, 1981
10.	उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियों में शिक्षा : उपलब्धि और चुनौतियां। प्रो० एस० एन० दुबे	29 जुलाई, 1981
11.	सामाजिक विज्ञानों में क्षेत्र आंकड़े संग्रह करने की समस्यायें श्री के० मोहन राय	5 अगस्त, 1981
12.	शिक्षा, विज्ञान और आर्थिक वृद्धि सुश्री रंजना श्रीवास्तव	19 अगस्त, 1981
13.	शिक्षा और समानता प्रो० सुमा चिटनिस	24 अगस्त, 1981
14.	छठी पंचवर्षीय योजना में परिप्रेक्ष्य योजना के लिए प्रविधियां डा० एस० पी० गुप्ता	26 अगस्त, 1981
15.	अमरीकी उच्च शिक्षा समस्यायें और भविष्य डा० वशिष्ट मल्होत्रा	2 सितम्बर, 1981
16.	दूरी के अध्यापन (पत्राचार द्वारा अध्यापन) के लिए नीतियों की योजना डा० ओ० एस० देवल	9 सितम्बर, 1981
17.	मलेसिया में शिक्षा योजना और प्रशासन श्री जे० वीरराघवन	16 सितम्बर, 1981

18. स्कूल जाने वाले बच्चों के संप्रत्यात्मक परिपक्वन, पोषण प्रस्थिति तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बीच अंत:संबंध — 30 सितम्बर, 1981
सुश्री मीना श्रीवास्तव

19. दिल्ली में स्कूल दूरदर्शन कार्यक्रमों की उपयोगिता और व्यापकता पर एक अध्ययन — 14 अक्तूबर, 1981
डा० आर० एल० फुटाला

20. दिल्ली में कर्मचारियों की पारिवारिक पृष्ठ-भूमि, शिक्षा, व्यवसाय तथा धन अर्जन — 28 अक्तूबर, 1981
श्री हरभजन सिंह

21. गुड़गांव जिले में शिक्षा प्राप्त करवाने की लागत — 4 नवम्बर, 1981
डा० डी० डी० शर्मा

22. उच्च तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले आत्म संकल्पनात्मक तथा अभि-ज्ञानेतर कारक — 18 नवम्बर, 1981
डा० विभा रानी

23. शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का वितरण संबंधी प्रभाव — 25 नवम्बर, 1981
श्री वी० एस० रेड्डी

24. विभिन्न बोर्डों/विश्वविद्यालयों से प्राप्त विद्यार्थियों के नम्बरों की तुलना की विधियां — 2 दिसम्बर, 1981
श्री वेद प्रकाश

25. डाक द्वारा निरीक्षण — 9 दिसम्बर, 1981
श्री टी० के० डी० नायर

26. प्रौढ़ शिक्षा वियतनाम — 30 दिसम्बर, 1981
चार सदस्यों वाली प्रौढ़ शिक्षा विशेषज्ञ दल

27. शिक्षा की यूनिट (इकाई) लागत : हिन्दू कालिज की लागत प्रभाविता का एक अध्ययन — 6 जनवरी, 1982
सुश्री मृदुला सक्सेना

28. उच्च शिक्षा में विषय और पसन्द (विकल्प) — 27 जनवरी, 1982
डा० एस० सी० गोयल

29. पश्चिमी जर्मनी में शैक्षिक विकास में समाज विज्ञान का अंशदान — 28 जनवरी, 1982
प्रो० दाइड्रिच गोल्डस्मिड

30. एलबरटा विश्वविद्यालय के स्नातक शिक्षा कार्यक्रम का संगठन — 2 फरवरी, 1982
प्रो० ई० ए० होल्डावे

31. अच्छी अध्यापक शिक्षा के लिए नियोजन — 17 फरवरी, 1982
प्रो० बकीर मैहंदी

32. ब्रिटेन में शैक्षिक प्रशासन में अनुसंधान — 24 फरवरी, 1982
डा० जार्ज बेरो

33. भारत में साक्षरता के स्तरों में इनइक्यूटी : 1981 की जनगणना का जिलावार विश्लेषण — 17 मार्च, 1982
श्री वाई० पी० अग्रवाल

34. गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए माइक्रो स्तर नियोजन — 24 मार्च, 1982
डा० आर० एस० शफी

35. ज्ञान का समाजविज्ञान : मार्क्स और मैनहैम — 31 मार्च, 1982
प्रो० समीर घोष

(च) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

संस्थान शैक्षिक योजना तथा प्रबंध से संबंधित कार्यक्रमों में यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा

कार्यालय, बैंकाक, आई बी ई तथा यू एस ई एफ आई के साथ सहयोग कर रहा है। संस्थान ने एशियाई शैक्षिक नवाचार तथा विकास कार्यक्रम (ए. पी. ई. आई. डी.) बैंकाक तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यालय के राष्ट्रीय केंद्र बिंदु (आई. बी. ई.) जिनेवा के साथ अपनी सह-सदस्यता (एसोशिएट मैम्बरशिप) को जारी रखा है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा प्रशिक्षण/संलग्नक कार्यक्रमों तथा कार्यशाला का आयोजित किया जाना एक महत्वपूर्ण कार्य था। लम्बे समय के शैक्षिक नियोजन पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला 12 जनवरी से 25 जनवरी तक आयोजित की गई जिसमें 11 विभिन्न एशियाई देशों से 21 भाग लेने वाले व्यक्ति थे और 5 प्रेक्षक थे। अमरीका के पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्चा परामर्शदाताओं के लिए भारतीय इतिहास तथा संस्कृति पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 15 व्यक्तियों ने भाग लिया। संस्थान ने बंगला देश से दो अधिकारियों के अध्ययन वीक्षण की भी व्यवस्था की।

(छ) अतिथिगण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनेक गणमान्य अतिथि संस्थान में आए। इनमें निम्न-लिखित सम्मिलित हैं :

योजना आयोग के मंत्री और सदस्य, उपकुलपति, अन्य प्रतिष्ठित शिक्षाविद् और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों से अन्य अधिकारी।

विदेशों से भी अनेक शिष्ट मंडल संस्थान में आए।

अतिथिगणों की सूची अनुबंध-2 में दी गई है।

(ज) पुस्तकालय तथा प्रलेखन सेवा

संस्थान के पास शैक्षिक योजना तथा प्रशासन तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में संबंधित पुस्तकों की एक विशाल पुस्तकालय है। इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक योजना तथा प्रबंध संबंधी साहित्य के मामले में यह पुस्तकालय, एशियाई क्षेत्र का समृद्धतम पुस्तकालय है। यह केवल संकाय, अनुसंधानकर्ताओं तथा विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की ही सेवा नहीं करता बल्कि अन्तः पुस्तकालय परिदाय पद्धति के माध्यम से अन्य संगठनों की भी सेवा करता है।

National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi
D-9362
5-12-96

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1200 नए प्रलेखों तथा 1791 पुस्तकों से पुस्तकालय की श्रीवृद्धि की गई। इस समय पुस्तकालय के पास 30,137 से अधिक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय के पास संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, ओ ई सी डी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनीसेफ आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों की रिपोर्टें भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में प्रतिवर्ष 253 पत्र-पत्रिकाएं आती हैं जो मुख्यत: शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंध तथा अन्य संबद्ध विषयों की होती हैं। इन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित सभी लेखों की प्रविष्टि अनुक्रमणिका में की जाती है। पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त पुस्तकालय में समाचारपत्रों से शैक्षिक योजना तथा प्रबंध संबंधी लेखों की कतरनें भी एकत्र की जाती हैं।

पाठकों को महत्वपूर्ण रोचक लेखों तथा अन्य नई सामग्री से परिचित कराने के लिए, इन सबकी मासिक सूचियाँ तैयार की गई।

पाठकों को हर पखवाड़े में प्राप्त हुई शिक्षा संबंधी पत्र-पत्रिकाओं को विषयवस्तु से अवगत कराने के लिए संस्थान ने अपनी पाक्षिक पत्रिका '**पीरियाडिकल्स आन एजूकेशन : टाइटिल्स रिसीव्ड एण्ड देअर कन्टेन्ट्स**' का अनुलिखित प्रकाशन जारी रखा है।

पुस्तकालय ने विविध क्षेत्रों से सूचना के नए मदों को संस्थान के कार्यक्रम यूनिटों और अनुसंधान परियोजना दलों को प्राप्त करवाने के लिए एकत्रित किए हैं, जहाँ वे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ग्रन्थ सूचियाँ तैयार की गई हैं।

प्रलेखन उप-एकक

उप-राष्ट्रीय पद्धति यूनिट के निकट सहयोग से पुस्तकालय में एक पृथक् उप-यूनिट के रूप में एक प्रलेखन यूनिट की स्थापना की गई है जिससे संस्थान सूचना तथा अनुभव के समाशोधन गृह के रूप में कार्य कर सके। यूनिट ने क्षेत्रों, राज्यों तथा जिलों से संबंधित प्रलेखों को एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। निम्नलिखित मुख्य विषयों से संबंधित प्रलेख एकत्रित किए गए हैं :

(i) जिला जनगणना हस्त पुस्तिकायें,
(ii) जिला गजेटियर,

(iii) जिला सांख्यिकीय हस्त पुस्तिका,

(iv) जिला और राज्यों की छठी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनायें,

(v) जिला बैंक रिपोर्ट,

(vi) राज्यों की सांख्यिकीय संक्षिप्तियां,

(vii) तीसरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण, स्कूल शिक्षा, चौथा अखिल भारतीय सर्वेक्षण, स्कूल शिक्षा,

(viii) राज्यों की शैक्षिक योजनायें,

(ix) राज्यों और जिलों के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण,

(x) राज्य शिक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्टें,

(xi) शैक्षिक संहितायें, अधिनियम, नियम तथा नियम पुस्तिकायें आदि ।

चूंकि जिले को शैक्षिक योजना और प्रशासन का एक यूनिट माना गया है, इसलिए प्रलेखन केंद्र में भारत के विषय में सभी संबद्ध सूचना और आंकड़े उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव किया गया है।

(झ) प्रकाशन

वर्ष 1981-82 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए :

1. निम्नलिखित राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा का प्रशासन :
   —आसाम
   —बिहार
   —उड़ीसा
   —राजस्थान
   —पश्चिमी बंगाल

2. बिहार राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद ।

3. वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण)

4. इ पी ए बुलेटिन ; 1980-81 साप्ताहिकी—खंड 4 नं० 2 (जुलाई, 81)

खंड 4 नं० 3 (अक्तूबर 1981) तथा खंड 4 नं० 4 और खंड 5 नं० 1 (जनवरी और अप्रैल, 1982)।

नीपा ने प्रत्येक आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम, संगोष्ठी तथा कार्यशाला की साइक्लोस्टाइल रिपोर्ट भी निकाली है। समीक्षाधीन अवधि में निम्नलिखित रिपोर्टें तैयार की गईं :

1. हरियाणा के लिए शैक्षिक मानकों पर कार्यशाला (अप्रैल 2-4, 1981)।

2. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास संगोष्ठी (अप्रैल 6-11, 1981)।

3. जम्मू कश्मीर के जिले और तहसील के शैक्षिक नियोजन अधिकारियों के लिए दूसरी प्रशिक्षण संगोष्ठी (अप्रैल 11-25, 1981)

4. दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।

5. हरियाणा के कालिज के प्रधान अध्यापकों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम (मई 25-जून 6, 1981)।

6. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम (मई 25-जून 12, 1981) ।

7. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए पहला पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (जून 22-27, 1981)।

8. संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययनों के पर्यवेक्षकों और पाठ्यचर्या परामर्शदाताओं के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति पर कार्यशाला (जून 30-जुलाई 16, 1981)।

9. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम (अगस्त 3-21, 1981)।

10. श्री फजलूर रहमान खान, उप शिक्षा अधिकारी, बंगला देश का स्थानन (सितम्बर 21-अक्तूबर 17, 1981)।

11. गैर-मौद्रिक आगमों पर बल देते हुए शैक्षिक विकास के लिए संसाधनों के उचित उपयोग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (सितम्बर 22-25, 1981)।

12. स्कूल प्रबंध पर कार्यशाला (नवम्बर 2-7, 1981)।

13. कालिज प्रधान अध्यापकों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम (नवम्बर 2-21, 1981)।

14. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए क्षेत्र अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (नवम्बर 23-दिसम्बर 5, 1981)।

15. महिला कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम (नवम्बर 30-दिसम्बर 19, 1981)।

16. लम्बे समय के शैक्षिक नियोजन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (दिसम्बर 12-23, 1981)।

17. स्कूलों के मुख्य अध्यापकों के लिए स्कूल प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम (दिसम्बर 31, 1981-जनवरी 9, 1982)।

18. लम्बे समय के शैक्षिक नियोजन पर क्षेत्रीय कार्यशाला (जनवरी 12-25, 1982)।

19. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए दूसरा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

20. राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य कार्मिकों के लिए अभिविन्यास कायक्रम (फरवरी 1-4, 1982)।

21. संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के निरीक्षण अधिकारियों तथा स्कूलों के मुख्य अध्यापकों के लिए स्कूल प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (फरवरी 8-13, 1982)।

22. कालिज के प्रधान आचार्यों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम (फरवरी 8-27, 1982)।

23. जनसंख्या शिक्षा पर अखिल भारतीय संगोष्ठी (उच्च स्तरीय शैक्षिक प्रशासकों के लिए (फरवरी 18-19, 1982)।

24. हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए कार्मिक और वित्तीय प्रबंध से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम (फरवरी 23-27, 1982)।

25. विश्वविद्यालय प्रशासन परियोजना के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका जाने वाले कालिज प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (जून 29-अप्रैल 1, 1982)।

भाग—3

सलाहकारी, परामर्शकारी तथा सहायता सेवायें

संस्थान का मुख्य कार्य शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों तथा भारत में अन्य मुख्य स्वायत्त संगठनों तथा विदेश में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा सरकारों को सलाहकारी, परामर्शकारी तथा सहायता सेवायें प्रदान करना है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित सेवायें प्रदान कीं; स्कूल अवस्था पर शैक्षिक सुविधाओं के लिए मानक बनाकर राज्य तथा केन्द्र सरकार को विविध प्रकार की सेवायें, शैक्षिक विकास के विभिन्न पक्षों की राष्ट्रीय मॉनिटरिंग की सरल और सहजता से लागू की जाने वाली पद्धति का निर्माण, शैक्षिक योजना और प्रशासन पर नीति संबंधी प्रभाव वाले अनेक अनुसंधान अध्ययन का कार्य, केन्द्र सरकार के प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता से संबंधित कार्यक्रमों में तेजी लाने में सहायता तथा अन्य महत्वपूर्ण संगठनों को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में संकाय संसाधनों को उपलब्ध करवाना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य क्रियाकलाप। संस्थान ने यूनेस्को तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए अनुसंधान अध्ययन संचालित करके तथा उन्हें परामर्शकारी सेवायें प्रदान कर अनेक क्रियाकलापों को भी हाथ में लिया। इसके अतिरिक्त संस्थान ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, तथा शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संबंधित संस्थाओं और कार्मिकी का अकादमिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन भी किया। संस्थान ने केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर आयोजित उच्च स्तरीय सम्मेलनों, समितियों तथा कार्यकारी समूहों में भी भाग लिया। संस्थान ने शिक्षा नियोजन तथा प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखितों से भी सक्रिय रूप से सहयोग किया—शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभाग, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, यूनेस्को तथा यू एस ई एफ आई आदि।

इस संबंध में संस्थान के क्रियाकलापों का व्यापक रूप से निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है :

राष्ट्रीय

(क) केन्द्रीय मंत्रालयों के आग्रह पर प्रारंभ किए गए अनुसंधान अध्ययन और परियोजनायें।

(ख) शिक्षा सचिवों तथा मंत्रियों के सम्मेलनों, अखिल भारतीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, समितियों और कार्य शक्तियों में योगदान।

उप-राष्ट्रीय

(क) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अनुरोध पर हाथ में लिए गए अध्ययन और परियोजनायें।

(ख) पद्धति संवर्द्धन में राज्यों को दी गई सलाह।

(ग) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा संगठित कार्यक्रमों में संकाय सहायता।

अंतर्राष्ट्रीय

(क) यूनेस्को के आग्रह पर हाथ में लिए अनुसंधान अध्ययन।

(ख) संगठित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि में योगदान।

1. राष्ट्रीय

(क) अध्ययन और परियोजनायें

संस्थान ने शिक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के कहने पर निम्नलिखित अध्ययन प्रारंभ किए। इनका विवरण संस्थान के क्रियाकलापों के पुनरावलोकन में पहले से विस्तृत रूप से दिया गया है :

(i) संगठनात्मक निवोजन, मॉनिटरिंग और सांख्यिकी पर अध्ययन;

(ii) आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन;

(iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का औद्योगिक प्रशिक्षण;

(iv) नीपा में जनसंख्या शिक्षा;

(v) शैक्षिक रूप से कुछ प्रगतिशील और पिछड़े हुए राज्यों में निरीक्षण पद्धति और अभ्यास तथा प्रपत्र।

(ख) अखिल भारतीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, समितियों आदि में योगदान तथा अन्य सलाहकारी सेवायें।

संस्थान ने विभिन्न उच्च स्तरीय सम्मेलनों, समितियों और कार्यकारी समूहों तथा अखिल भारतीय संगोष्ठियों में भाग लिया। इस संबंध में जून 1981 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में संस्थान द्वारा प्रस्तुत एक टिप्पण का, जिसमें छठी पंचवर्षीय योजना में शैक्षिक योजना और प्रशासन की मुख्य क्रियाकलापों की सूची दी गई थी और इस संबंध में संस्थान की भूमिका के बारे में बतलाया गया था, विशेष उल्लेख किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय तथा उसके विविध कार्यकारी समूहों की शिक्षा सांख्यिकी पर उच्च स्तरीय समिति, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता पर राष्ट्रीय समिति, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक सुविधाओं पर विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की स्थायी समिति तथा शैक्षिक संघों के अखिल भारतीय संघ, भारत का परिवार नियोजन संघ तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थानों और महिला अध्ययनों पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा प्रायोजित पारिवारिक जीवन शिक्षा में अध्यापक की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन में संस्थान द्वारा भाग लिए जाने का भी विशेष उल्लेख किया जा सकता है।

2. उप-राष्ट्रीय

(क) अध्ययन और परियोजनायें

संस्थान ने हरियाणा के लिए शैक्षिक मानकों के विकास पर एक अध्ययन प्रारंभ किया जिसका विस्तृत ब्यौरा संस्थान के क्रियाकलापों की समीक्षा के अंतर्गत दिया गया है। संस्थान ने सिक्किम के शिक्षा विभाग के पुनर्गठन में भी सहायता प्रदान की। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक दल का नेतृत्व नीपा के निदेशक ने किया।

(ख) पद्धतियों के सुधार में राज्यों को सलाह देना

संस्थान ने स्कूलों की निरीक्षण रिपोर्ट का फोरमेट तैयार करने में संघ शासित

क्षेत्र लक्षद्वीप को सहायता प्रदान की तथा वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली तथा विद्या भवन, उदयपुर को दी गई स्वायत्तता की समीक्षा के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सहायता की। संस्थान ने केरला, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की समितियों तथा शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठकों में भी भाग लिया।

(ग) राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा संगठित कार्यक्रमों में संकाय द्वारा दी गई सहायता

संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्रीय कालिज, मैसूर, राज्य संसाधन केंद्र, हरियाणा, एस सी इ आर टी, हरियाणा, दिल्ली समाजकार्य अनुवर्ती शिक्षा केंद्र, यादवपुर विश्व-विद्यालय, कलकत्ता, श्रमिक विद्यापीठ, बम्बई, एच सी एम लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर तथा एस सी इ आर टी, तमिलनाडू द्वारा संचालित विविध कार्यक्रमों में अपने संकाय सदस्यों की सेवायें विशेषज्ञ व्यक्तियों के रूप में प्रदान कीं।

3. अंतर्राष्ट्रीय

(क) अनुसंधान अध्ययन

संस्थान ने यूनेस्को सांख्यिकी कार्यालय, पेरिस तथा यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक से एक करार के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन प्रारंभ किए, जिनका ब्यौरा संस्थान के क्रिया-कलापों की समीक्षा के अंतर्गत दिया गया है :—

(i) शैक्षिक व्यय—एक क्षेत्रीय विश्लेषण।

(ii) भारत के दो राज्यों में शैक्षिक योजना तथा इक्यूटी योजना पर तुलनात्मक नीति अध्ययन।

(iii) ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा के घटक और संबंध पर किए गए कुछ प्रयोगों पर तुलनात्मक अध्ययन; योजना और प्रशासन तंत्र।

(iv) खंड तथा संस्था स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन की विधियां और समस्याय।

(v) एशिया और पेसिफिक में शैक्षिक विकासों की एक पश्चो-मुखी अध्ययन (1960 से 80 तक)।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

संस्थान शैक्षिक नियोजन और प्रबंध से संबंधित कार्यक्रमों में बैंकाक में यूनेस्को के

शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय, आई. बी. ई. तथा यू. एस. ई. एफ. आई. से सहयोग कर रहा है जिसका उल्लेख संस्थान के क्रियाकलापों की समीक्षा में भी किया गया है। अफगानिस्तान, बंगला देश, चीन, नेपाल, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलिपीन्स, श्रीलंका, थाईलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका से 38 विदेशियों ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से बनाए गये कार्यक्रमों में भाग लिया।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा अध्ययन वीक्षणों में योगदान

संस्थान ने विविध कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा अध्ययन वीक्षणों में भाग लिया। संस्थान ने निम्नलिखित में भाग लिया—शैक्षिक प्रशासन में कार्यक्रम विकास बैठक, बैंकाक; मनिला (फिलिपीन्स), जकार्ता (इंडोनेशिया) तथा बैंकाक (थाईलैंड) में अंतरदेशीय विनिमय अध्ययन वीक्षण; इंडो-फ्रेंच सांस्कृतिक करारनामें, पेरिस के अंतर्गत संगठन की समस्याओं पर दूसरी संगोष्ठी; बैंकाक में शिक्षा पर संगोष्ठी, नागोया (जापान) में क्षेत्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र केंद्र द्वारा ग्रामीण विकास पर आयोजित संगोष्ठी; संयुक्त राष्ट्र एशियाई और पैसिफिक विकास केंद्र, कोलालम्पुर द्वारा आयोजित '1980 के दशवर्षावधि में विकास संभावनायें" शीर्षक पर सम्मेलन; होनोलूलू में एशिया तथा पैसिफिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संघ (एन ए ए पी ई) द्वारा आयोजित शिक्षा और परिवर्तन पर संगोष्ठी तथा पर्यावरण विभाग, भारत सरकार तथा भारतीय पर्यावरणीय शिक्षा सभा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

भाग—4

प्रशासन और वित्त

संस्थान की संपूर्ण वित्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार द्वारा नामित-अध्यक्ष इसका प्रधान है। निदेशक जो संस्थान का अकादमिक और कार्यपालक प्रधान है, की प्रशासन, वित्त और अनुसंधान क्षेत्रों में सहायता के लिए एक कार्यपालक निदेशक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए डीन की व्यवस्था की गई है। संस्थान की संगठनात्मक संरचना में अकादमिक प्रशासन और लेखा एककों की व्यवस्था है। अकादमिक एककों के प्रधान अध्येता/सहयोगी अध्येता हैं और प्रशासन और लेखा एकक क्रमशः रजिस्ट्रार और लेखा अधिकारो के अंतर्गत कार्य करते हैं।

परिप्रेक्ष्य योजना में परिकल्पित विविध प्रकार के तथा संवर्धित क्रियाकलापों को संस्थान द्वारा प्रारंभ किए जाने की दृष्टि से संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने तथा नयी चुनोतियों का सामना करने के लिए संकाय संबंधी अकादमिक तथा प्रशासनिक सहायता को सुदृढ़ तथा पुनर्गठित किया गया है। प्रलेखन, आंकड़ा बैंक तथा कार्टोग्राफी सेल और प्रकाशन एककों की स्थापना करके एक मजबूत अकादमिक आधारिक संरचना का निर्माण किया गया है। प्रशासनिक आधारिक संरचना को भी सुदृढ़ किया गया।

उच्च प्रतिभासंपन्न संकाय को आकर्षित करने तथा उन्हें बनाए रखने की दृष्टि से संकाय सदस्यों के लिए यू० जी० सी० के वेतनमानों को लागू करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया तथा अनुमोदन के लिए उसे शिक्षा मंत्रालय भेजा गया। संस्थान के निर्माण कार्य में भी तीव्रता लायी गई।

संकाय सदस्यों के वेतनमानों में संशोधन तथा उनके पदों में परिवर्तन करने पर उप समिति

सेवा स्थितियों में सुधार करने के लिए संकाय सदस्यों के संयुक्त अभ्यावेदन पर कार्यपालक समिति ने 28 जून, 1980 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में संकाय के सदस्यों

के पदनामों में परिवर्तन तथा वेतनमानों में संशोधन किए जाने के प्रश्न पर डा० मैल्कौल्म एस आदिशेषय्या की अध्यक्षता में उप-समिति का गठन किया। शिक्षा मंत्रालय तथा योजना आयोग ने इस समिति में प्रतिनिधित्व किया। उप समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1980 में प्रस्तुत की जिसमें आचार्यों, प्राचार्यों तथा प्राध्यापकों के लिए यू जी सी के वेतनमान दिए जाने की सिफारिश की, परन्तु अध्येताओं, सहयोगी अध्येताओं तथा अनुसंधान/प्रशिक्षण अध्येताओं के पदों के लिए उनकी राय यह थी कि उनके वर्तमान पदनाम ही रखें जायें। उप समिति ने संकाय सदस्यों के कार्य विवरणों अर्हताओं तथा स्टाफ संबंधी और मकान संबंधी अन्य सिफारिशें भी कीं। कार्यपालक समिति द्वारा 2 मई, 1981 को आयोजित सातवीं बैठक में इन सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यपालक समिति ने संस्थान के संकाय सदस्यों के पदनामों में परिवर्तन तथा उनके वेतनमानों में परिशोधन करने के लिए उप-समिति की सिफारिशों पर सामान्यतः अपनी सहमति प्रकट की। उप-समिति की सिफारिश के अनुसार संकाय सदस्यों के परिशोधित वेतनमानों पर आदिशेषय्या समिति की रिपोर्ट को अनुमोदनार्थ शिक्षा मंत्रालय भेजा गया।

संकाय तथा अकादमिक सहायता का पुनर्गठन

नीपा के परिप्रेक्ष्य योजना में संकाय को शिक्षाशास्त्रियों तथा शिक्षा प्रशासकों की एकत्त टीम माना गया है जो क्षेत्रों/समस्याओं के विशिष्ट अध्ययन में वैयक्तिक रूप से लगे हुए हैं तथा साथ ही समय समय पर विशिष्ट कार्यों पर समूह रूप में परियोजित किए जाते हैं। संकाय परिनियोजन की व्यवस्थाओं को अधिकतम नम्य होना चाहिए जिससे परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुसार संकाय का पुनः समूहन संभव हो सके और साथ ही विशिष्टीकरण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा सकें। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए संस्थान के कार्य को विशिष्ट उत्तरदायित्वों, तथा समन्वय और पुनरावलोकन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के अनुसार निम्नलिखित समूहों में पुनर्गठित किया गया :

(1) शैक्षिक नियोजन
(2) शैक्षिक प्रशासन
(3) शैक्षिक वित्त
(4) शैक्षिक नीति
(5) उप-राष्ट्रीय पद्धतियां
(6) स्कूल और गैर-औपचारिक शिक्षा
(7) उच्च शिक्षा
(8) अंतर्राष्ट्रीय यूनिट

इन समूहों से सौंपे गए क्षेत्रों में कार्यक्रमों के विकास और कार्य-पालन में पूरे उत्तर-दायित्व से कार्य करने की आशा की जाती है। यद्यपि उपरोक्त समूह लम्बे समय तक लगातार कार्य करने के आधार पर कार्य करते रहेंगे, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निदेशक द्वारा समय-समय पर विशिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट कार्य-शक्तियों तथा समितियों का भी गठन किया जाएगा। प्रारंभ में कार्यशक्तियों और समितियों का गठन किया गया।

कार्यशक्तियां (ब्रल)

(i) जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण पर कार्य शक्तियां।

(ii) मॉनिटरिंग और मूल्यांकन पर कार्यशक्तियां।

(iii) निरीक्षण और पर्यवेक्षण पर कार्यशक्तियां।

(iv) जनसंख्या शिक्षा पर कार्यशक्तियां।

(v) लागत अध्ययन पर कार्यशक्तियां।

(vi) आश्रम स्कूलों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर कार्य शक्तियां।

समितियां

(i) पत्राचार पाठ्यक्रम पर समिति

(ii) पुस्तकालय और प्रकाशन पर समिति

गठित अकादमिक समूह और कार्यशक्तियों के कार्य का समन्वय और पुनरावलोकन संस्थान की अकादमिक समिति द्वारा निदेशक की अध्यक्षता में किया जाता है। इस समिति में विभिन्न समूहों के प्रधान, कार्यपालक निदेशक, डीन और निदेशक द्वारा समिति में नामित संकाय के सदस्य होते हैं।

प्रशासन का पुनर्गठन

संस्थान द्वारा प्रारंभ किए गए विविध प्रकार के और संवर्धित क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रशासन के कार्य करने के तरीके को अधिक तर्कसंगत तथा प्रवाहयुक्त बनाने की आवश्यकता के कारण प्रशासन विभाग को निम्नलिखित दो उप-एककों में पुनर्गठित किया गया है जिसके प्रभारी अधिकारी रजिस्ट्रार होंगे।

(i) सामान्य प्रशासन एकक (खरीद, देखभाल, राज्यीय और सामान्य सेवायें); तथा

(ii) कार्मिक और अकादमिक प्रशासन एकक।

डीन के समग्र नियंत्रण के अंतर्गत एक प्रशिक्षण टाइपिंग पूल की स्थापना भी की गई है। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए टंकण सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

संकाय और अन्य स्टाफ का सुदृढ़ीकरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1100-1600 रुपये वेतनमान वाले सहयोगी अध्येताओं के 4 पद और 700-1300 रु० वेतनमान वाले अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी के तीन पद तथा अन्य सहायक स्टाफ के पदों को बनाकर संकाय को सुदृढ़ बनाया गया। उपरोक्त में से सहयोगी अध्येताओं के दो पद उप-राष्ट्रीय पद्धति एकक तथा सहयोगी अध्येता और अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी के एक एक पद जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्रमों के लिए उत्पन्न किए गए। 1500-2000 रुपये वेतनमान में प्रकाशन अधिकारी का एक पद तथा 700-1300 रु० वेतनमान में एक प्रलेखन अधिकारी का पद भी उत्पन्न किया गया। वर्ष के दौरान कुछ दफ्तरी पद भी उत्पन्न किए गए।

31 मार्च, 1981 के केडर संख्या 118 की तुलना में 31 मार्च, 1982 के केडर स्टाफ और परियोजना स्टाफ की कुल स्वीकृत संख्या क्रमश: 139 और 28 थी।

सेवाकालीन प्रशिक्षण

संस्थान के सहयोगी अध्येता श्री एम० एम० कपूर ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस (फ्रांस) में 13 अक्तूबर, 1981 से नौ माह तक शैक्षिक योजना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी श्री वाई०पी० अग्रवाल ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता में 9 फरवरी से 20 फरवरी, 1982 तक शिक्षा में नमूना सर्वेक्षण विधियों के अनुप्रयोग पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

प्रकाशन सहायक श्री एम० एम० अजवानी ने ओपन स्कूल, माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली में 23 जनवरी 1982 के मुद्रण प्रौद्योगिकी में अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लिया।

संस्थान के रजिस्ट्रार श्री आर० पी० सक्सेना ने सचिवालयिक प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में 29 मार्च से 24 अप्रैल, 1982 तक प्रबंध विकास कार्यक्रम में भाग लिया।

स्टाफ परिवर्तन

श्री जे० वीरराघवन 30 अप्रैल, 1981 तक संस्थान के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। प्रो० मुनिस रज़ा, अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 1 मई, 1981 को संस्थान के निदेशक का पद संभाला। प्रो० एम० वी० माथुर, भूतपूर्व निदेशक नीपा, ने 1 जून, 1981 को प्रतिष्ठित आचार्य के रूप में संस्थान में प्रवेश किया।

श्री वाई० पी० अग्रवाल, डा० (श्रीमती) आर० एस० शफी, श्री एन० वी० वरगीज, डा० (कुमारी) के० सुजाता, डा० (श्रीमती) सुधा राव तथा डा० जे० बी० जी० तिलक ने संकाय में प्रवेश किया। श्री बी० सेल्वराज ने प्रकाशन अधिकारी के पद पर संस्थान में प्रवेश किया।

डा० शंकर प्रसाद श्रीवास्तव तथा डा० (श्रीमती) सुष्मा मेहर ने नीपा में जनसंख्या शिक्षा कार्यकलापों से संबंधित कार्य के लिए संस्थान में प्रवेश किया। डा० गोपेश कुमार भट्ट ने शिक्षा की लागत के अध्ययन से संबंधित कार्य के लिए संस्थान में प्रवेश किया।

डा. जे. एल. आजाद, भूतपूर्व निदेशक (शिक्षा), योजना आयोग तथा डा. जे. एन. कौल, भूतपूर्व परामर्शदाता, नीपा ने वरिष्ठ अध्येता, आई. सि. एस. एस. आर. के रूप में प्रवेश किया।

डा० जी० डी० शर्मा, अध्येता, नीपा ने बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई में रीडर के पद पर नियुक्त हो जाने पर संस्थान छोड़ दिया।

31 मार्च, 1982 में संकाय के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-5 में दी गई है। स्टाफ में परिवर्तन परिशिष्ट-6 में दिए गए हैं।

(1) प्रलेखन एकक

परिप्रेक्ष्य योजना में संस्थान के बहुपक्षीय कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की सहायता हेतु एक अकादमिक आधारित संरचना का निर्माण करने के लिए एक प्रलेखन एकक की स्थापना की आवश्यकता को प्रधानता दी गई है। कार्यपालक समिति ने 3 सितम्बर 1981 में हुई अपनी आठवीं बैठक में पुस्तकालय के अंदर एक पृथक उप-एकक के रूप में एक प्रलेखन एकक की स्थापना की अनुमति प्रदान की और इस एकक को व्यवस्थित रूप से

चलाने के लिए 700-1600 रु० वेतनमान में एक प्रलेखन अधिकारी के पद की भी सहमति प्रदान की। यह एकक उप-राष्ट्रीय पद्धति एकक के निकट सहयोग से कार्य करेगा। एकक ने समीक्षाधीन वर्ष में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

(2) आंकड़े बैंक तथा कार्टोग्राफिक सेल

संस्थात ने कार्यक्रमों के पुनरावलोकन से प्राप्त हो रहे नए जनगणना आंकड़े सहित बृहत मात्रा में प्राप्त आंकड़े के नियोजन तथा उनकी परिमाणात्मक विश्लेषण पर बल देते हुए एक अध्ययन के निर्माण की तुरंत आवश्यकता पर अपना ध्यान फोकस किया। इस कार्य को हाथ में लेने के लिए संस्थान में एक आंकड़े बैंक स्थापित करने की तथा राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सहयोग से एन० सी० इ० आर० टी० में लगाये गए कम्प्यूटर टर्मिनल की सुविधाओं का उपयोग करने की आवश्यकता अनुभव की गई।

क्षेत्रीय योजना के लिए भी एक कार्टोग्राफिक सेल की स्थापना की आवश्यकता की अनुभव की गई।

कार्यपालक समिति ने 2 मई, 1982 को आयोजित अपनी सातवीं बैठक में संस्थान में एक आंकड़े बैंक और कार्टोग्राफिक सेल की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की और उपरोक्त एककों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 700-1300 रु० तथा 550-900 रु० वेतनमानों में क्रमश: अनुसंधान सहयोगी (आंकड़े बैंक) तथा वरिष्ठ तकनीकी सहायक (कार्टोग्राफ़िक सेल) का एक-एक पद उत्पन्न करने पर भी सहमति प्रदान की। समीक्षाधीन अवधि वर्ष में उपरोक्त एककों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

(3) प्रकाशन एकक

परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत बहुमुखी कार्यक्रम हाथ में लिए जाने के कारण उच्च-स्तरीय संपादन, मुद्रण तथा अनुलेखन की तथा अनेक रिपोर्ट, आवधिक पत्रिकायें तथा पत्रिकायें निकालने की आवश्यकता है। संस्थान के विस्तृत प्रकाशन कार्यक्रम ने प्रकाशन अधिकारी के प्रभार के अंतर्गत एक प्रकाशन एकक की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की। कार्यपालक समिति ने 3 सितम्बर, 1981 को आयोजित अपनी आठवीं बैठक में अन्य आवश्यक स्टाफ सहित 1500-2000 रु० वेतनमान में नियुक्त एक प्रकाशन अधिकारी के अधीन एक प्रकाशन एकक स्थापित करने पर सहमति प्रदान की।

छात्रावास

संस्थान नई दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित करता है, वे आवासी होते हैं।

प्रशिक्षणार्थियों को एक सात मंजिले छात्रावास में रखा जाता है जिसमें पूर्णत: सज्जित 48 कमरे हैं। इन सभी कमरों में संलग्न स्नानगृहों की व्यवस्था है तथा प्रत्येक कमरा दो बिस्तरों से सज्जित है।

छात्रावास में वार्डन की व्यवस्था नहीं थी। कार्यपालक समिति ने अपनी 3 सितम्बर, 1981 की आठवीं बैठक में उचित मानदेय की अदायगी पर एक छात्रावास वार्डन की नियुक्ति अथवा छात्रावास में निःशुल्क रहने की सुविधाओं, जैसा भी उचित जान पड़े, पर अपनी सहमति प्रकट की। तदनुसार 1-10-1981 को एक वार्डन की नियुक्ति की गई है।

छात्रावास संस्थान से इंटरकॉम पद्धति से अंत: संबद्ध और छात्रावास की सभी सातों मंजिलें भी इंटरकाम द्वारा अंत: संबंधित हैं।

विदेशी अतिथियों तथा उच्चाधिकारियों को उपयुक्त सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से कार्यपालक समिति ने 8 जनवरी, 1982 को आयोजित अपनी नवीं बैठक में छात्रावास की पहली मंजिल पर चार कमरों में वातानुकूलित यंत्रों, कम्वेक्टर हीटरों तथा गीज़रों की सुविधायें प्रदान कर उन्हें उच्चस्तरीय बनाने पर अपनी सहमति प्रकट की।

उच्चस्तरीय सुविधाओं वाले कमरों का किराया 100 रु. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति नियत किया गया। भाग लेने वालों के लिए कमरे का किराया प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3 रु० से बढ़ा कर 6 रु० तथा अन्यों के लिए 10 रु० प्रति दिन से 15 रु० प्रति दिन करने का भी निर्णय लिया गया।

वार्डन की नियुक्ति, इंटरकॉम की सुविधा देने तथा कमरों में अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करने से छात्रावास के कार्य तथा उसकी उपयोगिता में महत्वपूर्ण संवृद्धि हुई है।

निर्माण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्य किया गया :

(i) 16 ए टाइप क्वाटरों तथा 8 ई टाइप क्वाटरों का निर्माण जो 1980-81 में अनुमानित लागत 25.03 लाख रु० पर मंजूर किया गया था, समाप्ति पर है। निदेशक के क्वाटर तथा टाइप II और III के आठ क्वाटरों के निर्माण, जिसकी अनुमानित लागत 14.61 लाख रुपये है, की मंजूरी दे दी गयी है।

(ii) संस्थान की जल पूर्ति संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए एक अतिरिक्त कुओं के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया तथा दो ट्यूबवेल्स की बोरिंग की स्वीकृति प्रदान की गई।

(iii) वर्ष के दौरान मनोरंजन हाल और गराज का निर्माण समाप्त कर लिया गया और सितम्बर 1981 में उनको अपने अधिकार में ले लिया गया है। संस्थान के क्रियाकलापों का विस्तार होने तथा कार्यालय स्थान की कमी होने के कारण तथापि मनोरंजन हाल को छः कार्यालय कमरों में विभाजित कर उसे कार्यालय में बदल दिया गया है। दो गराजों भी कार्यालय प्रयोजन के लिए कार्यालय कक्षों में बदल देने का भी निर्णय किया गया है। इससे भी अधिक छात्रावास के खुले स्थान का उपयोग करके दो अतिरिक्त स्टोर कक्षों का भी निर्माण किया गया है। इस प्रकार तैयार की गयी अतिरिक्त कार्यालय तथा स्टोर की सुविधाओं से संस्थान की बढ़ती हुई कार्यालय स्थान तथा स्टोर संबंधी आवश्यकताओं को कुछ सीमा तक पूरा करना संभव हो सका है।

(iv) कार्यालय तथा छात्रावास के सामने और इर्दगिर्द के क्षेत्र को फूलों की क्यारियों, घास तथा पेड़ों से सजाया गया है।

अन्य आधारिक संरचनायें

(i) इंटरकॉम पद्धति

संचार पद्धति से संवर्धित करने के लिए संस्थान और छात्रावास में 35,000 रु० की लागत से एक इंटरकॉम पद्धति की स्थापना की गई है।

(ii) उपस्कर

पहली मंजिल पर सम्मेलन हाल को अधुनातम फिलिप्स सम्मेलन पद्धति से जिसमें 12 प्रतिनिधि यूनिट तथा एक अध्यक्ष यूनिट है, 0.21 लाख रुपये की लागत से सुसज्जित किया गया है।

विशेष प्रयत्नों से कुछ अत्यधिक मूल्य वाले उपस्करों को, जैसे फोटोकोपियर तथा आफसेट मल्टिलिथ मशीन जो खराब और बेकार पड़ी थी, की मरम्मत करवाई गयी।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा आंकड़े बैंक और कार्टोग्राफिक सेल को पूरी तरह उपस्करों से लेस करने के लिए प्रोग्राम केलकुलेटर, मेग्नेटिक कार्ड रीडर, कम्प्यूटर टैप्स, स्लाइड प्रोजेक्टर, कार्टोग्राफिक उपस्कर आदि खरीदे गए ।

वित्त

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नीपा को पूरी वित्तीय सहायता दी जाती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान संस्थान को 45.84 लाख रुपये का अनुदान (गैर-योजना लेखा से 20.29 लाख रुपये तथा योजना लेखा से 25.55 लाख रुपये) प्राप्त हुआ और इसके साथ पिछले वर्ष से चले आ रहे रोकड़ शेष जो 2.46 लाख रुपये है। संस्थान ने छात्रावास के कमरों की किराये से 0.66 लाख रुपये तथा अन्य आय से 2.82 लाख रुपये प्राप्त किए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 51.78 लाख रुपये की कुल प्राप्ति, जिसमें रोकड़ शेष भी सम्मिलित है, की तुलना में कुल व्यय 49.46 लाख रुपये था (गैर-योजना लेखा से 23.58 लाख रुपये तथा 'योजना' लेखा से 25.88 लाख रुपये)। वर्ष 1981-82 के लेखों की लेखाजांच अगस्त-सितम्बर, 1982 में की गई । लेखा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की प्रति परिशिष्ट-6 में दीं गई है।

अनुबन्ध—1

स्कूल शिक्षा प्रबंध

1. दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (20-25 अप्रैल, 1981)

प्रस्तावना

दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) के शिक्षा विभाग के अनुरोध पर राष्ट्रीय संस्थान ने एम सी डी के शिक्षा विभाग के 29 वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित एक सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया।

उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे; भाग लेने वालों की सहायता से उनकी क्षेत्रीय समस्याओं यथा उनके जॉब चार्ट का समालोचनात्मक विश्लेषण करना; उन्हें कुछ आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों तथा उनके शैक्षिक प्रशासन में अनुप्रयोग से परिचित करवाना, उनकी शैक्षिक प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के रूप में व्यावसायिक प्रवीणता और प्रभावशीलता प्राप्त करने में सहायता करना।

विषयवस्तु

दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करने के पश्चात् यह कार्यक्रम तैयार किया गया। कार्यक्रम में निम्न विषय लिए गए थे ; भारत में प्राथमिक शिक्षा का सर्व-व्यापीकरण—समस्यायें तथा भविष्य; दिल्ली नगर निगम में प्राथमिक शिक्षा का सर्व-व्यापीकरण; प्राथमिक शिक्षा स्कूलों में क्षेत्रीय अपव्यय तथा गतिरोध; इसको कुछ सीमा तक कम करने में निरीक्षण अधिकारियों की भूमिका, दिल्ली

नगर निगम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए प्रोत्साहन; दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों के जॉब चार्ट का समालोचनात्मक पुनरावलोकन; दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षा में संवर्धन; दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण; प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व; दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शारीरिक सुविधायें, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान की भूमिका; दिल्ली नगर निगम स्कूलों के लिए टेलीविजन तथा रेडियो पर संवर्द्धित कार्यक्रमों का मूल्यांकन; स्कूल नामांकन और अध्यापकों के प्रक्षेपण की तकनीकें, शैक्षिक प्रशासन के लिए मानवीय संबंध उपागम; दिल्ली नगर निगम स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप; समस्यायें और भविष्य; अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा—निरीक्षण अधिकारियों की भूमिका, कक्षा 5 के अन्त में सामान्य परीक्षा; वित्तीय प्रबंध; अध्यापक संगठनों की अपने सदस्यों की व्यावसायिक वृद्धि में भूमिका; निर्णय लेने की शैली आदि।

"समान व्यक्तियों के कार्यक्रमों" के रूप में अनिवार्यतः नियोजित यह अभिविन्यास कार्यक्रम व्याख्यान-परिचर्चाओं पर ही अधिक निर्भर रहा। अधिकांश पत्र भाग लेने वालों द्वारा ही तैयार किए गए थे और कार्यक्रम के विभिन्न अनुभागों में उनका प्रस्तुतीकरण उन्हीं के द्वारा किया गया। विभिन्न सत्रों के दौरान जो परिचर्चायें की गईं वे उन्मुक्त और स्पष्ट थीं। कार्यप्रणाली में व्यावहारिक अभ्यास और भाग लेने वालों द्वारा एन डी एम सी के नवरंग स्कूल में प्राथमिक अवस्था में पाठ्यचर्या तथा सहपाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलापों में नवाचारी कार्यक्रम के अध्ययन के लिए क्षेत्रीय वीक्षण भी सम्मिलित थे।

प्रो० मुनिस रज़ा, अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास का अध्ययन केंद्र, समाज विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रो० एम० वी० मा[illegible] अवैतनिक प्रतिष्ठित आचार्य, नीपा तथा अध्यक्ष, भारतीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संघ ने समापन भाषण दिया।

श्री सी० एल० सपरा, अध्येता नीपा इस अभिविन्यास कार्यक्रम के निदेशक थे। श्री के० जी० विरमानी, सहयोगी अध्येता तथा श्री टी० के० डी० नायर, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी नीपा ने क्रमशः कार्यक्रम समवन्यक तथा सहयोगी कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया।

2. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन से सम्बन्धित अभिविन्यास कार्यक्रम (25 मई से 12 जून, 1981)

प्रस्तावना

शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित तीन सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम (1981 की शृंखला में पहला) 25 मई से 12 जून, 1981 को आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों से 12 व्यक्तियों ने तथा संघ शासित क्षेत्र से एक व्यक्ति ने भाग लिया। राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र इस प्रकार हैं—गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली।

उद्देश्य

कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न थे; भाग लेने वालों को शैक्षिक योजना, प्रशासन और पर्यवेक्षण की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं तथा समस्याओं से परिचित करवाना, उन्हें नयी शैक्षिक प्रकृतियों तथा गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रमों से परिचित करवाना, और उन्हें शैक्षिक प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के रूप में व्यावसायिक प्रवीणता तथा प्रभावशीलता प्राप्त करने योग्य बनाना।

विषयवस्तु

उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों सम्मिलित किए गये : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन; शैक्षिक प्रबंध की संकल्पनायें तथा तकनीकें, शैक्षिक नवाचारों का प्रबंध, स्कूलों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण, स्कूल प्रांगण; अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण—जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका, प्रबंध सूचना पद्धति; मॉनिटरिंग और मूल्यांकन; शैक्षिक योजना और प्रशासन की समस्याओं को सुलझाने में अध्यापक संगठनों की भूमिका, शैक्षिक प्रशासन पद्धति तथा संस्था-स्तर पर सुधारों की संभावनायें तथा शैक्षिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संगठन।

"समान के लिए संगोष्ठी" के रूप में अनिवार्यतः नियोजित यह अभिविन्यास कार्यक्रम व्याख्यानों, पैनल तथा समूह परिचर्चाओं पर आधारित था।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो० एस० नूरुल हसन, उप-अध्यक्ष, वैज्ञानिक और

औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया। समापन भाषण डा० प्रेम कृपाल, भूतपूर्व शिक्षा सचिव, भारत सरकार तथा अध्यक्ष, यूनेस्को कार्य पालक बोर्ड ने किया।

डा० सी० एल० सपरा, अध्येता, नीपा, इस कार्यक्रम के निदेशक थे। श्री के० जी० विरमानी, सहयोगी अध्येता ने कार्यक्रम समवन्यक तथा सामान्य संवक्ता का कार्य किया। श्री टी० के० डी० नायर, अनुसंधान / प्रशिक्षण सहयोगी इस कार्यक्रम के डिजाइन तथा इसके संचालन से निकट रूप से संबंधित थे। श्री एस० एल० मीना तथा कुमारी मीना श्रीवास्तव, वरिष्ठ तकनीकी सहायकों ने भी इस कार्यक्रम को चलाने में सहायता की।

3. वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम (3-21 अगस्त, 1981)

प्रस्तावना

संस्थान ने विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के वरिष्ठ शिक्षा प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित तीन सप्ताह का एक अभिविन्यास कार्यक्रम (शृंखला में दूसरा) 3-21 अगस्त, 1981 को आयोजित किया।

उद्देश्य

कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों को शैक्षिक योजना, प्रशासन और पर्यवेक्षण की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं तथा समस्याओं से परिचित करवाना, उन्हें नयी शैक्षिक प्रकृतियों तथा गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रमों से परिचित करवाना, और उन्हें शैक्षिक प्रशासकों और पर्यवेक्षको के रूप में व्यावसायिक प्रवीणता तथा प्रभावशीलता प्राप्त करने योग्य बनाना।

विषयवस्तु

उपर्युक्त उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए गये : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन, शैक्षिक प्रबंध की संकल्पनायें तथा तकनीकें, शैक्षिक नवाचारों का प्रबंध; स्कूलों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण, स्कूल प्रांगण, अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण—जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका, प्रबंध सूचना पद्धति; मॉनिटरिंग और मूल्यांकन; शैक्षिक योजना और प्रशासन की समस्याओं को सुलझाने में अध्यापक संगठनों की भूमिका, शैक्षिक प्रशासन पद्धति तथा संस्था-स्तर पर सुधारों की संभावनायें तथा शैक्षिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संगठन।

"समान के लिए संगोष्ठी" के रूप में अनिवार्यत: नियोजित यह अभिविन्यास कार्यक्रम व्याख्यानों, पैनल तथा समूह परिचर्चाओं पर आधारित था।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो० एस० नूरूल हसन, उप-अध्यक्ष, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। समापन भाषण डा० प्रेम कृपाल, भूतपूर्व शिक्षा सचिव, भारत सरकार तथा अध्यक्ष, यूनेस्को कार्यपालक बोर्ड ने दिया।

इस कार्यक्रम में 18 व्यक्तियों ने भाग लिया। भाग लेने वाले स्कूल शिक्षा संबंधित वरिष्ठ विद्यालयी प्रशासक थे, यथा लोक शिक्षा के उप निदेशक तथा नौ राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्रों के जिला शिक्षा अधिकारी तथा समान प्रस्थिति वाले अधिकारी। जिन राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने इसमें प्रतिनिधित्व किया वे इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पांडिचेरी।

"समान के लिए संगोष्ठी" के रूप में अनिवार्यतः आयोजित यह अभिविन्यास कार्यक्रम व्याख्यान परिचर्चाओं तथा पैनल और समूह परिचर्चाओं पर आधारित था। पैनल चर्चायें निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण विषयों पर की गई, 'पाठ्यक्रम नियोजन में नयी प्रवृत्तियां' तथा 'स्कूलों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण'।

अधिक समय व्यावहारिक अभ्यास, समूह कार्य, पुस्तकालय अध्ययन और एन० सी० इ० आर० टी० तथा योजना आयोग में दौरों पर व्यतीत किया गया।

लड़कों के सरकारी स्कूल नं० 3. सरोजनी नगर में प्रारंभ किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भाग लेने वालों को प्रयत्क्ष ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए दौरों की व्यवस्था की गई : इसके अतिरिक्त भाग लेने वालों को राजधानी दिल्ली में दो प्रायोगिक स्कूलों यथा 'ओपेन स्कूल' तथा नवरंग पब्लिक स्कूल में दौरा करने का भी अवसर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर व्यावहारिक अभ्यास और समूह कार्य की व्यवस्था की गई। शैक्षिक योजना में विश्लेषणात्मक तथा प्रक्षेपण तकनीकों का अनुप्रयोग; कुछ राज्यों के वर्तमान स्थित निरीक्षण प्रपत्रों की समीक्षा तथा नया निरीक्षण प्रपत्र तैयार करना; शैक्षिक प्रबंध में मानवीय संबंध दृष्टिकोण।

डा० सी० एल० सपरा, अध्येता, नीपा इस कार्यक्रम के निदेशक थे। श्री के० जी० विरमानी सहअध्येता ने कार्यक्रम समन्वयक तथा सामान्य संवक्ता का कार्य किया। श्री टी० के० डी० नायर, अनुसंधान / प्रशिक्षण सहयोगी, श्री ए० मैथ्यू, कार्यक्रम सहयोगी तथा एस० एल० मीना, वरिष्ठ तकनीकी सहायक ने सहयोगी कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका निभाई। श्री चरण जीव मेहता, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी ने एक क्षेत्रीय दौरे में संकाय के प्रतिनिधि का कार्य किया।

4. स्कूल प्रबन्ध पर कार्यशाला (बम्बई : 2-7 नवम्बर, 1982)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के सहयोग से परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी (ए. इ. इ. एस.) द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के प्रधानाचार्यों, उप-प्रधानाचार्यों तथा वरिष्ठ स्नातकोत्तर अध्यापकों के लिए स्कूल प्रबंध पर एक सप्ताह की कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में भारत के विभिन्न भागों से 19 व्यक्तियों ने भाग लिया जिसमें परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी के स्कूलों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थानीय स्कूल भी सम्मिलित थे। इस कार्यशाला का आयोजन परमाणु ऊर्जा माध्यमिक विद्यालय, विद्यार्थी मार्ग, अणुशक्ति नगर बम्बई-400094 में किया गया।

उद्देश्य

कार्यशाला के निम्न उद्देश्य थे : शैक्षिक प्रबंध में नयी संकल्पनाओं का गुण विवेचन करना, संस्था के एक प्रभावी नेता के रूप में स्कूल प्रधान अध्यापकों के लिए अपेक्षित उचित भूमिकाओं, कौशलों तथा ज्ञान की संकल्पना करना तथा संवर्धित स्कूल प्रबंध के लिए क्रिया योजना का निर्माण करना।

विषयवस्तु

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई :

(1) शैक्षिक प्रबंध—एक विहंगावलोकन; (2) प्रभावी प्रधानाचार्य का एक मॉडल; (3) स्टाफ विकास; (4) नेतृत्व व्यवहार; (5) नवाचारों का प्रबंध; (6) प्रधानाचार्य की प्रबंध संबंधी भूमिका; (7) संचार; (8) सह पाठ्यचर्या क्रियाकलापों का प्रबंध; (9) माइक्रो स्तर पर शिक्षा में समूह गतिकी; (10) अपने ही स्कूल की नैदानिक खोज; (11) मानवीय संबंध, (12) क्रिया योजना।

यह कार्यशाला अनिवार्यतः ए. इ. इ. एस. के प्रधानाचार्यों को अपने व्यावसायिक अनुभवों को समानता के आधार पर आपस में एक दूसरे तथा क्षेत्र से आए विशेषज्ञों और अन्य ज्ञानविद् व्यक्तियों से आदान प्रदान करने के लिए एक फोरम के रूप में

आयोजित की गई थी। यह कार्यशाला अधिकांशत: व्याख्यान परिचर्चाओं तथा व्यावहारिक अभ्यासों पर आधारित थी। इनके अतिरिक्त इसमें समूह तथा वैयक्तिक कार्य भी किया गया। भाग लेने वालों से अपने व्यावसायिक वृत्ति के दौरान शैक्षिक क्षेत्र में प्रारम्भ किए गए नवाचारों तथा प्रयोगों पर एक संक्षिप्त टिप्पण तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य सफलता के कारणों की पहचान तथा असफलता से सीख प्राप्त करना था। भाग लेने वालों से अपने पसंद के क्षेत्र/क्रियाकलापों के क्षेत्रों के लिए क्रिया योजना भी तैयार करने को कहा गया। उनसे स्कूल जीवन के उस क्षेत्र की पहचान करने का भी अनुरोध किया गया जिसे वे कमजोर समझते थे और जिन पर उनको ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता थी।

भाग लेने वालों से विचार विनिमय के लिए नीपा के संकाय सदस्यों तथा ए०इ०इ० एस० स्कूलों के विशेषज्ञ व्यक्तियों के अतिरिक्त शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों से अतिथि वक्ताओं को भी इस कार्यशाला में नियंत्रित किया गया। अधिकाशत: स्थानीय कालिजों तथा अन्य ख्याति प्राप्त संस्थाओं से इन वक्ताओं को निमंत्रित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वालों को शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के अनुभवों तथा कार्यों से परिचित होने का अवसर प्रदान करना था।

भाग लेने वालों को शैक्षिक योजना और प्रशिक्षण के विषय में अधुनातन पुस्तकों से परिचित करने के लिए टाटा मैकग्रोहिल प्रकाशन कम्पनी लिमिटेड के सहयोग से न्यू पापुलर बुक शाप, आई. टी. आई. कैम्पस बम्बई में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में लगभग 150 पुस्तकें प्रदर्शन के लिए रखी गई।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री एम.ए. हादी, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इन्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा 2 नवम्बर, 1982 को किया गया। डा. आर. पी. सिंहल, परामर्शदाता, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान इस कार्यशाला के निदेशक थे। डा. एन. एम. भागिया, अध्येता, नीपा तथा एस. शेषाद्री, प्रधानाचार्य, ए. इ. इ. एस. बम्बई, ने सहयोगी निदेशक का कार्य किया; श्री चरणजीव सेहता, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी, नीपा ने कार्यक्रम समन्वयक तथा सामान्य संवक्ता का कार्य किया।

5. स्कूलों के मुख्य अध्यापकों के लिए स्कूल प्रबन्ध से सम्बन्धित अभिविन्यास कार्यक्रम (नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1980—जनवरी, 1982)

प्रस्तावना

संस्थान ने केंद्रीय तिबेतन स्कूल प्रशासन (सी टी एस ए) तथा केंद्रीय विद्यालय संस्थान (के वी एस) के सहयोग से उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए स्कूल प्रबंध से संबंधित 10 दिन का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कायक्रम का उद्घाटन प्रो० शिव कुमार मित्रा, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली ने 31 दिसम्बर, 1981 को किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय के 32 प्रधानाचार्यों तथा तिबेतन केंद्रीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा महाचार्य ने भाग लिया।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : (i) स्कूल प्रबंध में मुख्य संकल्पनाओं का गुण विवेचन; (ii) प्रभावी संस्थागत नेतृत्व के रूप में एक स्कूल प्रधानाचार्य के लिए अपेक्षित उचित भूमिकाओं, कौशलों तथा ज्ञान की संकल्पना; तथा स्कूल प्रबंध में सुधार लाने के लिए क्रिया-योजना का निर्माण।

विषयवस्तु

कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया : स्कूल प्रबंध : एक विहंगावलोकन; प्रधानाचार्य की प्रबंधकीय भूमिका तथा प्रभावी प्रधानाचार्य का एक मॉडल; नेतृत्व व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता, पर्यवेक्षण, स्टाफ का विकास, संचार, संसाधन का प्रबन्ध : वित्त; संसाधन का प्रबन्ध : समय; स्कूल शिक्षा में गैर-मौद्रिक आगम; स्कूलों में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का प्रबन्ध; विद्यार्थियों का प्रबन्ध : उनकी आवश्यकतायें तथा समायोजन; किशोरों की समस्यायें, स्कूल समुदाय संबंध; नवाचारों का प्रबंध; संस्थागत नियोजन; क्रिया नियोजन।

संस्थान के संकाय के अतिरिक्त कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य विशेषज्ञ व्यक्तियों में शिक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय विद्या संस्थान, केन्द्रीय तिबेतन स्कूल प्रशासन के अनुभवी योजनाकार तथा प्रशासक और दिल्ली के उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य सम्मिलित थे।

कार्यक्रम का संचालन व्याख्यान, परिचर्चाओं, पैनल परिचर्चाओं तथा समूह कार्य द्वारा किया गया। भाग लेने वालों को कुछ सत्रों में वक्ता द्वारा दिए गए विषय पर कुछ अभ्यास भी दिए गए। उन्होंने अपने-अपने स्कूलों के लिए क्रिया योजनायें भी तैयार कीं।

इस कार्यक्रम का संचालन डा० आर० पी० सिंहल, परामर्शदाता तथा डीन (प्रशिक्षण) नीपा के पूर्ण मार्गदर्शन में किया गया। डा०एन०एम० भागिया, नीपा ने कार्यक्रम निदेशक का तथा डा०आर०एस० शर्मा, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी, नीपा ने कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया। श्री एस. एल. मीना, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, नीपा इस कार्यक्रम सहयोगी के थे।

6 संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के निरीक्षण अधिकारियों तथा स्कूलों के मुख्य अध्यापकों के लिए स्कूल प्रबन्ध से सम्बन्धित अभिविन्यास कार्यक्रम (5-13 फरवरी, 1982)

प्रस्तावना

संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में निरीक्षण अधिकारियों तथा स्कूल के मुख्य अध्यापकों के लिए स्कूल प्रबंध से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वर्ष 1980 में पांडिचेरी क्षेत्र की सरकार ने नीपा से अनुरोध किया। इसके फलस्वरूप संस्थान ने पांडिचेरी सरकार के शिक्षा विभाग के सहयोग से 8-13 फरवरी, 1982 को उपर्युक्त कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधान आचार्यों, उच्च स्कूलों के मुख्य अध्यापकों, शिक्षा उप-निरीक्षकों तथा केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों सहित 37 व्यक्तियों ने भाग लिया।

उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : (i) भाग लेने वालों को प्रशासनिक और वित्तीय नियमों से अवगत करवाना; (ii) शिक्षा के क्षेत्र में नई प्रवृत्तियों से परिचित करवाना; तथा (iii) भाग लेने वालों को स्कूल शिक्षा में गुणत्ता सुधार उपलब्धि की दृष्टि से व्यावसायिक प्रवीणता तथा प्रभावशीलता प्राप्त करवाना।

विषयवस्तु

भाग लेने वालों को कुछ विशिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए दो समूहों में विभाजित किया गया—एक में स्कूलों के मुख्य अध्यापक सम्मिलित थे और दूसरे में निरीक्षण अधिकारी. तथापि, सामान्य अभिविन्यास के लिए सभी भाग लेने वालों ने अन्य सत्रों में एक एकक समूह के रूप में भाग लिया। निरीक्षण अधिकारियों के प्रयोग के लिए एक निरीक्षण प्रपत्र का निर्माण इस कार्यक्रम का विशिष्ट लक्षण था। भाग लेने वालों द्वारा यह प्रपत्र तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त भाग लेने वाले 33 व्यक्तियों ने शैक्षिक विषयों से संबंधित पुस्तकों का सार भी तैयार किया।

कार्यक्रम के अंत में भाग लेने वालों ने संघ शासित पांडिचेरी में शैक्षिक प्रबंध से संबधित सिफारिशें प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम का मूल्यांकन नीपा द्वारा बनाये गए प्रपत्र के आधार पर किया गया।

7. हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए कार्मिक और वित्तीय प्रबन्ध से सम्बन्धित अभिविन्यास पाठ्यक्रम (23-27 फरवरी, 1982, नई दिल्ली)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए कार्मिक तथा वित्तीय प्रबंध से संबंधित एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया। स्कूल शिक्षा निदेशालय, हरियाणा सरकार की परामर्शता से इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया था। इस पाठ्यक्रम में उच्च माध्यमिक स्कूलों के पांच प्रधानाचार्यों, पांच वरिष्ठ जिला शिक्षा अधिकारियों, दो उप जिला शिक्षा अधिकारियों तथा हरियाणा शिक्षा विभाग के छः अन्य अधिकारियों सहित 18 व्यक्तियों ने भाग लिया।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : भाग लेने वालों को कार्मिक तथा वित्तीय प्रबंध की नयी संकल्पनाओं, विधियों तथा तकनीकों से परिचित करवाना; भाग लेने वालों को हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग पर लागू होने वाले सेवा नियमों पर तथा आचरण वित्तीय नियमों पर चर्चा करने योग्य बनाना; भाग लेने वालों को शैक्षिक प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के रूप में व्यावसायिक प्रवीणता और प्रभावशीलता प्राप्त करने योग्य बनाना।

विषयवस्तु

पाठ्यक्रम में जिन विषयों पर चर्चा की गई, वे इस प्रकार हैं : कार्मिक प्रबंध विस्तार और मामले, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व; जॉब विश्लेषण तथा नियोक्ता मूल्यांकन; सेवा और आचरण नियम; स्टाफ बैठकों का आचरण; निर्णय लेने की क्षमता; संघर्ष प्रबंध; स्टाफ विकास; एक पर्यवेक्षक की भूमिका, अध्यापकों और नियोक्ताओं का अभिप्रेरण; शैक्षिक पर्यवेक्षण; वित्तीय प्रबंध नियम; अंत: कार्मिक संबंध तथा संगठन, नियतन, गैर-मौद्रिक आगमों के विशेष संदर्भ में संसाधनों का उपयोग।

पाठ्यक्रम अनिवार्यत: समानों की संगोष्ठी के रूप में आयोजित किया गया और मुख्यत: व्याख्यान-परिचर्चाओं, समूह कार्य-केसों पर आधारित था। भाग लेने वालों को आपस में विचार विनिमय करने के साथ संस्थान के संकाय, और हरियाणा सरकार के

शिक्षा विभाग सहित अन्य संगठनों के शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने का लाभ प्राप्त हुआ।

इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन हरियाणा सरकार के गणमान्य मंत्री चौधरी देश राज ने किया। प्रो० मुनिस रज़ा, निदेशक, नीपा ने 27 फरवरी, 1982 को समापन भाषण दिया।

श्री के०जी० विरमानी, सहयोगी अध्येता, ने कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया। डा० सी० एल० सपरा, अध्येता तथा डा० (श्रीमती) राधा शर्मा, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी ने सहयोगी कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया और श्री एस०एल० मीना, वरिष्ठ तकनीकी सहायक ने इनकी सहायता की।

8. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास संगोष्ठी (6-11 अप्रैल, 1981)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय संस्थान ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से 6-11 अप्रैल, 1981 को प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए ग्यारहवीं अभिविन्यास संगोष्ठी आयोजित की। इससे पहले 10 संगोष्ठियां आयोजित करने के अतिरिक्त राज्य स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों के लिए संस्थान द्वारा चार संगोष्ठियां आयोजित की गईं। इन संगोष्ठियों में सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से कुल 410 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त राजस्थान तथा दिल्ली प्रशासन से 24 अधिकारियों ने भी इस ग्यारहवीं संगोष्ठी में भाग लिया।

उद्देश्य

संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य थे : प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की संकल्पनात्मक रूपरेखा तथा उसके क्रियान्वयन के उपागम पर चर्चा करना ; कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला और परियोजना स्तरीय कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा कार्यों को निश्चित करना तथा उनकी पहचान करना ; मैक्रो तथा माइक्रो स्तर पर प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम की नियोजन की प्रक्रिया, यांत्रिकी तथा तकनीकों को समझना तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तकनीकी यंत्र और अकादमिक सहायताओं को समझना।

विषयवस्तु

कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई :

(i) कार्यक्रम के उद्देश्य तथा उसके क्रियान्वयन के लिए अपनाई जाने वाली युक्तियां ;

(ii) कार्यक्रम प्रबंध—जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों / परियोजना अधिकारियों की भूमिका ;

(iii) विकासशील एजेंसियों से संबद्धता ;

(iv) अन्य एजेंसियों का सहयोग ;

(v) माइक्रो और मैक्रो स्तरों पर नियोजन ;

(vi) पाठ्यचर्या तथा वस्तुयें;

(vii) उत्तर साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम ;

(viii) कार्मिकों का प्रशिक्षण ; तथा

(ix) मॉनिटरिंग, मूल्यांकन तथा प्रतिपुष्टि।

इस संगोष्ठी में प्रौढ़ शिक्षा का विकासात्मक क्रियाकलापों से समाकलन की व्यावहारिक समस्याओं पर मुख्य रूप से बल दिया गया। निरक्षर स्त्रियों को शिक्षित करने की विशेष समस्याओं को भी संगोष्ठी में वरीयता प्रदान की गई।

संगोष्ठी का नियोजन अनिवार्यतः समान व्यक्तियों के कार्यक्रम के रूप में किया गया जिससे भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति संगोष्ठी के विचार-विमर्श कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले सके। इसलिए भाग लेने वालों के सत्र में निम्नलिखित अभिविन्यास कार्य प्रणाली को अपनाया गया : अनुभवों का आदान-प्रदान ; पैनल परिचर्चायें, समूह कार्य ; राष्ट्रीय साधन केन्द्र में दौरा, यथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ; तथा दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में दौरे।

प्रो० एस० सी० दुबे, राष्ट्रीय अध्येता, आई० सी० एस० एस० आर० ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया। श्री जे० वीरराघवन, कार्यकारी निदेशक, नीपा ने जो संगोष्ठी निदेशक भी थे, समापन सत्र की अध्यक्षता की। डा० सी० बी० पद्मनाभन, अध्येता नीपा, श्री डी० वी० शर्मा, संयुक्त निदेशक, डी० ए० इ० तथा डा० के०डी० शर्मा सहयोगी अध्येता, नीपा ने कार्यक्रम समन्वयकों के रूप में सहायता प्रदान की।

9. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए पहला पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (22-27 जून, 1981)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डी० ए० ई०), शिक्षा मंत्रालय ने भारत के विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 20 जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों / परियोजना अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया।

पाठ्यक्रम अनुवर्ती और साक्षरता पश्च प्रकारताओं पर गंभीर सोच विचार करने के लिए बनाया गया था। इस पक्ष पर विशेष रूप से बल दिया गया था क्योंकि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना था कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अर्द्ध अथवा नव साक्षरों के लिए प्रभावी साक्षरता अनुवर्ती/साक्षरता प्रश्च क्रियाकलापों को आयोजित करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे :—

नियोजन और प्रशासन; प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों पर किए गए वाचारी अभ्यासों पर अनुभवों का आदान-प्रदान; समन्वय, अतीत से सीखना, संभावित जेंसियों, जिनसे समन्वय आवश्यक है, की पहचान तथा इसको प्राप्त करने की संभावित क्तियां, तथा अनुवर्तन ; वर्तमान प्रस्थिति और इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए विध उपागमों / मॉडलों का संश्लेषण।

विषयवस्तु

उपर्युक्त उद्देश्य की उपलब्धि के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को म्मिलित किया गया :

भाग लेने वालों से संबंधित मुख्य मामलों तथा क्षेत्रों की पहचान; नये संदर्भ में जला शिक्षा अधिकारियों की भूमिकायें, उत्तरदायित्व तथा कार्य; साक्षरता पश्च स्थायें तथा मामले (उद्देश्य, सामग्री, वितरण पद्धति, विविध कार्यकर्ताओं की भूमिका, दि); साक्षरता पश्च के लिए नियोजन; विकास एजेंसियों द्वारा अनुवर्तन; कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण (प्रशिक्षक / पर्यवेक्षक)।

पाठ्यक्रम, पैनल तथा समूह परिचर्चाओं पर आधारित था। भाग लेने वालों का कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से रुचि प्रगट करना तथा उनका आपस में तथा चर्चाओं में भाग लेने और उनके संचालन के लिए निमंत्रित विशेषज्ञ व्यक्तियों से विचार विनिमय करना ही कार्यक्रम की प्रभाविता का परिणाम था। भाग लेने वालों के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में क्षेत्र दौरों की भी व्यवस्था की गई।

श्री जे० वीरराघवन, कार्यपालक निदेशक, नीपा ने पाठ्यक्रम निदेशक का कार्य किया। डा० के० डी० शर्मा, सहयोगी अध्येता, नीपा तथा श्री डी० वी० शर्मा, संयुक्त निदेशक डी० ए० ई० कार्यक्रम के समन्वयक थे। श्री अरुण मेहता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, नीपा इस कार्यक्रम के सहयोगी समन्वयक थे।

10. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए क्षेत्र अभिविन्यासी प्रशिक्षण कार्यक्रम (नई दिल्ली, 23 नवम्बर 5 दिसम्बर, 1981)

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के अनुरोध पर प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से नीपा द्वारा दो सप्ताह की अवधि का एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्षण क्षेत्र में हो रहे कार्यक्रमों में किसी एक कार्यक्रम की सामर्थनताओं और कमियों को पहचानने के लिए भाग लेने वालों तथा संकाय सदस्यों द्वारा 2 दिन का गहन क्षेत्र कार्य था। 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में से 24 व्यक्तियों से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

उद्देश्य

आधार स्तर पर उपलब्ध सहायता के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा के संकल्पनात्मक पैरामीटर तथा, उसके क्रियान्वयन यंत्र के ज्ञान का विकास करना इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था।

विषयवस्तु

प्रयोज्य कार्यक्रम को 5 अलग-अलग प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया जो इस प्रकार हैं: प्रलेखों का अध्ययन, विशेष रूप से (i) प्रौढ़ शिक्षा के 50 वर्ष; (ii) भारत सरकार की विकास योजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा-घटकों के सार; (iii) कुछ चुने हुए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के शीघ्रता से किए हुए मूल्यांकन अध्ययनों के संक्षेप; हरियाणा राज्य में मुड़गांव ब्लाक के 80 चुने हुए ग्रामों के कार्यक्रमों का क्षेत्र अध्ययन; भाग लेने वालों के बीच उन्मुक्त और स्पष्ट परिचर्चायें तथा आपसी विचार विमर्श; संकाय और कार्यक्रम के मध्य स्तरीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ता, प्रौढ़ शिक्षा से संबंध रखने वाले विकास विभागों के अधिकारियों से परिचर्चा और वार्तालाप; उपर्युक्त चार अवस्थाओं में प्राप्त अनुभवों का संश्लेषण तथा समूह रिपोर्टों की तैयारी।

इस प्रकार भाग लेने वाले, प्रौढ़ क्षिक्षा के सिद्धांतों के ज्ञान के आधार पर तथा क्षेत्रीय स्थिति के अध्ययन के दौरान व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर अपने निर्णयों का निर्माण कर सके।

कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो० ए० जे० किदवई, उपकुलपति जामिया मिलिया उसमानिया, दिल्ली ने किया। श्री जे० डी० शर्मा, निदेशक, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ ने समापन भाषण दिया।

श्री जे० वीरराघवन, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान इस पाठ्यक्रम के निदेशक थे। डॉ० (श्रीमती) शफी ने कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया।

11. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए दूसरा पुनश्चर्या कार्यक्रम (नई दिल्ली : 18-23 जनवरी, 1982)

प्रस्तावना

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के सहयोग से अप्रैल, 1979 को जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रारंभ किया। इन कार्यक्रमों की योजना बनाते समय इस की भी कल्पना कर ली गई थी कि सभी जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों को क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् तथा प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने के लिए अन्य प्रशिक्षणों से गुजरना होगा। क्षेत्र में परियोजना अधिकारियों द्वारा समस्याओं का सामना करने पर सहायक शिक्षा अधिकारी को एक नये पद की उत्पत्ति की आवश्यकता समझी गयी, विशेष रूप से उस समय जब कि जिला स्तर पर अन्य एजेंसियों से समन्वय करने के लिए कुछ निर्णयों का लिया जाना आवश्यक हो गया था। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का जैसे-जैसे क्रियान्वयन होता गया, तकनीकी सहायता के साथ-साथ उसके प्रबंध में भी अतिरिक्त आगमों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। अतः यह आवश्यक समझा गया कि इन अधिकारियों के लिए अपनी सफलताओं और असफलताओं का पुनरावलोकन करने के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्र में नयी चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियां उत्पन्न करने के लिए एक उचित पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किया जाए। विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों से 12 व्यक्तियां ने 13-23 जनवरी, 1982 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

उद्देश्य

पुनश्चर्या कार्यक्रम की योजना निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए बनाई गयी थी :

(1) जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों की पहले से विकसित क्षमताओं के प्रकाश में उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण के पश्चात् किए गए कार्यों का पुनरावलोकन ;

(2) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के दौरान अनुभव की गई समस्याओं का प्रकारताओं को समझना तथा जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों द्वारा इन समस्याओं का हल ढूंढ़ना ;

(3) आयोजित किए गए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की गुणता तथा इस गुणता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए तथा उनका मूल्यांकन किया जाए ;

(4) वर्तमान समय में आयोजित अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों में तथा उत्तर साक्षरता के दौरान आने वाली समस्याओं अथवा प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् आने वाली समस्याओं को पहचानना, तथा ;

(5) वर्तमान स्थित संसाधनों के अंतर्गत साक्षरता पश्च कार्यक्रमों के लिए अति उचित उपागम के विषय में पता लगाना और उन पर चर्चा करना ।

विषयवस्तु

इस कार्यक्रम में अधिकांशतः पैनल परिचर्चायें तथा समूह कार्य ही प्रमुख थे । पैनल के सदस्यों को उन क्षेत्रों से लिया गया था जिनका साक्षरता पश्च कार्यक्रमों को आयोजित करने में प्रत्यक्ष प्रभाव था । ये विशेषज्ञ व्यक्ति कृषि, विस्तार, जनसंख्या शिक्षा, जनसंपर्क साधन, प्रकाशन और मुद्रण, योजना और मूल्यांकन क्षेत्रों से निमंत्रित किए गए थे। इन विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में तथा मुद्रण सामग्री के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके भाग लेने से कार्यक्रम अत्यधिक समृद्ध हो गया ।

भाग लेने वालों को दो समूहों में विभाजित किया गया । प्रत्येक समूह को निम्न-लिखित तीन क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए कहा गया :

(1) भारत सरकार द्वारा सुझाई गयी साक्षरता पश्च रीतियों—कहां तक ये माडल साध्य पाए गए हैं और उनमें सुधार लाने के लिए किन संशोधनों की आवश्यकता है ? इसके अतिरिक्त भाग लेने वालों को निम्नलिखित पर सुझाव देने की स्वतन्त्रता दी गई हैं : साक्षरता पश्च कार्यक्रमों के लिए न या उपागम ;

(2) साक्षरता पश्च सामग्री की तैयारी और उनकी प्राप्ति—इसमें आवश्यक सामग्री की प्रकारता पर चर्चा, तथा इस सामग्री को प्राप्त करने के विविध स्रोत तथा इस सामग्री को रूपांतरित तथा प्रयोग किए जाने की विधियां सम्मिलित हैं ; तथा

(3) सीखने वालों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की गई विधियां तथा अभी तक

दिए गए परीक्षणों से उपलब्धि के स्तर का प्रमाण और इनको अत्यधिक प्रायोगिक और उपयोगी बनाने में सुधारों के प्रकार ।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो० मुनिस रज़ा, निदेशक नीपा ने किया।

यह कार्यक्रम डा० आर०पी० सिंहल, परामर्शदाता तथा डीन (प्रशिक्षण) नीपा तथा श्री डी० वी० शर्मा, संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण तथा जनसंख्या एकक, प्रौढ़ निदेशालय के समग्र मार्गदर्शन में किया गया । श्रीमती आर० एस० शफी, नीपा और श्री वी० के० अस्थाना प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने कार्यक्रम समन्वयकों के रूप में सहायता प्रदान की।

12. हरियाणा के महाविद्यालय के प्रधान आचार्यों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम (25 मई से 6 जून, 1981)

प्रस्तावना

हरियाणा सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने हरियाणा के महाविद्यालय प्रधानाचार्यों के लिए 25 मई से 6 जून, 1981 को शैक्षिक योजना और प्रशासन से सम्बन्धित एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कुछ चुने हुए महाविद्यालयों से 24 प्रधानाचार्यों ने भाग लिया।

उद्देश्य

प्रधानाचार्यों की प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यकताओं के अनुसार हरियाणा सरकार की सलाह से यह कार्यक्रम बनाया गया था। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे--सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा की समस्याओं और संभावनाओं के संबंध में तथा सामाजिक परिवर्तन के एक उपस्कर के रूप में महाविद्यालय-कार्य की संभावना का पता लगाने और उपर्युक्त संदर्भ में राष्ट्र तथा साथ ही राज्य की शैक्षिक नीतियों की जांच से संबंधित समस्याओं से प्रधानाचार्यों को अवगत करवाना, उन्हें संस्थागत नियोजन की विविध तकनीकों तथा प्रबंध की निर्णय लेने की शैली में अधुनातन विकास से परिचित करवाना ; वित्तीय प्रबंध और विद्यार्थी सेवाओं का प्रबंध; उच्च शिक्षा के स्तर से संबंधित समस्याओं की जांच तथा स्तरों में सुधार के लिए उपाय सुझाना, उन्हें विद्यार्थी, अध्यापकों तथा संस्था के मूल्यांकन की विविध तकनीकों से परिचित करवाना, तथा औपचारिक और अनौपचारिक संपर्कों द्वारा सहयोगी व्यवसायिकों के अनुभव से सीखने का अवसर प्राप्त करवाना।

विषयवस्तु

कार्यक्रम के दौरान चर्चा के लिए लिए गए अनेक मामलों और समस्याओं को विस्तृत रूप से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है : सामाजिक-आर्थिक ढांचे में उच्च शिक्षा; सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उच्च शिक्षा की समस्यायें तथा संभावनायें, राष्ट्रीय और राज्यीय नीति और शैक्षिक विकास, उच्च शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन; उच्च शिक्षा में विश्व प्रवृत्तियां तथा छठीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा; नियोजन और संस्थागत प्रबंध की तकनीकें, उच्च शिक्षा के स्तर; विद्यार्थी सेवायें, कालिज और समुदाय; वित्तीय प्रबंध; संस्थागत निकाय—विद्यार्थी और अध्यापक संघ; मूल्यांकन; परीक्षा सुधार;

अध्यापक और विद्यार्थियों के मूल्यांकन की तकनीकें; तथा कालिज के प्रबंध तथा उसके दिन प्रतिदिन के प्रशासन में निर्णय लेने के अभ्यास।

कार्यक्रम का संचालन मुख्यतः व्याख्यान चर्चाओं द्वारा ही किया गया। तथापि किन्हीं महत्वपूर्ण मामलों पर पैनल परिचर्चाओं की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के बाद के अर्द्ध सत्र में भाग लेने वालों को स्थानीय कालिजों के प्रधानाचार्यों से अनौपचारिक रूप से विचार विनिमय करने का अवसर प्रदान किया गया। इस उद्देश्य के लिए स्थानीय कालिजों के प्रधानाचार्यों से कालिज नियोजन और प्रशासन से संबंधित विविध विषयों और मामलों पर पूरे दिन की अनौपचारिक चर्चाओं के लिए दो प्रधानाचार्यों को बुलाने के लिए अनुरोध किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो० एस० नूरुल हसन, उप अध्यक्ष, सी एस आई आर द्वारा किया गया और समापन हरियाणा सरकार के गणमान्य शिक्षा मंत्री चौधरी देश राज के समापन भाषण से हुआ।

डा. जी. डी. शर्मा, अध्येता नीपा इस कार्यक्रम के निदेशक थे तथा डा. आर. एस. शर्मा, अनुसंधान प्रशिक्षण सहयोगी, नीपा ने कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया। श्रीमती उषा नायर ने सामान्य संवक्ता का कार्य किया।

13-15 कालिज के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबन्धित अभिविन्यास कार्यक्रम (2-21 नवम्बर, 1981 ; 30 नवम्बर - 19 दिसम्बर, 1981 तथा 8-27 फरवरी, 1982)

प्रस्तावना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परामर्शता से संस्थान ने कालिज प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित तीन-तीन सप्ताह वाले अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए। महिला प्रधानाचार्यों के लिए पहला अभिविन्यास कार्यक्रम 2-21 नवम्बर, 1981 को, दूसरा 30 नवम्बर-19 दिसम्बर, 1981 को तथा तीसरा 8-27 फरवरी, 1982 को आयोजित किया गया।

उद्देश्य

अभिविन्यास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे : (i) भाग लेने वालों को भारत में उच्च शिक्षा, विशेष रूप से कालिज शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों तथा समस्याओं का एक विहंगावलोकन प्राप्त करवाना; (ii) उन्हें अध्यापन, सीखने तथा शिक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के वैकल्पिक उपागमों से परिचित करवाना, (iii) उन्हें व्यक्तियों तथा संस्थाओं के मूल्यांकन के कौशलों को प्राप्त करने योग्य बनाना; (iv) उन्हें वर्तमान निष्पत्ति में सुधार करने के लिए तथा स्टाफ को नयी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के लिए तैयार करने के लिए एक परिवर्तन एजेंट के रूप में कार्य करने योग्य बनाना; (v) प्रभाव कालिज-समुदाय अन्योन्यक्रिया का संवर्द्धन; तथा (vi) भाग लेने वालों को कालिज के प्रशासन में नियोजन और प्रबंध की आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से अवगत करवाना।

विषयवस्तु

इन उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए विषयों को तीन विस्तृत शीर्षकों में बांटा गया; यथा, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि; अकादमिक कार्यक्रम – पाठ्यचर्या का प्रबंध, अध्यापक, विद्यार्थी, अध्यापन, सीखना और परीक्षा; कालिज और समुदाय, प्रबंध - परम्परायें और नवाचार। कार्यक्रम के दौरान उपरोक्त विषयों पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम के अकादमिक और व्यावसायिक विषयवस्तु में निम्न विषय सम्मिलित थे : भारत में उच्च शिक्षा की समस्यायें तथा संभावितायें; भारत में शैक्षिक नियोजन—एक

विहंगावलोकन; शैक्षिक नियोजन में मूल संकल्पनायें तथा तकनीकें; कमज़ोर वर्ग को शिक्षित करना; उच्च शिक्षा और रोज़गार; महिलाओं की उच्च शिक्षा; समस्यायें और मामले; भारतीय उच्च शिक्षा का वित्तीयन, कालिज़ वित्त का प्रबंध, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उच्चशिक्षा के स्तरों में संवर्धन; स्वायत्तता प्राप्त कालिज; संस्थागत नियोजन; पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना; पाठ्येतर क्रियाकलापों का प्रबंध; बैठकों, संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं का संचालन; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा संकाय विकास; संकाय का निष्पत्ति मूल्यांकन; कालिजों में अध्यापक संघ की भूमिका; विद्यार्थी-अभिप्रेरणा तथा विद्यार्थी-अशांति; विद्यार्थियों की सेवाओं का प्रबंध; उच्च शिक्षा में अध्यापन की संवर्धित तकनीकें; यू जी सी और परीक्षा सुधार; परीक्षा सुधारों का विहंगावलोकन; उपचारात्मक अध्यापन; कालिज तथा समुदाय अन्योन्य क्रिया, कालिजों में राष्ट्रीय सेवा योजना; राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कालिजों की भूमिका; कालिजीय समाकलित ग्रामीण विकास की भूमिका; परिवर्तन का प्रबंध; कालिज प्रशासन में मानवीय कारक—एक समूह अभ्यास; निर्णय लेने की शैली; शैक्षिक प्रबंध में संचार की भूमिका; दल निर्माण; समय के प्रबंध में नवाचार; कालिजों की प्रशासनिक समस्यायें; कालिज का स्वमूल्यांकन; क्रिया योजना।

अध्ययन सामग्री

भाग लेने वालों में सटिप्पण ग्रंथसूची सहित चुनी हुई पठन सामग्री वाले दो पुस्तक खंडों का वितरण किया गया। पाठ्यक्रम के दौरान विषयों से संबंधित कुछ लेख भी वितरित किए गए।

कार्यप्रणाली

व्याख्यान-परिचर्चाओं के अतिरिक्त, कुछ चुने हुए विषयों पर पैनल परिचर्चायें भी की गयीं। प्रत्येक व्याख्यान परिचर्चा सत्र से एक उद्घाटन वक्ता था और परिचर्चा के लिए प्राप्त समय दिए जाने के प्रत्येक प्रयत्न किए गए। भाग लेने वालों की रुचि तथा उनकी विशेषज्ञ व्यक्तियों से अन्योन्य क्रिया के कारण कार्यक्रम प्रभावी सिद्ध हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना आयोग, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय जैसी एजेंसियों तथा विविध व्यावसायिक क्षेत्रों से अनुभवी प्रशासकों को इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ व्यक्तियों के रूप में आमंत्रित किया गया। भाग लेने वालों को चंडीगढ़ तथा दिल्ली में अच्छे कालिजों के कार्य करने के तरीकों के प्रेक्षण का भी अवसर प्रदान किया गया। भाग लेने वाले प्रत्येक समूह ने अपने प्रेक्षणों तथा मेजवान कालिज के स्टाफ और प्रधानाचार्यों से हुई चर्चाओं की एक रिपोर्ट तैयार की।

भाग लेने वाले

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 24 महिला प्रधामाचार्यों सहित 90 प्रधानाचार्यों ने तीन अभिविन्यास कार्यक्रमों में भाग लिया। इसका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

पहला कार्यक्रम : 2-21 नवम्बर, 1981	33 भाग लेने वाले
दूसरा कार्यक्रम : 30 नवम्वर-19 दिसम्बर, 19 1	24 भाग लेने वाले
तीसरा कार्यक्रम : 6-27 फरवरी, 1982	33 भाम लेने वाले

डा० आर० एन० चौधरी, अध्येता ने इन पाठ्यक्रमों में कार्यक्रम निदेशक का कार्य किया।

16. यू एस इ एफ आई विश्वविद्यालय प्रशासक परियोजना, 1982 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका जाने वाले कालिज के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (नई दिल्ली : 29 मार्च 1 अप्रैल, 1982)

प्रस्तावना

यू एस इ एफ आई के अनुरोध पर नीपा द्वारा यू एस इ एफ आई विश्वविद्यालय प्रशासक परियोजना, 1982 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका जाने वाले 5 कालिज प्रधानाचार्यों के लिए छठा प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों को भारत में उच्च शिक्षा के विकास से अवगत करवाना, उन्हें संयुक्त राज्य अमरीका में उच्च शिक्षा पैटर्न से परिचित करवाना तथा भारत और अमरीका में उच्च शिक्षा के विकास में अद्यतन प्रवृत्तियों की तुलना करना, तथा वर्तमान ढाँचे के अंतर्गत संभावित शैक्षिक नवाचारों पर विचार विमर्श करना।

विषयवस्तु

कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए गए :

अमरीकी उच्च शिक्षा—पुनरावलोकन तथा भविष्य ; उच्च शिक्षा में अमरीकी शब्दावली; वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा; संकाय विकास और संकाय मूल्यांकन; विद्यार्थी सेवा; अनुभवों का आदान प्रदान; कालिज प्रशासन की समस्यायें, कालिज समुदाय। भूतपूर्व विद्यार्थियों के संघ की अन्योन्य क्रिया तथा संकाय विद्यार्थी संबंध।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अंत:शास्त्रीय आधार पर किया गया था। संस्थान के संकाय के अतिरिक्त यू० एस० ई० एफ० आई० तथा अन्य ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विशेषज्ञों को निमंत्रित किया गया था।

17. हरियाणा के लिए शैक्षिक मानकों परकार्यशाला (2-4 अप्रैल, 1981)

प्रस्तावना

राज्य में शैक्षिक मानकों पर अध्ययन को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने 2-4 अप्रैल 1982 को हरियाणा राज्य के लिए शैक्षिक मानकों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया । इस कार्यशाला में 33 व्यक्तियों ने भाग लिया ।

उद्देश्य

हरियाणा में शैक्षिक सेवाओं के विकास और देखभाल के लिए निम्नलिखित प्रकार के मानकों पर चर्चा करना तथा उन्हें अंतिम रूप देना इस कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य थे :

(1) स्कूल खोलने और उनका उच्च स्तरीकरण के लिए मानक ;

(2) पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा हस्तकला उपस्कर समेत फर्नीचर तथा उपस्करों की व्यवस्था के लिए मानक ;

(3) अध्यापन स्टाफ की व्यवस्था के लिए मानक ;

(4) अध्यापन इतर स्टाफ की व्यवस्था के लिए मानक ;

(5) अध्यापकों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए मानक, तथा

(6) निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए मानक ।

विषयवस्तु

नीपा द्वारा यह अध्ययन हरियाणा सरकार को परामर्श सेवायें प्रदान करने के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था ।

18. जम्मू और कश्मीर के जिला और तहसील शैक्षिक नियोजन अधिकारियों के लिए दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम (13-25 अप्रैल, 1981)

प्रस्तावना

जम्मू और कश्मीर सरकार के शिक्षा विभाग के अनुरोध पर राष्ट्रीय संस्थान ने 13-25 अप्रैल 1981 को दो सप्ताह की प्रशिक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया। शैक्षिक नियोजन में सांख्यिकी तकनीकों के अनुप्रयोग के क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर के जिला और तहसील शैक्षिक नियोजन अधिकारियों के लिए शृंखला में यह दूसरी संगोष्ठी थी। जम्मू और लद्दाख डिवीजनों के 29 व्यक्तियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया।

उद्देश्य

संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों को शैक्षिक नियोजन में अद्यतन प्रवृत्तियों तथा तकनीकों से अवगत करवाना तथा उन्हें सांख्यिकी तकनीकों को शैक्षिक नियोजन में अनुप्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना।

विषयवस्तु

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई : जम्मू और कश्मीर में शिक्षा : समस्यायें और चुनौतियां; शैक्षिक नियोजन; संकल्पना और तकनीक; भारत तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में शैक्षिक नियोजन; जम्मू और कश्मीर के विशेष संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के लिए नियोजन; सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए नियोजन; उच्चतम माध्यमिक अवस्था पर व्यवसायीकरण के लिए नियोजन तथा सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य; प्रौढ़ शिक्षा के लिए नियोजन; संस्थागत नियोजन; शैक्षिक नवाचारों के लिए नियोजन; जम्मू और कश्मीर के विशेष संदर्भ में पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए नियोजन; शैक्षिक सांख्यिकी में संकल्पनायें और परिभाषायें; जम्मू और कश्मीर में सूचना पद्धति; शैक्षिक नियोजन के जनांकिकीय पक्ष, शैक्षिक नियोजन में जनसंख्या प्रक्षेपण की तकनीकें, स्कूल आयु जनसंख्या के उपाय तथा समावेशन; शिक्षा में प्रवाही सांख्यिकी का विश्लेषण, शिक्षा में लागत, बजट और आंतरिक कुशलता, शिक्षा में मानिटरिंग और मूल्यांकन; शिक्षा में नमूना सर्वेक्षण विधियां; शिक्षा के प्रति अनुक्रिया प्राप्त न होने के अनुपात की तकनीकें, शिक्षा में आंतरिक कुशलता का सूचक, शैक्षक नियोजन में प्रक्षेपण तकनीक (नामांकन); तथा शैक्षिक नियोजन (अध्यापक और लागत) में प्रक्षेपण तकनीकें।

व्याख्यान-परिचर्चाओं के अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल परिचर्चाओं, व्यवहारिक अभ्यास; समूह कार्य तथा क्षेत्रीय दौरों की भी व्यवस्था की गई।

संगोष्ठी का उद्घाटन प्रो० मुनिस रज़ा, अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किया तथा समापन श्री जे० वीरराघवन, कार्यकारी निदेशक, नीपा की अध्यक्षता में हुआ।

श्री जे० वीरराघवन इस प्रशिक्षण संगोष्ठी के निदेशक भी थे। श्री एम. एम. कपूर, सहयोगी अध्येता ने कार्यक्रम समन्वयक के रूप में उनकी सहायता की तथा श्रीमती उषा नायर, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी ने सहयोगी कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया।

19. आश्रम स्कूल तथा आई. टी. आई. के अध्ययनों की चर्चा के लिए विशेषज्ञ संगोष्ठी (11-12 अगस्त, 1981)

प्रस्तावना

आश्रम स्कूल—गहन विश्लेषण तथा आई. टी. आई. तथा पॉलिटैकनिकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं से संबंधित अध्ययनों में अनुसंधात प्रस्तावों, उपागम लेखों तथा प्रश्नावलियों पर चर्चा करने के लिए 11 और 12 अगस्त, 1981 को एक बैठक का आयोजन किया गया। अध्ययनों के परियोजना निदेशकों सहित मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश तथा महाराष्ट्र से 11 विशेषज्ञों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी में परियोजनाओं के डिजाइन तथा उसके प्रचार संबंधित कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और उन्हें अन्तिम रूप दिया गया।

20. सितम्बर 12, 1981 को आयोजित जनसंख्या शिक्षा में प्रशिक्षण से संबंधित विशेषज्ञों की संगोष्ठी

प्रस्तावना

शैक्षिकों, नियोजकों, प्रशासकों और विभिन्न स्तरों पर नीति निर्धारकों के लिए नीपा द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों की व्यापक विषयवस्तु, पैरामीटर और संकल्पनात्मक निर्देश आधार पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यह अनुभव किया गया कि जनसंख्या शिक्षा का फोकस समकालीन विश्व तथा राष्ट्रीय संदर्भ के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक पद्धति के ढांचे में जनसंख्या प्रक्रियाओं तथा विकासात्मक प्रक्रियाओं के बीच अंतःसंबंधों पर होना चाहिए। इस संगोष्ठी में आई. सी. एस. एस. आर., जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, परिवार नियोजन प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण संस्थान से 12 विशेषज्ञों ने भाग लिया।

21. गैर-मौद्रिक आगमों पर बल देते हुए शैक्षिक विकास के लिए संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (22-25 सितम्बर, 1981)

प्रस्तावना

योजना आयोग, भारत सरकार के सुझाव पर राष्ट्रीय संस्थान में "गैर-मौद्रिक आगमों पर बल देते हुए शैक्षिक विकास के लिए संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग" पर 22-25 सितम्बर, 1981 को चार दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

उद्देश्य

संगोष्ठी के उद्देश्य निम्न थे :

(1) शैक्षिक विकास के लिए संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग किए जाने की आवश्यकता का गुण विवेचन तथा इसे प्राप्त करने के लिए विविध युक्तियों की पहचान करना ; तथा (2) मैक्रो और माइक्रो स्तरों पर गैर-मौद्रिक आगमनों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम वसूलियों के तरीकों की खोज करना।

विषयवस्तु

संगोष्ठी में विचार विमर्श के प्रयोजन के लिए निम्न प्रमुख विषयों की पहचान की गई :

(i) भविष्य के लिए शिक्षा का एक समन्वयी दृष्टिकोण ; (ii) संस्थागत स्तर पर प्रबंध में सुधार; (iii) शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अन्योन्य क्रिया को सुधारने के लिए शैक्षिक पद्धति के अंतर्गत ही संबंधों को सुधारना ; (iv) शैक्षिक पद्धति का सामाजिक पद्धति से अन्योन्य क्रिया; (v) शैक्षिक पद्धति की सहायता के लिए प्राकृतिक पद्धति की उपयोगिता; तथा (vi) विकेंद्रित नियोजन।

इस संगोष्ठी में योजना आयोग, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा के विविध राज्य विभागों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राज्यीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, प्रबंध संस्थान, थल सेना और जल सेना के मुख्यालय, ज़िला प्रशासन, आई०सी०एस०एस०आर०, दूरदर्शन, आल इंडिया रेडियो, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो तथा कुछ स्कूलों से 41 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक के एक प्रतिनिधि, बंगला देश के एक शिक्षा अधिकारी तथा नीपा के

कुछ संकाय सदस्यों ने भी इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

संगोष्ठी के विषयों पर उचित बल दिए जाने के लिए संगोष्ठी के विविध विषयों पर विद्वान व्यक्तियों से कुछ लेख विशेष रूप से लिखवाये गए। इससे भी अधिक विचार विमर्श को अधिक उत्तेजनापूर्ण तथा सफल बनाने के लिए कुछ ज्ञानवान् शिक्षाविदों द्वारा लिखे हुए तथा कुछ चुने हुए संबद्ध लेखों सहित पठन सामग्री के कुछ खंड तथा महत्वपूर्ण प्रलेखों के कुछ सार भाग लेने वालों को प्राप्त करवाये गए।

प्रो० मुनिस रजा संगोष्ठी के निदेशक थे, डा० आर०पी० सिंहल ने सहयोगी संगोष्ठी निदेशक का कार्य किया तथा डा० (श्रीमती) राधा रानी शर्मा ने संगोष्ठी समन्वयक का कार्य किया और श्री एस०एल० मीना ने संगोष्ठी के प्रबंध में सहायता की।

22. लम्बे समय की शैक्षिक योजना पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (21-23 दिसम्बर, 1981 नई दिल्ली)

प्रस्तावना

लम्बे समय की शैक्षिक योजना पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन करने से पहले लम्बे समय की शैक्षिक योजना पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी 21-23 दिसम्बर, 1981 को आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का उद्देश्य सगोष्ठी के विषय से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करना था। भारत तथा विदेशों के अनेक विशेषज्ञों से संगोष्ठी के इस विषय पर लेख लिखने के लिए अनुरोध किया गया था। इस संगोष्ठी ने भारत के लेखकों को अपने सह-व्यवसायिकों से विचार विनिमय तथा संगोष्ठी में हुई परिचर्चाओं के आधार पर उन्हें अपने लेखों को परिष्कृत करने का अवसर प्रदान किया।

23. राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य कार्मिकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (फरवरी 1-4, 1982 नई दिल्ली)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य कार्मिकों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के निकट सहयोग से आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में 25 राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयकों ने भाग लिया जिनमें उप कार्यक्रम सलाहकार युवा अधिकारी, उप निदेशक तथा उनके समान स्तर वाले अधिकारी सम्मिलित थे। भाग लेने वालों ने 12 राज्यों तथा 3 संघशासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जो इस प्रकार हैं : आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली तथा गोआ।

उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : राष्ट्रीय सेवा योजना के क्रियान्वयन में लगे मुख्य कार्मिकों को विचारों के आदान-प्रदान तथा अनुभवों के विनिमय के लिए एक दूसरे के निकट आने का अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय सेवा योजना की संकल्पना; नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करना; तथा मॉनिटरिंग और मूल्यांकन सहित राष्ट्रीय सेवा योजना के संगठनात्मक और प्रशासनिक पक्षों पर विचार करना था।

विषयवस्तु

उपरोक्त उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए कार्यक्रम में निम्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया : राष्ट्रीय सेवा योजना, समेकित ग्रामीण विकास के लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्यक्रम; केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राष्ट्रीय सेवा योजना; जनसंख्या शिक्षा, आर्थिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम में प्रकाशन और अनुसंधान; राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रशासनिक और वित्तीय समस्यायें; राष्ट्रीय सेवा योजना का स्व मूल्यांकन सहित मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन।

यह संगोष्ठी प्रधानतया, "समान व्यक्तियों की संगोष्ठी के रूप में ही आयोजित था और कार्यक्रम मुख्यत: व्याख्यान-चर्चा, समूह कार्य, कार्यक्षेत्र-वीक्षण और ग्रन्थालय में अध्ययनों पर आधारित था। सभी सहभागी सदस्यों को आपस में विचार-विनिमय करने के साथ साथ संस्थान के संकाय-सदस्य एवं बाहर के कुछ विशिष्ट संस्थाओं से व्याख्यान देने और परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए आह्वानित शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आयोजक एवं प्रशासक आदि सदस्यों के साथ विचार विनिमय करने का भी सदवकाश प्राप्त हुआ।

श्री किरीट जोशी, शिक्षा सलाहकार, शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय, भारत सरकार ने 1 फरवरी, 1982 को इस अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 4 फरवरी, 1982 को प्रो० एम० वी० माथुर, प्रतिष्ठित आचार्य, नीपा ने कार्यक्रम का समापन भाषण दिया।

श्री के० जी० विरमानी, सहयोग अध्येता, नीपा ने कार्यक्रम समन्वयक एवं सामान्य संवक्ता के रूप में कार्य किया। श्री पी० सी० महापात्रा, सहयोगी कार्यवाही सलाहकार, शिक्षा एवं संस्कृति मन्त्रालय एवं श्री एन० वी० वरगीस, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी, नीपा ने सहयोगी कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया। श्री एस० एल० मीना, वरिष्ठ तकनीकी सहायक ने कार्यक्रम के संचालन में सहायता की।

24. उच्च स्तरीय शैक्षिक प्रशासकों के लिए जनसंख्या शिक्षा पर अखिल भारतीय संगोष्ठी (18-19 फरवरी, 1982 नई दिल्ली)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने शिक्षा आयुक्तों, शिक्षा सचिवों तथा राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में शिक्षा विभाग के प्रभारी अधिकारी, लोकशिक्षा निदेशकों के लिए जनसंख्या शिक्षा पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संस्थान ने शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और यू. एन. एफ. पी. ए. यूनेस्को के सहयोग से एक जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ की। उच्च स्तरीय शैक्षिक प्रशासकों के लिए इस विषय पर नीपा द्वारा आयोजित यह पहली संगोष्ठी थी और इसके पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी तथा उपर्युक्त स्तर के अधिकारियों के लिए जनसंख्या शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।

उद्देश्य

संगोष्ठी के उद्देश्य निम्न थे : राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करना; भाग लेने वालों को जनसंख्या परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास के द्वंद्वात्मक संबंधों तथा शैक्षिक विकास से उनके सहवर्ता संबंधों से अनुभूत करवाना तथा जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंध के लिए युक्तियों की पहचान करवाना।

विषयवस्तु

संगोष्ठी में निम्न विषयों पर चर्चा की गई : राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा; जनगणना 1981 : उनके प्रभाव, जनसंख्या और विकास; उनका परस्पर संबंध; जनसंख्या और मानव शक्ति नियोजन, जनसंख्या और शैक्षिक विकास; जनसंख्या और स्त्रियों तथा बच्चों की प्रस्थिति, जनसंख्या और स्वास्थ्य; जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का प्रबंध; मामले और नीतियां।

यह संगोष्ठी अनिवार्यतः 'समानों की संगोष्ठी' के रूप में आयोजित की गई थी और समूह चर्चाओं पर मुख्यतः आधारित थी। इस संगोष्ठी में भाग लेने वालों को प्रस्तुत विषय पर उनके अनुभवों और विचारों के विनिमय का अवसर प्राप्त हुआ। संगोष्ठी में व्याख्यान परिचर्चायें, साथ ही पैनल परिचर्चायें भी की गई।

इस संगोष्ठी का संचालन प्रो० मुनिस रज़ा, निदेशक, नीपा, जो इस संगोष्ठी के कार्यक्रम निदेशक भी थे, के समग्र मार्गदर्शन में किया गया । डा० आर. पी. सिंहल, परामर्शदाता और प्रशिक्षण के संकाय अध्यक्ष ने इस संगोष्ठी में सहयोगी कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया । डा० एस० पी० श्रीवास्तव ने सहयोगी कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया तथा श्री एस. एल. मीना, नीपा ने संगोष्ठी के प्रबंध में सहायता प्रदान की ।

25. संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षक तथा पाठ्यचर्या परामर्शदाता के लिए भारतीय इतिहास तथा संस्कृति से संबंधित कार्यशाला (30 जून–16 जुलाई, 1981)

प्रस्तावना

भारत में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक प्रतिष्ठान के अनुरोध पर तथा शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन पर राष्ट्रीय संस्थान ने 30 जून से 16 जुलाई, 1981 को सामाजिक अध्ययनों के पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या परामर्शदाताओं के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति में कार्यशाला का आयोजन किया। समुद्र पारीय शैक्षिक पर्यवेक्षकों का यह तीसरा समूह था जो संस्थान से सम्बद्ध था। इस कार्यशाला में संयुक्त राज्य के 15 सामाजिक विज्ञानों के पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या परामर्शदाताओं ने भाग लिया।

उद्देश्य

यह कार्यशाला भारत में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक प्रतिष्ठान के परामर्श से संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या परामर्शदाताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई थी। इस कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे : भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन; भाग लेने वालों को शिक्षा की मुख्य प्रवृत्तियों से तथा भारत में विकास के बदलते हुए प्रतिरूपों से परिचित करना; आधुनिक भारत की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और प्रतिकूल प्रवृत्तियों के ज्ञान में सुधार लाना जिससे यह ज्ञान संयुक्त राज्य के स्कूलों में भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्यापन में सुधार लाने में उपयोगी सिद्ध हो सकेगा; तथा भारतीय विद्वानों की सहायता से आपसी समझ का प्रसार करना।

विषयवस्तु

कार्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए परिचर्चाओं में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए गए : भारत—भूमि; भारत—व्यक्ति; भारतीय ऐतिहासिक परम्परा के मुख्य लक्षण; स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष; भारतीय राजनीति; नियोजन और विकास; हरित क्रांति; औद्योगिक विकास; विदेश संबंध; जनसंख्या; समस्यायें और नीतियां, राष्ट्रीय एकता और समाकलन की समस्यायें, सामाजिक बंधन—अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां; महिलाओं की प्रस्थिति; साक्षरता दाय; भारतीय कला का संदेश; आधुनिक भारत में विज्ञात और टैक्नोलोजी; भारतीय शिक्षा -समस्यायें और परिप्रेक्ष्य; भारतीय स्कूलों में सामाजिक विज्ञानों का अध्यापन; भारत—एक संक्षिप्त दृश्य।

इस कार्यशाला में राष्ट्रीय स्टाफ के संकाय के अतिरिक्त अन्य निम्नलिखित विशेषज्ञ व्यक्ति भी सम्मिलित थे—शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, सी. एस. आई. आर. विज्ञान और टैक्नोलोजी विभाग, एन. सी. ई. आर. टी , दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा महिला विकास अध्ययन केन्द्र से बुलाए गए प्रधानाचार्य, अनुभवी प्रशासक तथा विशेषज्ञ ।

कार्यशाला व्याख्यान-परिचर्चाओं पर ही मुख्यत: आधारित थी और इनके पश्चात् अपरान्ह में क्षेत्र-दौरे किए गए । प्रत्येक भाग लेने वाले ने अपनी वैयक्तिक क्षमता के अनुरूप कार्यशाला में भाग लिया और उन्हें सार्थक रूप से वक्ताओं से विचार-विनिमय करने का भी पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ ।

प्रो० मुनिस रज़ा, निदेशक, नीपा ने कार्यक्रम निदेशक का कार्य किया। उनकी सहायता डा० आर. एन. चौधरी ने कार्यक्रम समन्वयक के रूप में की । श्री के. जी. विरमानी ने सहयोगी कार्यक्रम समन्वयक तथा सुश्री रंजना श्रीवास्तव ने सहायक कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया ।

26. श्री महमूद अमिनूल इस्लाम, प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशासन, प्रबंध और अनुसंधान संस्थान तथा संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, बंगला देश का अध्ययन दौरा

प्रस्तावना

बंगला देश सरकार ने शैक्षिक प्रशासन, नियोजन और प्रबंध के सभी पक्षों में नियुक्त कार्मिकों को क्षेत्र में उचित अनुसंधान करने, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहयोग करने तथा शैक्षिक संस्थानों को परामर्शकारी तथा सलाहकारी सेवायें प्रदान करने के लिए सेवाकालीन और सेवापूर्व प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रशासन, प्रबंध और अनुसंधान संस्थान (एन आई इ ए एम आर) की स्थापना की। श्री महमूद अमिनूल इस्लाम, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, बंगला देश इस संस्थान के पहले प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। यूनेस्को के लिए बंगला राष्ट्रीय आयोग, शिक्षा मंत्रालय, बंगलादेश की ओर से श्री इस्लाम को 5-8 अगस्त, 1981 को एक अध्ययन दौरे के लिए नीपा में भेजा गया।

उद्देश्य और विषयवस्तु

श्री इस्लाम के दौरा कार्यक्रम में निदेशक तथा वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ व्यक्तिगत चर्चाओं के अतिरिक्त अन्य संकाय सदस्यों से समूह परिचर्चायें भी सम्मिलित थीं। श्री इस्लाम को नीपा के उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों और उनके प्रबंध से परिचित करवाया गया; उन्हें दोनों देशों—बंगला देश और भारत के समान रुचि के क्षेत्रों यथा—प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, व्यावसायिकता तथा शैक्षिक नीति, योजना, वित्त तथा प्रबंध के विशिष्ट क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं और अस्थायी समाधानों से अवगत करवाया गया।

27. प्राथमिक शिक्षा के प्रबंध और प्रशासन के आधुनिक तकनीकों का अध्ययन करने के लिए श्री फ़ज़रूल रहमान खान, जिला शिक्षा अधिकारी ताँगेल, बंगला देश का नीपा में स्थानन (21 सितम्बर से 17 अक्तूबर, 1981)

संस्थान ने शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार में यूनेस्को से सहयोग के भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कहने पर बंगला देश के यूनेस्को अध्येता श्री फ़ज़रूल रहमान खान के लिए प्राथमिक स्कूल शिक्षा में प्रशासन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में 21 सितम्बर से 17 अक्तूबर, 1981 को पांच सप्ताह का एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया । नीपा द्वारा डिजाइन किए गए इस स्थानन कार्यक्रम में श्री खान ने एकत्रित आंकड़े, नीपा के संकाय तथा अन्य शैक्षिक प्रशासकों से चर्चा तथा प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर बंगला देश राज्य के एक जिले में प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार किया । नीपा में अपने प्रशिक्षण के दौरान श्री खान को प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंध से संबंधित समस्याओं ही से अवगत नहीं करवाया बल्कि उन्हें माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर-औपचारिक शिक्षा से संबंधित समान मामलों से भी परिचित करवाया ।

श्री खान को क्षेत्रीय अनुभव प्राप्त करवाने के लिए स्थानीय स्कूलों, एन सी इ आर टी, नई दिल्ली तथा एस सी इ आर टी, गुड़गांव (हरियाणा) तथा डी ए ओ, एस डी इ ओ, बी इ ओ, तथा डी ए इ ओ गुड़गांव में उनके दौरों की व्यवस्था की गई। श्री खान ने उपरोक्त कार्यालयों के कार्यप्रणाली में अत्यंत रुचि प्रकट की तथा उन्होंने उनमें काम कर रहे कार्यकर्त्ताओं से विचार विनिमय भी किया। इस कार्यक्रम के नियत कार्य के रूप में उन्होंने श्री जे पी नायक द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पर लिखी पुस्तक का सार संक्षेप भी तैयार किया ।

28. लम्बे समय की शैक्षिक योजना पर क्षेत्रीय कार्यशाला (12-25 जनवरी, 1982 नई दिल्ली)

प्रस्तावना

नीपा और एशिया तथा पेसिफिक में शिक्षा के यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक द्वारा एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ने मेजवान की भूमिका निभाई। इस कार्यशाला में 11 विभिन्न एशियाई देशों से 21 सदस्यों तथा 5 प्रेक्षकों ने भाग लिया।

उद्देश्य

1980 की पिछली बैठकों में नीपा तथा आर ओ इ ए पी ने यह अनुभव किया कि अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा के लम्बे समय के पूर्वानुमान लगाने की विधियों तथा तकनीकों तथा मानवीय संसाधन विकास पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अधिक-से अधिक बल दिया जाना चाहिए।

इस कार्यशाला का आयोजन उपर्युक्त विचारों और संकल्पों का व्यवहार में लाने की दृष्टि से किया गया था। इस कार्यशाला के उद्देश्य निम्न थे : शिक्षा में लम्बे समय की पूर्वानुमान योजना की विधियों और तकनीकों तथा मानवीय संसाधन विकास में अनुभव प्राप्त देशों में कुछ चुने हुए शैक्षिक तथा सामाजिक आर्थिक योजनाकारों की व्यवस्था करना; कार्यशाला में भाग ले रहे सदस्यों में निम्न विषय में जागरूकता की वृद्धि करना— शिक्षा की लम्बे समय की भविष्य योजना बनाते समय बहुविधता, सूक्ष्मता, संभावनायें तथा बाध्यतायें तथा इनकी सामाजिक-आर्थिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक विकास प्रक्रियाओं से अन्योन्य क्रिया; तथा प्रत्येक देश की अपनी सामाजिक-आर्थिक विकास प्रकिया के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर लम्बे समय की शैक्षिक योजना के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षणात्मक साम्रमी के विकास में तीव्रता लाना।

विषयवस्तु

व्यापक उद्देश्यों के उपरोक्त वर्ग में निम्नलिखित विशिष्ट तकनीकी विषयों पर प्रस्तुत किए गए लेखों पर तथा उसके बाद की परिचर्चाओं में विचार विमर्श किया गया : जनसंख्या/पर्यावरण/मानवीय बस्ती अनुमान; टेकनोलोजिकल भविष्य/मूल्यांकन; मानवीय संसाधन विकास/मानव शक्ति योजना; शिक्षा तथा विकास/मूल आवश्यकताओं के पूर्वानुमान लगाने में गुणता संबंधी (भविष्यता) तथा परिमाण सम्बन्धी (माडल बनाना) विधियों, शैक्षिक विषमतायें, क्षेत्रीय, ग्रामीण/शहरी, पुरुष/महिला सांस्कृतिक, सामाजिक-

आर्थिक); प्रबंध/संगठनात्मक विकास; योजना कार्यक्रम/परियोजना मॉनिटरिंग, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन सूचना ज्ञान जाल; संसाधन उपयोगिता/नियतन/उपयोगिता; आगम/आगम लक्ष्य निर्धारण तथा मार; शैक्षिक प्रौद्योगिकी, उत्पादन कार्य आदि; तथा अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय अंत:शास्त्रीय सम्बन्ध; टेकनोलोजी अंतरण; प्रवास/ब्रेनड्रेन; सामूहिक निर्भरता/क्षेत्रीय सहयोग, नयी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक/सूचना व्यवस्था (दृश्यावली) निर्माण/विश्व मार्डलिंग आदि)

कार्यशाला में निम्नलिखित विधियों और तकनीकों का प्रयोग किया गया : (i) व्याख्यान/प्रस्तुतीकरण (विशिष्ट विषयी) समस्याओं/मामलों तथा भविष्य वक्तव्य तकनीकों के अनुप्रयोग पर विशेष फोकस करते हुए); (ii) प्रत्येक व्याख्यान/प्रस्तुती के पश्चात् व्यावहारिक अभ्यासों के रूप में नियत कार्य दिए गए; तथा (iii) भविष्य पूर्वानुमान तकनीकों, प्रक्षेपण विधियों, अनुकरण (छद्म रूप), दृश्यावली निर्माण आदि के अनुप्रयोग पर किए गए समूह कार्य और व्यावहारिक अभ्यासों की समीक्षा।

कार्यशाला 36 उपसत्रों तथा 3 समूहों सत्रों में आयोजित की गई। भाग लेने वालों के लाभ के लिए कार्यशाला के विषय से संबंधित नई दिल्ली की महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाओं में दौरों की भी व्यवस्था की गई।

कार्यशाला का उद्घाटन 12 जनवरी, 1982 को श्री टी एन कॉल, भूतपूर्व विदेश सचिव तथा वर्तमान में सदस्य, कार्यपालक बोर्ड, यूनेस्को ने किया। प्रो० एस० नूरूल हसन, उप-अध्यक्ष, भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने समापन भाषण दिया।

29. शैक्षिक योजना और प्रबन्ध पर पत्राचार कार्यक्रम

प्रस्तावना

संस्थान 1978-79 से प्रत्येक वर्ष शैक्षिक योजना और प्रबन्ध में छः महीने की अवधि का पत्राचार कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इस श्रृंखला में चौथा कार्यक्रम 1 अगस्त, 1981 को प्रारम्भ किया गया।

भाग लेने वाले

यह कार्यक्रम सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति का है तथा इसमें राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के जिला और वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी भाग लेते हैं। यद्यपि 69 व्यक्तियों को इस पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत किया गया था, परन्तु अब उनकी संख्या 18 रह गई है।

मुख्य उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भाग लेने वालों को सामान्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अद्यतन विकास तथा विशेष रूप से शैक्षिक नियोजन और प्रबन्ध में अद्यतन विकास से अवगत करवाना; तथा लम्बे समय तक उनको अपने कार्य से अलग किए बिना शैक्षिक नियोजकों तथा प्रशासकों के रूप में उनकी तकनीकी प्रवीणता तथा प्रभाविता में संवर्द्धन करना है।

पाठ्यक्रम विषयवस्तु

पाठ्यक्रम में 41 पाठ यूनिटों को छः पुस्तकों में विभाजित किया गया : (i) पृष्ठ-भूमि तथा मूल संकल्पनायें; (ii) शैक्षिक प्रबंध की प्रस्तावना; (iii) नियोजन, (iv) क्रियान्वयन; (v) वर्तमान मामले; तथा (vi) चुनौतियां तथा प्रतिउत्तर।

नियत कार्य और व्यावहारिक कार्य

पाठ यूनिटों पर नियत कार्य के अतिरिक्त भाग लेने वालों को क्षेत्र दौरे करने पड़े, उन्हें शैक्षिक नियोजन या प्रबन्ध सम्बन्धित विषय (विषय का चुनाव संस्थान के अनुमोदन से किया जाता है) पर लेख/परियोजना तथा संस्थान द्वारा अनुमोदित पुस्तक सूची में से चुनी गई पुस्तक पर समीक्षा तैयार करनी पड़ी।

सम्पर्क कार्यक्रम

पाठ्यक्रम की समाप्ति एक सप्ताह के सम्पर्क कार्यक्रम से हुई। केवल वे ही व्यक्ति इस सम्पर्क कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं जो : (क) 6 में से 4 पुस्तकों पर नियत कार्य; (ख) पुस्तक समीक्षा, तथा (ग) सत्र पत्र/परियोजना रिपोर्ट पूरी कर लेते हैं ।

इस सम्पर्क कार्यक्रम का मुख्य लक्षण—(i) नियत कार्यों पर परिचर्चायें, तथा (ii) भाग लेने वालों द्वारा सत्र पत्र का प्रस्तुतीकरण है ।

भाग लेने वालों के लिए चौथे पाठ्यक्रम में सम्पर्क कार्यक्रम मई, 1982 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ।

अनुबन्ध—2

अतिथिगण

समीक्षाधीन अवधि में संस्थान ने निम्नलिखित प्रशिष्ट मंडलों/गणमान्य अभ्यागतों का स्वागत किया ।

—राज्य शिक्षा विभाग, कैलिफोर्निया से 15 प्रारम्भिक और प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल ने 26 जून, 1981 को संस्थान का दौरा किया । इस देश में उनके दौरे का उद्देश्य भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान (यू एस इ एफ आई) के कार्यक्रम के अन्तर्गत "आधुनिक भारत" का अध्ययन करना था । अतिथि अध्यापकों की नीपा के सदस्यों से आयोजित बैठक ने वर्तमान समय में दोनों देशों के समान शैक्षिक मामलों, विशेष रूप से स्कूल-शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर अनुभवों तथा विचारों के आदान-प्रदान करने तथा अन्योन्यक्रिया करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर प्राप्त करवाया । अमरीकियों ने संस्थान के क्रियाकलापों और कार्यक्रमों में अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की ।

—भारतीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संघ के तत्वाविधान में 4 मई, 1981 को डा० एन० वेदमानी मैन्यूअल, आचार्य तथा अध्यक्ष शिक्षा विभाग, केरल विश्वविद्यालय ने "शैक्षिक नवाचार; विसार तथा विकृतियों" विषय पर एक वार्ता दी । इस वार्ता के पश्चात् संस्थान के संकाय सदस्यों से एक रुचिकर परिचर्चा की गई ।

—विश्व बैंक के शिक्षा विभाग के डा० अबदुन नूर ने 26 जून, 1981 को संस्थान का दौरा किया और उनके लिए विकासशील देशों को जिन शैक्षिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है उस पर चर्चा करने के लिए सकाय के सदस्यों से बैठक आयोजित की गई । डा० नूर ने सर्वव्यापक नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति की मांगपर विशेष रूप से बल दिया । उन्होंने इस वांछित लक्ष्य की उपलब्धि में आने वाली समस्याओं का भी जिक्र किया ।

—श्री मैट्स हुलटिन, शिक्षा सलाहकार, विश्व बैंक, वाशिंगटन ।

—श्री फजलुर रहमान खान, जिला शिक्षा अधिकारी, ढाका, बंगला देश।

श्री अमीनूल इसलाम, प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय प्रशासन और प्रबन्ध अनुसंधान संस्थान तथा संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, बंगला देश, 5-8 अगस्त, 1981। श्री मोहम्मद इस्लाम ने "बंगला देश में शैक्षिक प्रशासन की तत्कालीन प्रवृत्तियों" शीर्षक पर 7 अगस्त, 1981 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

—प्रो० पी० एन० माथुर, अर्थशास्त्र विभाग, वेल्स विश्वविद्यालय काज्रिज, पैंगलेयास, एबरीस्विथ, यू० के० (8 अगस्त—6 सितम्बर, 1981)। प्रो० माथुर ने मानव शक्ति योजना के विशेष सन्दर्भ में शिक्षा के अर्थशास्त्र पर एक यूनिट का विकास करने में संस्थान को सहायता प्रदान की।

—श्री हंस रैफ, सलाहकार, शिक्षा योजना और प्रबंध, यूनेस्को, आर०ओ०इ०ए०पी० बैंकाक ने "मालद्वीप में शैक्षिक नियोजन" पर 7 अगस्त, 1981 को एक भाषण दिया।

—श्री गैवरिल कारकेलस, अध्यक्ष, शिक्षा पर सांख्यिकी विभाग, सांख्यिकी कार्यालय, यूनेस्को, पेरिस ने 5 अक्तूबर, 1981 को संस्थान में दौरा किया तथा यूनेस्को का सांख्यिकी कार्यालय, पेरिस की चालू परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर संकाय के सदस्यों से बातचीत की।

—श्री मोहम्मद अब्दुल जाबर, अध्यक्ष सांख्यिकी विभाग, शैक्षिक सूचना और सांख्यिकी ब्यूरो, बंगला देश ने 7 दिसम्बर, 1981 को संस्थान का दौरा किया और संकाय के सदस्यों से भेंट की।

—इंडोनेशिया से युनेस्को अध्येताओं के एक समूह ने 9 दिसम्बर, 1981 को संस्थान का दौरा किया और शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में समान रुचि की समस्याओं पर संकाय के सदस्यों से भेंटवार्ता की।

—यूनेस्को द्वारा प्रायोजित वियतनामी प्रौढ़ शिक्षा विशेषज्ञों के चार सदस्यीय दल ने 30 दिसम्बर, 1981 को संस्थान का दौरा किया। विशेषज्ञों को संकाय के सदस्यों से विचार विनिमय का अवसर प्राप्त हुआ।

—प्रो० डाइट्रिच गोल्डस्मिट, निदेशक, मैक्स प्लैंक मानव संसाधन तथा शैक्षिक विकास संस्थान, पश्चिमी बर्लिन ने पश्चिमी जर्मनी में "समाज विज्ञान का शैक्षिक विकास में योगदान" पर 28 जनवरी, 1982 को एक भेंटवार्ता प्रस्तुत की।

—प्रो० एडवर्ड ए० होलडावे, शैक्षिक प्रशासन विभाग, एलबर्टो विश्वविद्यालय, कनाडा ने 2 फरवरी, 1982 को संस्थान का दौरा किया और "एलबर्टो विश्वविद्यालय के स्नातक शिक्षा कार्यक्रम के संगठन" पर संकाय के सदस्यों से विचार विनिमय किया।

—डा० जार्ज बैरो, प्रतिष्ठित आचार्य, शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा संस्थान, लंदन विश्वविद्यालय, ने संस्थान में 23 जनवरी 1982 को "ब्रिटेन में शैक्षिक प्रशासन पर अनुसंधान" विषय पर एक व्याख्यान दिया।

—डा० चार्ल्स एस० बैनसन ने 1 मार्च, 1982 को संस्थान में दौरा किया और संकाय के सदस्यों से बैठक की।

—श्री आर०आर० अय्यर, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण विभाग, सामाजिक विज्ञानों और उनके अनुप्रयोग का अनुभाग, यूनेस्को, पेरिस ने संस्थान का दौरा किया।

—श्री टी० एन० कॉल भूतपूर्व विदेश सचिव तथा वर्तमान में सदस्य, कार्यकारी बोर्ड, यूनेस्को।

—डा० जोनस्टोन जैम्स, एन० मैक्यूरी विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया।

—श्री कीकूची ज्योति, अध्यक्ष, अनुसंधान अनुभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, टोकियो, जापान।

—श्री कूरीमोती, के० शैक्षिक नियोजन विभाग, यूनेस्को, पेरिस।

—डा० टुन लिविन, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन में कार्यक्रम विशेषज्ञ, आर० ओ० इ० ए० पी०, बैंकाक।

—डा० नूरुदीन बान जाहिद, शिक्षा निदेशक, नेगरी सेम्बिलन, मलेशिया।

—श्री हंस डब्लू रेफ, शैक्षिक योजना और प्रबंध सलाहकार, आर० ओ० इ० ए० पी०, बैंकांक।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय

—श्रीमती अन्ना मल्होत्रा, शिक्षा सचिव।

—श्री एस० सत्यम, संयुक्त सचिव।

—श्री किरीत जोशी, शैक्षिक सलाहकार।

—श्री जे०ए० कल्याणकृष्णन, वित्तीय सलाहकार।

—श्री एस० रामामूर्ति, संयुक्त सचिव (योजना)।

—डा० (सुश्री) कपिला वात्स्यायन, संयुक्त शिक्षा सलाहकार।

—प्रो० एल०आर० शाह, कार्यक्रम सलाहकार (एन एस एस)।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

—श्री वसंत साठे, केन्द्रीय मन्त्री।

योजना आयोग

—डा० एम० एस० स्वामीनाथन, सदस्य।

—डा० एस० एन० सर्राफ, सलाहकार (शिक्षा)।

—डा. एस. पी. गुप्ता, मुख्य सलाहकार (पी. पी. विभाग)।

—डा. पदम सिंह, उप सलाहकार (पी. पी. विभाग)।

केन्द्रीय गृह मन्त्रालय

—डा. भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव।

केन्द्रीय ग्रामीण पुनर्निर्माण

—श्री जी. एल. बेलूर, भारतीय प्रशासनिक सेवा, संयुक्त सचिव।

—श्री एन. पी. सिंह, निदेशक (राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम)।

शिक्षा मन्त्रालय (हरियाणा)

—चौधरी देस राज, गणमान्य शिक्षा मन्त्री।

राज्य शिक्षा विभाग

—श्री ए. सहस्रनामन, आई. ए. एस., जिला विकास आयुक्त, जम्मू और कश्मीर सरकार ।

—श्री वी. वी. मौंगिया, उप आयुक्त (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम ।

—डा. एच. के. सिंह, संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग; हरियाणा ।

—डा. (कुमारी) ए. नंदा, अपर निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) दिल्ली प्रशासन ।

—श्री बी. आर. व्यास, शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य, दिल्ली प्रशासन ।

—कुमारी उषा बाली, निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार ।

—श्री पी. आर. उमाशंकर, विशेष आयुक्त तथा सचिव (सामान्य शिक्षा) केरल सरकार ।

—श्री मधु सूदन सिंह, शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गैंटाक ।

—श्री पी. आदिनारायण, स्कूल शिक्षा निदेशक, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद ।

—श्री एच. एन. सिंह, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा निदेशक, नया मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल कम्पाउण्ड, अहमदाबाद ।

—श्री वी. वी. चिप्लूकर, निदेशक, शिक्षा, महाराष्ट्र सरकार, पूना ।

—श्री इफ्ताक हुसैन, सहायक स्कूल निरीक्षक, डिबरूगढ़, आसाम ।

—श्री सी. आर. वैद्यनाथन, सलाहकार (शिक्षा) बिहार सरकार ।

—डा के. एल. गांधी, अपर निदेशक, शिक्षा, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

—श्री के. सी. शर्मा, आई. ए. एस. लोक शिक्षा निदेशक, हरियाणा सरकार ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

—श्री आर. के. छाबड़ा, सचिव ।

—श्री एस. सी. गोयल, संयुक्त सचिव।

—डा. डी. शंकर नारायण, अपर सचिव।

एन सी इ आर टी

—डा. एस. के. मित्रा, निदेशक।

—डा. टी. एन. धर, संयुक्त निदेशक।

—प्रो. बी. एस. पारिख, विभाग अध्यक्ष, सामाजिक अध्ययन और मानविकी शिक्षा विभाग।

—डा. ए. के. जलालुद्दीन, प्रधानाचार्य, विज्ञान और अंकगणित विभाग।

—डा. ए. बी. एल. श्रीवास्तव, अध्यक्ष, सर्वेक्षण और आंकड़ा परीक्षण यूनिट।

—श्री डी. पी. नायर, वरिष्ठ अध्येता, आई. सी. एस. एस. आर।

एस. सी. ई. आर. टी.

—डा. बी. आर. गुप्ता, निदेशक, एस. सी. ई. आर. टी., हरियाणा।

—प्रो के. रामानायन, निदेशक, एस. सी. ई. आर. टी. ,मद्रास।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

—डा. जे. डी. शर्मा, निदेशक।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

—श्री जीवन नायक, परामर्शदाता।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

—माननीय फादर टी. वी. कुन्नन्कल।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

—डा. अमरीक सिंह, सचिव ।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

—प्रो० कुलदीप माथुर, प्राचार्य, व्यवहारात्मक विज्ञान तथा विकास प्रशासन ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

—प्रो. एस. नूरुल हसन, उपाध्यक्ष ।

प्रबंध संस्थान

—प्रो. उदय पारिख, आई. आई. एम., अहमदाबाद ।

आई. सी. एस. एस. आर.

—डा. डी. डी. नरूला, सदस्य सचिव ।

यू एस. इ. एफ. आई

—श्रीमती सरला नायक, निदेशक ।

—डा. (श्रीमती) प्रेम पसरीचा, इ. टी. ए. अधिकारी ।

—श्री सी. एस. रामकृष्णन, निदेशक ।

—श्री आर. बी. मंगल, कार्यक्रम निदेशक ।

विश्वविद्यालय

—प्रो. सत्य भूषण, उपकुलपति, जम्मू विश्वविद्यालय।

—डा. आर. एन. महरोत्रा, आचार्य तथा शिक्षा विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय।

—श्री रुद्रदत्त, पत्राचार पाठ्यक्रम तथा अनुवर्ती शिक्षा, दिल्ली विश्वविद्यालय ।

—डा. (सुश्री) सुनीति दत्त, शिक्षा-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

—डा. एन. एस. प्रधान, प्रधानाचार्य, किरोड़ीमल कालिज, दिल्ली विश्वविद्यालय।

—प्रो. एन. आर. चटर्जी, अध्यक्ष, प्रबंध अध्ययन, दिल्ली विश्वविद्यालय।

—श्री मोहिंदर सिंह, प्रधानाचार्य, विवेकानंद महिला कालिज, दिल्ली विश्वविद्यालय।

—डा. कृष्ण वाल, प्रधानाचार्य, रामलाल आनन्द कालिज, दिल्ली विश्वविद्यालय।

—श्री ओ. पी. कोहली, अध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ।

—डा. जे. एम. कॉल, अतिथि आचार्य, मेरठ विश्वविद्यालय।

—डा. हेमलता स्वरूप, उपकुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय।

—प्रो. आबद अहमद, निदेशक, साऊथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय।

—प्रो. आनन्द स्वरूप, उपकुलपति, पंतनगर, कृषि विश्वविद्यालय।

—प्रो. रईस अहमद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।

—डा. पी. एन. मल्होत्रा, कालिज डीन, दिल्ली विश्वविद्यालय।

—प्रो. बावर मेंहदी, जामिया मिलिया इसलामिया।

—डा. ए. कुंडु, जे. एन. यू.।

—प्रो. एस. एम. दुबे, अध्यक्ष, समाज विज्ञान विभाग, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय।

—प्रो. सूमा चिटनिस, टाटा सामाजिक विज्ञान अध्ययन बम्बई ने "शिक्षा और समानता" पर 7 अगस्त, 1981 को एक वार्ता प्रसारित की।

—डा. (सुश्री) सविता बर्मन, भूविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

—डा. ए. अहमद, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जे. एन. यू.।

—डा. जी. एम. भल्ला, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जे. एन. यू.।

—डा. एम. एस. राजन, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, जे. एन. यू।

—प्रो. योगेन्द्र सिंह, समाज विज्ञान स्कूल, जे. एन. यू.।

—डा. आशिश बोस, आर्थिक वृद्धि संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय।

अन्य

—प्रो. स्वरूप सिंह, संसद सदस्य, 21, विलिंगडन क्रिसेंट

—डा. प्रेम कृपाल, भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा सचिव तथा यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष।

—श्री एम. एन. कपूर, निदेशक, ज्ञान भारती स्कूल, नई दिल्ली।

—श्री पी. पद्मनाभन, जनगणना आयुक्त तथा भारत के रजिस्ट्रार जनरल।

—प्रो. गौतम माथुर, निदेशक, आई. ए. एम. आर.।

—डा. स्वरूप सिंह, भूतपूर्व उपकुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा वर्तमान में राज्य सभा सदस्य।

परिशिष्ट — 1

नीपा की परिषद् के सदस्यों की सूची

31-3-1982 यथा स्थिति

1. प्रो. डी. टी. लकड़वाला — अध्यक्ष
भूतपूर्व उपाध्यक्ष
योजना आयोग
द्वारा सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ
इकनामिक एण्ड सोशल चेंज,
पोस्ट बाक्स नं० 4062,
नवरंगपुरा,
अहमदाबाद-380009 ।

2. प्रो. मुनिस रज़ा — उपाध्यक्ष
निदेशक, नीपा
नई दिल्ली ।

पदेन सदस्य

3. डा. (श्रीमती) माधुरी शाह — सदस्य
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002 ।

4. श्रीमती पन्ना मल्होत्रा, — सदस्य
सचिव,
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

5. श्री जे. ए. कल्याणकृष्णन, — सदस्य
वित्तीय सलाहकार,
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय,
नई दिल्ली ।

6. श्री के. डी. मदान, — सदस्य
अपर सचिव,
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग,
सरदार पटेल भवन,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001 ।

7. श्री के. आर. शिवरामकृष्णन, — सदस्य
संयुक्त सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग,
योजना भवन,
नई दिल्ली ।

8. डा. एस. के. मित्रा, — सदस्य
निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
नई दिल्ली ।

अन्य सदस्य

9. श्री यू. सी. सरनिया, सदस्य
शिक्षा सचिव,
आसाम सरकार,
सचिवालय,
दिसपुर,
गोहाटी-781006 ।

10. श्री के एन. अर्धनारीश्वरन, सदस्य
शिक्षा आयुक्त,
बिहार सरकार,
नया सचिवालय,
पटना ।

11. श्री एल. सी. गुप्ता, सदस्य
शिक्षा सचिव,
हरियाणा सरकार,
सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़ ।

12. श्री के. रामामूर्ति, सदस्य
शिक्षा सचिव,
गुजरात सरकार,
सचिवालय,
गांधीनगर-382010 ।

13. श्री एम. गोपालकृष्णन, आई. ए. एस. सदस्य
सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग,
सचिवालय भवन,
हैदराबाद-22 ।

14. श्री विरेन्द्र सिंह, सदस्य
शिक्षा सचिव, अण्डमान और निकोबार आईलैंड,
पोर्ट ब्लेयर ।

15. श्री बी. एल. हांडा, सदस्य
शिक्षा निदेशक,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
ग्लैन होगेन,
शिमला-171001 ।

16. श्री के. के. चक्रवर्ती, सदस्य
लोक शिक्षा निदेशक
मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल ।

17. डा. एम. पटनायक, सदस्य
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उड़ीसा सरकार,
न्यू कैपीटल,
भुवनेश्वर-1 ।

18. श्री एस. हालप्पा, सदस्य
लोक शिक्षा निदेशक,
कर्नाटक सरकार,
न्यू पब्लिक ओफीसस
पोस्ट बाक्स-5049
बंगलौर-560001 ।

19. श्री ई. येमासिंह, सदस्य
शिक्षा निदेशक (स्कूल)
मणीपुर सरकार,
इम्फाल ।

20. श्री एस. के. गुप्ता, सदस्य
लोक शिक्षा निदेशक,
अरुणाचल प्रदेश सरकार,
न्यू इतानगर-791110 ।

21. डा. मैल्कोम एस. आदिशेषिया, सदस्य
अध्यक्ष,
मद्रास विकास अध्ययन केन्द्र,
79, सैकिड मैन रोड,
गांधी नगर, अडियार,
मद्रास-600006 ।

22. श्री एम. एन. कपूर, सदस्य
ई-4, महारानी बाग,
नई दिल्ली ।

23. प्रो. सत्य भूषण, सदस्य
उपकुलपति,
जम्मू विश्वविद्यालय,
जम्मू ।

24. प्रो. गुरबक्श सिंह, सदस्य
उपकुलपति,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली ।

25. श्रीमती शिवगामी पेथाची, सदस्य
संवक्ता,
वेडफ़ोर्डविला,
7/8 लेथ कासल नोर्थ स्ट्रीट,
सेनथोम,
मद्रास-600008 ।

26. डा० एल० बुल्लय्या, सदस्य
भूतपूर्व उपकुलपति,
आंध्रप्रदेश,
1-10-13 अशोक नगर,
हैदराबाद ।

27.	श्री एस. राममूर्ति, संयुक्त सचिव (योजना) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
28.	श्री जे० वीरराघवन, कार्यपालक निदेशक, नीपा, नई दिल्ली।	सदस्य
29.	डा०आर०पी० सिंहल, परामर्शदाता, नीपा नई दिल्ली।	सदस्य
	श्री आर० पी० सक्सेना रजिस्ट्रर नीपा, नई दिल्ली।	सचिव

परिशिष्ट—2

नीपा की कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची

(31-3-1982 को यथा स्थिति)

1. प्रो० मुनिस रज़ा, — अध्यक्ष
निदेशक,
नीपा,
नई दिल्ली।

2. श्री जे. ए. कल्याणकृष्णन, — सदस्य
वित्तीय सलाहकार,
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

3. श्री एस. रामामूर्ति — सदस्य
संयुक्त सचिव (योजना)
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

4. श्री के. आर. शिवारामकृष्णन, — सदस्य
संयुक्त सलाहकार (शिक्षा),
योजना आयोग,
योजना भवन,
नई दिल्ली।

5.	श्री के. रामामूर्ति, सचिव, शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार, सचिवालय, गांधीनगर-302010	सदस्य
6.	डा. मैलकोलम एस. आदिशेषया, अध्यक्ष, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, 79, सैकिड मैन रोड, आडियार, मद्रास-600006.	सदस्य
7.	श्री जे. वीरराघवन, कार्यपालक निदेशक नीपा, नई दिल्ली ।	सदस्य
	श्री आर. पी. सक्सेना, रजिस्ट्रार, नीपा, नई दिल्ली ।	सचिव

परिशिष्ठ—3

नीपा की वित्तीय समिति के सदस्यों की सूची

(31-3-1982 को यथा स्थित)

1.	प्रो. मुनिस रज़ा, निदेशक, नीपा, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	श्री जे. ए. कल्याणकृष्णन, वित्तीय सलाहकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	श्री एस. राममूर्ति, संयुक्त सचिव (योजना), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
4.	श्री के. आर. शिवरामकृष्णन, संयुक्त सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।	सदस्य

5.	श्री एल. सी. गुप्ता, सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।	सदस्य
6.	श्री जे. वीरराघवन, कार्यपालक निदेशक, नीपा, नई दिल्ली।	विशेष आमंत्रित
	श्री आर. पी. सक्सेना, रजिस्ट्रार, नीपा, नई दिल्ली।	सचिव

परिशिष्ट—4

कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

31-3-82 को यथास्थिति

1.	प्रो० मुनिस रज़ा, निदेशक, नीपा, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	श्री एस० रामामूर्ति, संयुक्त सचिव (योजना), शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	श्री एस. सत्यम, संयुक्त सचिव (स्कूल शिक्षा), शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
4.	डा० अमरीक सिंह, सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002.	सदस्य

5. श्री के० आर० शिवरामकृष्णन, सदस्य
संयुक्त सलाहकार (शिक्षा),
योजना आयोग,
योजना भवन,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली ।

6. श्री आर. के. छाबड़ा, सदस्य
सचिव,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट
नई दिल्ली ।

7. श्री अशोक वाजपई, आई. ए. एस. सदस्य
सचिव, शिक्षा विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार,
बल्लभ भवन,
भोपाल-472004.

8. श्री वी. बी. चिपलुंकर, सदस्य
शिक्षा निदेशक,
महाराष्ट्र सरकार,
केन्द्रीय भवन,
पूना-411001.

9. प्रो० रईस अहमद, सदस्य
भौतिकी विभाग,
अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़ ।

10. प्रो० नितीश डे, सदस्य
मुख्य कार्यपालक (कार्मिक),
जी.इ. सी. ऑफ इंडिया लिमिटेड,
मैगनेट हाऊस, 6, चित्तरंजन एवेन्यू,
कलकत्ता-700072.

11.	डा० एस. डी. नरूला, सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002.	सदस्य
12.	श्री जे. वीरराघवन, कार्यपालक निदेशक, नीपा, नई दिल्ली।	सदस्य
13.	डा. एस.पी.सिंहल, परामर्शदाता, नीपा, नई दिल्ली।	सदस्य
14.	डा० सी. बी. पद्मनाभन, अध्येता, नीपा, नई दिल्ली।	सदस्य
	श्री आर. पी. सक्सेना, रजिस्ट्रार, नीपा, नई दिल्ली।	सचिव

परिशिष्ट—5

राष्ट्रीय संस्थान का संकाय और अनुसंधान स्टाफ

(31-3-1982 को यथास्थित)

प्रो. मुनिस रजा, निदेशक
श्री जे. वीरराघवन, कार्यपालक निदेशक
डा. आर. पी. सिंहल, परामर्शदाता
प्रो. एम. वी. माथुर, प्रतिष्ठित आचार्य
डा. सी. बी. पद्मनाभन, अध्येता
डा. आर. एन. चौधुरी, अध्येता
डा. सी. एल. सपरा, अध्येता
डा. एन. एम. भागिया, अध्येता
श्री के. जी. विरमानी, सहयोगी अध्येता
श्री एस. एस. दुदानी, सहयोगी अध्येता
श्री एम. एम. कपूर, सहयोगी अध्येता
डा. (श्रीमती) आर. एस. शफी, परियोजना अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा
डा. (श्रीमती) के प्रेमी, सहयोगी अध्येता
डा. जे. बी. जी. तिलक, सहयोगी अध्येता
श्री टी. के. डी. नायर, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी
डा. आर. एस. शर्मा, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी
श्री सी. मेहता, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी
डा. (श्रीमती) एस. भागिया, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी
डा. (श्रीमती) राधा शर्मा, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी
श्री वाई. पी. अग्रवाल, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी
डा. (कुमारी) के. सुजाता, अनुधान/प्रशिक्षण सहयोगी
श्री एन. वी. वरगीस, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी
डा. (श्रीमती) सुधा राव, अनुसंधान/प्रशिक्षण सहयोगी
कुमारी निर्मल मल्होत्रा, पुस्तकाध्यक्ष
श्री एन. डी. कंडपाल, पलेखन अधिकारी
डा. (श्रीमती) सुष्मा मेढ़, परियोजना समन्वयक (जनसंख्या शिक्षा)
डा. एस. पी. श्रीवास्तव, सहायक परियोजना समन्वयक (जनसंख्या शिक्षा)
डा. गोपेश कुमार भट्ट, परियोजना सहयोगी (लागत अध्ययन)

आई. सी. एस. एस. आर. परियोजना-स्टाफ

प्रो. एस. सी. दुबे, राष्ट्रीय अध्येता
डा. जे. एल. आजाद, वरिष्ठ अध्येता
डा. जे. एन. कौल, वरिष्ठ अध्येता

प्रकाशन

श्री बी. सेल्वराज, प्रकाशन अधिकारी

प्रशासन

श्री आर पी सक्सेना, रजिस्ट्रार
श्री के. एन. दुआ, प्रशासन अधिकारी
श्री एस. सुन्दरराजन, लेखा अधिकारी

परिशिष्ट—6

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1-4-1981 से 31-3-1982 तक की अवधि के लिए आय और भुगतान लेखा

आय			भुगतान	
रोकड़ जमा			**गैर योजना**	
हाथ रोकड़ शेष	167.50		अधिकारियों का वेतन	3,84,104.00
अग्रदाय	1,000.00		स्थापना का वेतन	2,79,600.55
बैंक रोकड़	3,12,247.66		भत्ते और मानदेय	5,61,391.25
		3,13,425.16	छुट्टी यात्रा रियायत	5,730.00
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता			अतिरिक्त समय भत्ता	42,672.50
			चिकित्सा प्रतिपूर्ति	24,626.95
गैर योजना	20,29,000.00		सी. जी. एच. एस. अंशदान	609.00
योजना	25,55,000.00		भविष्य निधि अंशदान (सी. पी. एफ. पर नियोक्ता का अंशदान तथा जी.पी.एफ./ सी. पी. एफ. ब्याज)	49,892.50
		45,84,000.66		
आवास किराया		3,258.80		
छात्रावास किराया		66,038.00		

सी. जी. एच. एस. वसूलियां		444.00
फुटकर कार्यालय आय		9,986.37
ब्याज		
1. निवेश पर ब्याज	13.25	
2. बचत बैंक खाते पर ब्याज	12,547.63	
3. ब्याज वाली अग्रिम राशि पर ब्याज	183.30	12,749.18
काम में न आने वाले मदों की बिक्री से प्राप्त राशि		
1. वाहनों का व्ययन	34,300.88	
2. अन्य मद	28,695.11	
		62,995.99
धन की वापसी		
सी. पी. एफ. अंशदान का नियोक्ता का हिस्सा		1,755.00
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	28,291.00	
पेंशन और उपदान	30,177.10	14,07,094.85
यात्रा भत्ता व्यय		49,320.10
अनुसंधान और प्रशिक्षण		
(1) यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	1,468.20	
(2) अध्येतावृत्तियां फीस / पुरस्कार/अतिथि वक्ताओं को मानदेय	22,320.90	
(3) मुद्रण और लेखन सामग्री	56,589.91	
(4) मनोरंजन प्रभार	11,337.35	
(5) फुटकर व्यय	9,880.75	1,10,597.11
कार्यालय खर्च (अन्य प्रभार)		
पानी और बिजली	61,790.98	
बीमा	1,114.00	

जमा

1. अग्रिम धन जमा	3,000.00	
2. सी. पी, डब्लू. डी. से धन की वापसी	1,53,727.60	
		1,56,727.60

वसूल किए जाने वाले अग्रिम

स्कूटर अग्रिम	600.00	
साइकिल अग्रिम	1,990.00	
त्यौहार अग्रिम	10,920.00	
बाढ़ अग्रिम	160.00	
मकान निर्माण अग्रिम	3,820.00	
		17,490.00

विविध देनदार

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	4,912.50	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2,659.50	
यू. एन. डी. पी.	20,919.82	
हरियाणा सरकार	350.20	
		28,842.02

टेलीफोन और ट्रंक काल	45,233.63
डाक व तार प्रभार	33,232.60
मुद्रण और लेखन सामग्री	39,399.92
वाहनों का अनुरक्षण	26,260.55
वर्दियां	10,880.64
फुटकर आकस्मिकताएं	90,996.45
लेखा परीक्षा फीस	10,500.00
किराया, दर और कर	63,491.10
भवन की देखभाल	1,13,043.08
मनोरंजन और आतिथ्य	7,215.13
उपस्कर का अनुरक्षण	64,468.66
फर्नीचर और जुड़नार का अनुरक्षण	3,024.00
पेट्रोल, तेल और स्नेहक	42,547.21
कुली प्रभार, ढुलाई और सीमा शुल्क	2,027.65

राज्य सरकार / संस्थाओं द्वारा अनुदानों की वापसी

बिहार सरकार	21.25	
राजस्थान सरकार	6,637.72	
एन. सी. ई. आर. टी.	5,058.40	
		11,717.37

(धन) प्रेषण

प्रतिनियुक्तों के जी. पी. एफ.		
सी. पी. एफ.	57,286.90	
आयकर	38,922.00	
मकान निर्माण अग्रिम	11,280.00	
सी. जी. ई. आई. एस.	222.50	
सी. जी. ई. जी. आई. एस.	400.00	
स्कूटर अग्रिम	600.00	
अनाज अग्रिम	45.00	
समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं	32,410.17	
बागवानी का अनुरक्षण	4,181.65	
विज्ञापन	31,743.15	
		6,83,560.57

योजना

अधिकारियों का वेतन	42,964.30	
स्थापना का वेतन	35,885.35	
भत्ते और मानदेय	76,060.95	
अतिरिक्त समय भत्ता	2,254.30	
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,992.20	
		1,59,157 10

अनुसंधान और प्रशिक्षण

(1) यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता	12.943.55	
(2) अध्येतावृत्ति फीस / पुरस्कार / अतिथि वक्ताओं को मानदेय	11,750.00	
(3) मुद्रण और लेखन सामग्री	1,00,208.80	
(4) अभिकलित्र लेखन सामग्री	5,362.50	

अदालत वसूली	4,800,00	
पी.आर.एस.एस.	12,790.00	
जल और विद्युत प्रभार	310.00	
		1,26,656.40
जी.पी.एफ. / सी.पी.एफ. अभिदान तथा संस्थान के स्टाफ के अग्रिम की वापसी		1,40,827.00
यूनेस्को कूपनों की खरीद		9,150.00

परामर्शता

स्कूल भवन के निर्माण के लिए नए मानक स्थापित करना— हरियाणा सरकार	25,000.00

सुपुर्द कार्यक्रम और अध्ययन

अनुसंधान परियोजना—
गृह मंत्रालय

(i) आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन		
(5) मनोरंजन प्रभार	7,721.65	
(6) फुटकर खर्च	15,768.50	
		1,53,755.00

गुड़गांव जिले में शिक्षा की लागत पर अध्ययन

वेतन पर भत्ते	14,961.70	
यात्रा भत्ते	470.50	
आकस्मिक व्यय	934.50	
		16,366.70
प्रकाशन व्यय		1,00,782.54

जमा

(1) जमा अग्रिम धन की वापसी	3,000.00	
(2) प्रतिभूति जमा	2,840.00	
(3) भवन निर्माण के लिए सी. पी. डब्ल्यू. डी. में जमा	15,22,566.00	

(ii) अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिए तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण	30,000.00		
2. नमूना अध्ययन—शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए तथा विकसित राज्यों में निरीक्षण पद्धति तथा अभ्यास और प्रोफार्मा—शिक्षा मंत्रालय	25,000.00		
3. अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर अध्ययन—गृह मंत्रालय	1,20,000.00		
4. जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एन.सी.ई.आर.टी.)	44,250.00		
यूनेस्को प्रायोजित कार्यक्रम			
(i) लम्बे समय तक की शैक्षिक योजना पर कार्यशाला	54,654.10		
(4) मैटाडोर तथा तीन पहिया वाले वाहनों के लिए जमा	1,24,733.51		16,53,139.51
पूंजीगत व्यय			
फर्नीचर और जुड़नार	1,04,252.00		
टाइपराइटर	37,903.32		
कार्यालय के अन्य उपस्कर	1,70,571.49		
पुस्तकालय पुस्तकें	1,89,751.49		5,02,478.30
वसूल किए जाने वाले अग्रिम			
(1) साईकिल अग्रिम	825.00		
(2) त्यौहार अग्रिम	10,000.00		
(3) मकान निर्माण अग्रिम	1,01,900.00		
(4) फुटकर अग्रिम	350.00		1,13,675.00
विविध देनदार			
आर. पी. एफ. (सी. डी. एस.)			278.63

(ii) शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र में अंतर्देशीय परस्पर आदान-प्रदान	1,841.62	56,495.72
अच्छे जीवन स्तर के लिए कार्य की आकांक्षा पर अध्ययन		20,000.00
आई.सी.एस.एस.आर. अध्येतावृत्ति		
(1) प्रो. एस. सी. दुबे को राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	35,542.00	
(2) डा. जे. एल. आजाद को वरिष्ठ अध्येतावृत्ति	10,450.00	
		45,992.00
उचंत लेखा		5,134.50
राज्य सरकारों / संस्थाओं को अनुदान सहायता		
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालिज, हैदराबाद		7,500.00
ऋण (प्रेषण)		
(1) प्रतिनियुक्तियों के जी.पी.एफ./सी.पी.एफ.	57,286.90	
(2) आयकर	38,922.00	
(3) मकान निर्माण अग्रिम	11,280.00	
(4) सी.जी.ई.आई.एस.	222.50	
(5) सी. जी. ई. जी. आई. एस.	400.00	
(6) स्कूटर अग्रिम	600.00	
(7) अनाज अग्रिम	45.00	
(8) अदालत वसूली	4,800.00	
(9) पी. आर. एस. एस.	12,790.00	
(10) जल और विद्युत प्रभार	1,204.15	
		1,27,550.55

जी. पी. एफ./सी. पी. एफ.	
अभिदान और संस्थान के	
स्टाफ द्वारा अग्रिम राशि	
की वापसी	1,40,827.00
यूनेस्को कूपनों की खरीद	9,150.00

परामर्शता

स्कूल भवन के निर्माण के लिए	
नए मानक विकसित करना,	
हरियाणा सरकार	4,684.20

सुपुर्द कार्यक्रम और अध्ययन

अनुसंधान कार्यक्रम—

गृह मंत्रालय

(i) आश्रम स्कूल का गहन

अध्ययन

(ii) अनुसूचित जातियों / जनजातियों के लिए तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण		
स्थापना प्रभार	39,556.85	
यात्रा और आकस्मिक व्यय	8,835.40	
क्षेत्र लागत	53,200.00	
फुटकर व्यय	207.00	
		1,01,799.25

जनसंख्या शिक्षा परियोजना

(एन. सी. ई. आर. टी.)		
वेतन तथा भत्ते	22,466.65	
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	3,735.80	
आकस्मिक व्यय	2,281.50	
		28,48395

यूनेस्को प्रायोजित कार्यक्रम

(i) भारत में स्कूल नामांकन का प्रक्षेपण की विधि पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी	5,738.65	

(ii) लम्बे समय तक की शैक्षिक योजना पर कार्यशाला		64,851.81	
			70,590.46
अच्छे जीवन स्तर के लिए कार्य की आकांक्षा पर अध्ययन			2,472.00
आई. सी. एस. एस. आर. अध्येतावृत्ति			
(1) प्रो. एस. सी. दुबे को राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति वेतन और भत्ते		35,602 50	
अनुसंधान सहायता		7,600.00	
आकस्मिक व्यय	12,209.41	55,411.91	
(2) डा. जे. एल. आज़ाद को वरिष्ठ अध्येतावृत्ति	6,000.00		

आकस्मिक	2,416 55		
		8,416.55	63,828.46
			167.50

उचंत लेखा

रोकड़ बाकी

हाथ रोकड़	168.60	
अग्रदाय	1,000.00	
यूनेस्को कूपन	1,143.75	
बैंक में	4,17,363.98	
		4,19,676.33
योग	59,17,935.11	योग 59,17,935.11

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई अनुदान सहायता जिस उद्देश्य के लिए दी गई थी उसी के लिए उपयोग में ली गई और इसके साथ लगाई गई शर्त का पूरी तरह पालन किया गया है।

(एस० सुन्दरराजन)	(जे० वीरराघवन)	(मुनिस रजा)
लेखा अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान	प्रशासन संस्थान	प्रशासन संस्थान

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

31 मार्च 1982 तक रोकड़ बाकी का विवरण

क्रम सं०	शीर्ष का नाम	रोकड़ जमा	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल आय	कुल भुगतान	अंत शेष
1.	गैर-योजना	2 01,464.02	20,29 000.00		23,58,087.63	2,00,821.33
	कार्यालय आय		3,23,444.94	25,58,908.96		
2.	योजना	44,867.94	25,55,000.00		25,87,617.78	31,539.53
	कार्यालय आय		19,289.37	26,19,157.31		
3.	हरियाणा सरकार (—) (परामर्शता के लिए)	350.20	25,000,00	24,649.80	4,334.00	20,315.80
	सुपुर्द कार्यक्रम					
4.	यूनेस्को					

(क) शिक्षा के स्थानीय सहयोग का प्रबंध	4,549.90	—	4,549.90	—	4,549.90
(ख) स्कूल नामांकन के प्रक्षेपण की विधियों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण गोष्ठी	17,846.16	—	17,846.16	5,738.65	12,107.51
(ग) ए. पी. ई. आई. डी. प्रकाशनों का अनुवाद	(—) 1,081.84	—	(—) 1,081.84	—	(—) 1,081.84
(घ) शिक्षा सुविधाओं के क्षेत्र में अंतरदेशीय अनुभवों के आदान-प्रदान	(—) 7,473.80	1,841.62	(—) 5,632.18	—	(—) 5,632.18
(ङ) लम्बे समय की शैक्षिक योजना पर क्षेत्रीय कार्यशाला	—	54,654.10	54,654.10	64,851.81	(—) 10,197.71
5. अच्छे जीवन स्तर के कार्य की आकांक्षा (ए. ए. बी. थ्यू. ओ. एल.)	—	20,000.00	20,000,00	2,472.00	17,528.00

6. यू. एन. डी. पी.						
अफगानिस्तान से यूनेस्को अध्येतावृत्ति पाने वालों के लिए शिक्षा योजना प्रशासन और सांख्यिकी का प्रशिक्षण कार्यक्रम	(—)	20,919.82	20,919.82	—	—	—
7. गृह मन्त्रालय						
(क) अनुसंधान परियोजनाएं						
(i) आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन						
(ii) अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिए तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण		50,000.00	30,000.00	80,000.00	1.01,799.25	(—) 21,799.25
(ख) अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर अध्ययन		—	1,20,000.00	1,20,000.00	—	1,20,000.00

8. शिक्षा मन्त्रालय					
एक नमूना अध्ययन : शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों तथा विकसित राज्यों में निरीक्षण पद्धति तथा अभ्यास और प्रोफार्मा	—	25,000.00	25,000.00	—	25,000.00
9. एन. सी. ई. आर. टी.					
जनसंख्या शिक्षा परियोजना	—	44,250.00	44,250.00	28,483.95	15,766.05
10. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद					
(क) प्रो. एस. सी. दुबे को दी गई राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	24,355.30	35,642.00	59,897.30	55,411.91	4,485.39
(ख) डा. जे. एल. आज़ाद को दी गई वरिष्ठ अध्येतावृत्ति	—	10,450.00	10,450.00	8,416.55	2,033.45

11.	(धन) प्रेषण	—	—	1,26,656.40	1,27,550.55	(—) 894.15
12.	उचंत लेखा	167.50	5,134.50	5,302.00	167.50	5,134.40
					अंत शेष	4,19,676.33

ब्यौरा :—

हाथ रोकड़	168.60
अग्रदाय	1,000.00
यूनेस्को कूपन	1,143.75
बैंक रोकड़	4,17,363.98
	4,19,676.33

(एस० सुन्दरराजन)
लेखा अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

(जे० वीरराघवन)
कार्यपालक निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

(मुनिस रजा)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1981-82 वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

व्यय			आय			
गैर-योजना			**भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता**			
अधिकारियों का वेतन	3,84,104.00		गैर-योजना	20,29,000.00		
स्थापना का वेतन	2,79,600.55		योजना	25,55,000.00	45,84,000.00	
भत्ते और मानदेय	5,61,391.25		**पूंजीकृत अनुदान घटाकर**			
छुट्टी यात्रा रियायत	5,730.00		पुस्तकालय पुस्तकें	1,89,751.49		
अतिरिक्त समय भत्ता	42,672.50		फर्नीचर, जुड़नार, टाइपराइटर तथा कार्यालय के अन्य उपस्कर	3,12,726.81		
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	24,626.95		वाहनों के लिए जमा	1,24,733.51	6,27,211.81	39,56,78 .19
सी. जी. एच. एस. अंशदान	609.00					
भविष्य निधि अंशदान (जी पी एफ और सी पी एफ पर ब्याज और सी पी एफ पर नियोक्ता का हिस्सा	49,892.50					

छुट्टी वेतन और पेंशन		
अंशदान	28,291.00	
पेंशन और उपदान	30,177.10	
		14,07,094 85
यात्रा भत्ता व्यय		49,320.10
गैर-योजना		
अनुसंधान और प्रशिक्षण		
(1) यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता	1,468.20	
(2) अध्येता वृत्ति फीस/ अतिथि वक्ताओं को पुरस्कार/मानदेय	22,320.90	
(3) मुद्रण और लेखन सामग्री	56,589.91	
(4) मनोरंजन प्रभार	11,337.35	
(5) फुटकर व्यय	9,880.75	1,01,597.11

लाइसेंस फीस		3,258.80
छात्रावास किराया		66,038.00
सी. जी. एच. एस. वसूलियां		444.00
फुटकर कार्यालय आय		9,986.37
ब्याज		
(1) पूंजी निवेश पर ब्याज	13.25	
(2) बचत खाते पर ब्याज	12,547.63	
(3) ब्याज वसूल किए जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज	188.30	
प्रयोग में न आने वाले मदों की बिक्री से प्राप्त आय		12,749.18
(1) वाहनों का व्ययन	34,300.88	
(2) अन्य मद	28,695·11	62,995.99
(धन) वापसी		
नियोक्ता का सी. पी. एफ. अंशदान के हिस्से को समपहरण	1,755.00	

कार्यालय व्यय (अन्य प्रभार)

जल और विद्युत	61,790.98
बीमा	1,114.00
टेलीफोन तथा ट्रंककाल प्रभार	45,233.63
डाक और तार प्रभार	33,232.60
मुद्रण और लेखन सामग्री	39,399.92
वाहनों का अनुरक्षण	26,260,55
वर्दियां	10,880.64
फुटकर आकस्मिकताएं	90,996.45
लेखापरीक्षक फीस	10,500.00
किराया, दर और कर	63,491.10
भवनों का अनुरक्षण	1,13,043 08
मनोरंजन और अतिथि सत्कार	7,215,13

अनुदानों की खर्च न की गई राशि की वापिसी

(1) बिहार सरकार		21.25	
(2) राजस्थान सरकार	6,637.72		
(3) एन सी ई आर टी	5,058.40	11,717.37	13,472.37

परामर्शदात्री

स्कूल भवन निर्माण आदि के लिए नए मानकों का विकास— हरियाणा सरकार	25,000.00

उपस्कर का अनुरक्षण	64,468.66	
फर्नीचर और जुड़नार का अनुरक्षण	3,024.00	
पेट्रोल, तेल और स्नेहक	42,547 21	
कुली खर्च ढुलाई और सीमा शुल्क	2,027.65	
विज्ञापन	31,743.15	
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	32,410 17	
बागवानी का अनुरक्षण	4,181.65	
योजना		6,83,560.57
अधिकारियों का वेतन	42,964.30	
स्थापना का वेतन	35,885.35	
भत्ते और मानदेय	76,060 95	
अतिरिक्त समय भत्ता	2,254.30	
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,992.20	
		1,59,157.10

योजना

अनुसंधान और प्रशिक्षण

(1) यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता	12,943.55	
(2) अध्येतावृत्ति फीस/ पुरस्कार/अतिथि वक्ताओं को मानदेय	11,750 00	
(3) मुद्रण और लेखन सामग्री	1,00,208.80	
(4) अभिकलित्र लेखन सामग्री	5,362.50	
(5) मनोरंजन प्रभार	7,721.65	
(6) फुटकर व्यय	15,768.50	1,53,755.00

गुड़गांव जिले में शिक्षा की लागत पर अध्ययन

वेतन और भत्ते	14,961.70	
यात्रा भत्ते	470.50	
आकस्मिक व्यय	934.50	16,366.70
प्रकाशन व्यय		1,00,782.54

राज्य सरकारों/संस्थाओं		
को अनुदान सहायता		
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ		
कालिज, हैदराबाद	7,500.00	
परामर्शता		
स्कूल भवन आदि के निर्माण		
के लिए नए मानकों का विकास—		
हरियाणा सरकार	4,684.20	
खर्च पर आय का आधिक्य	14,66,914.73	
योग	41,50,732.90	41,50,732.90

(एस. सुन्दरराजन)
लेखा अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

(जे. बीर राघवन)
कार्यपालक निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

(मुनिस रजा)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

31-3-1982 को समाप्ति पर तुलन-पत्र

देयताएं			परिसम्पत्तियां		
पूंजीकृत अनुदान			**भूमि और भवन**		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार बकाया राशि	41,83,020.48		उपस्कर तथा मशीनरी/ फर्नीचर तथा जुड़नार स्टाफकार सहित वाहन, टाइपराइटर आदि		20,01,586.09
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,27,211.81	48,10,232.29	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	15,12,965.96	
खर्च पर आय का आधिक्य			वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,37,460.32	19,50,426.28
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	35,88,522.76		निपटाई हुई (निर्वतित) परिसंपत्तियों का मूल्य		57,655.09
वर्ष के दौरान परिवर्धन	14,66,914.73	50,55,437.49			
सुपुर्द कार्यक्रमों/अध्ययनों/ अध्येतावृत्तियों पर खर्च न किया गया अनुदान शेष			**पुस्तकालय पुस्तकें**		
गृह मंत्रालय	98,200.75		पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	6,62,634.12	
शिक्षा मंत्रालय	25,000,00				

एन. सी. ई. आर. टी.	15,.766.05	
ए ए बी क्यू ओ एल अध्ययन	17,528.00	
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	6,518.84	1,63,013.64
भविष्य निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,39,079.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,91,506.00	
वर्ष के दौरान अंतिम भुगतान को घटाकर	1,26,540.00	4,04,045.00
उचंत लेखा		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	167.50	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,134.50	
वर्ष के दौरान निकासी घटाकर	167.50	6,134.50
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,89,751.49	8,52,385.61
भविष्य निधि का निवेश		
पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,98,357.50	2,98,357.50
सुपुर्द कार्यक्रमों/अध्ययनों आदि पर वसूल योग्य राशि		
यूनेस्को		254.32
जमा और निवेश		
प्रतिभूतियां जमा पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	2,300.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,840.00	5,140.00

उपहार और दान

पिछले तुलन पत्र के अनुसार (पुस्तकालय पुस्तकें)	910.52	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	—	910.52
पूंजी निवेश बट्टे खाते में डालकर		57,655.09

सी. पी. डब्लू. डी.

पिछले तुलन पत्र के अनुसार	33,27,763.63	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	15,22,566.00	
वर्ष के दौरान धन वापिसी को घटाकर	1,53,727.60	46,96,602.03

वसूल किए जाने वाले अग्रिम

त्यौहार अग्रिम	6,780.00	
साइकिल अग्रिम	575.00	
मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम	1,700.00	
भवन निर्माण अग्रिम	98,080.00	
फुटकर अग्रिम	350.00	1,07,485.00

विविध देनदार

लेखा परीक्षा निदेशक केन्द्रीय राजस्व	9,398.00

		आर. पी. एफ. आयुक्त		
		(सी डी एस)	278.63	9,676.63
		(धन) प्रेषण		
		वसूली योग्य जल और		
		विद्युत प्रभार		894.15
		रोकड़ बाकी		
		हाथ रोकड़	168.60	
		अग्रदाय	1,000.00	
		यूनेस्को कूपन	1.143.75	
		बैंक में : चालू खाता	4,17,363.98	
		बचत बैंक खाता	96,289.50	5,15,965,83
योग	1,04,96,428.53		योग	1,04,96,428.53

नोट :—उपस्कर, मशीनरी, फर्नीचर तथा जुड़नार और वाहनों आदि में वर्ष के दौरान होने वाले परिवर्धन में 1,24,733.51 रुपये की राशि सम्मिलित है जो एक मैटाडोर और तीन पहियों वाले स्कूटर की ख़रीद के लिए डी० जी० एस० तथा डी० और एम० एस० एलाइड मोटर लिमिटिड को अग्रिम राशि के रूप में दी गई है।

(एस०सुन्दरराजन)	(जे० वीरराघवन)	(मुनिस रज़ा)
लेखा अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

वर्ष 1981-82 में नियत कार्यक्रमों / अध्येतावृत्ति के लिए प्राप्त अनुदानों का लेखा प्रपत्र

(यूनेस्को, यू० एन० डी० पी०, हरियाणा, आई० सी० एस० एस० आर०, गृह मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय, एन० सी० ई० आर० टी०)

प्राप्ति			अदायगी	
1. यूनेस्को			स्कूल नामांकन के प्रक्षेपण	
(क) शिक्षा की स्थानीय सहायता का प्रबंध			की विधियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण	
रोकड़ जमा	4,549.90		संगोष्ठी	5,738.65
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	शून्य		लम्बे समय तक की शैक्षिक योजना पर कार्यशाला	64,851.81
		4,549.90	अंतिम शेष	
(ख) स्कूल नामांकन के प्रक्षेपण की विधियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी			(क) शिक्षा के स्थानीय समर्थन का प्रबंध	4,549.90

रोकड़ जमा 17,846.16

वर्ष के दौरान

प्राप्त राशि शून्य 17,846.16

(ग) ए. पी. ई. आई. डी.

का प्रकाशन

रोकड़ जमा (—) 1,081.84

वर्ष के दौरान

प्राप्त राशि शून्य (—) 1,081.84

(घ) शैक्षिक सुविधाओं के

क्षेत्र में अंतर्देशीय अनुभव

का विनिमय

रोकड़ जमा (—) 7,473.80

वर्ष के दौरान

प्राप्त 1,841.62 (—) 5,632.18

(ख) पद्धतियों पर राष्ट्रीय

प्रशिक्षण संगोष्ठी 12,107.51

(ग) ए पी इ आई डी

प्रकाशन (—) 1,081.84

(घ) अनुभवों का अंत:

राष्ट्रीय विनिमय (—) 5,632.18

(ङ) लम्बे समय तक की

शैक्षिक योजना पर

कार्यशाला (—) 10,197.71 (—) 254 32

(ङ) लम्बे समय तक की शैक्षिक योजना पर कार्यशाला					
रोकड़ जमा वर्ष के दौरान प्राप्त	54,654.10	54,654.10			
	योग	70,336.14		योग	70,336,14
2. अच्छे जीवन स्तर के लिए कार्य की आकांक्षा (ए ए बी क्यू ओ एल)			वर्ष के दौरान किया गया व्यय अंतिम शेष		2,472.00 17,528.00
रोकड़ जमा वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	20,000.00	20,000.00			
	योग	20,000.00		योग	20,000.00

3. यू. एन. डी पी.

अफगानिस्तान के यूनेस्को			वर्ष के दौरान किया	
अध्येतावृत्ति धारक के लिए			गया व्यय	शून्य
शैक्षिक योजना : प्रशासन				
और सांख्यिकी प्रशिक्षण				
के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम				
रोकड़ शेष	(—) 20,919.82			
वर्ष के दौरान				
प्राप्त राशि	20,919.82	शून्य		
			अंतिम शेष	शून्य
	योग	शून्य	योग	शून्य

4. हरियाणा सरकार					
स्कूल भवन के निर्माण के लिए नए मानकों का विकास					
रोकड़ शेष	(—) 350.20				
समायोजन द्वारा प्राप्त राशि	350.20	शून्य	अंतिम शेष		शून्स
	योग	शून्य		योग	शून्य
5. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद					
(1) प्रो० एस. सी. दुबे को दी गई राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति			(1) राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति :	55,411.91	
			(2) वरिष्ठ अध्येतावृत्ति :	8,416.55	63,828.46

रोकड़ जमा	24,355.30				
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	35,542.00	59,897.30			

(2) डा० जे० एल० आजाद को

दी गई वरिष्ठ अध्येतावृत्ति रोकड़ जमा	शून्य		अंतिम शेष (1) राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	4,485.39	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	10,450.00		(2) वरिष्ठ अध्येतावृत्ति	2,033.45	6,518.84
	योग	70,347.30	योग		70,347.30

6. **गृह मंत्रालय (भारत सरकार)**

अनुसंधान परियोजनायें

(i) आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन तथा

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण

रोकड़ जमा	50,000.00				
वर्ष के दौरान					
प्राप्त राशि	30,000.00	80,000 00	किया गया खर्च		1,01,799.25
			अंतिम शेष	(—)	21,799.25
	योग	80,000 00			
				योग	80,000.00

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर अध्ययन

रोकड़ जमा	शून्य				
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	1,20,000.00	1,20,000.00	व्यय		शून्य
			अंतिम शेष		1,20,000.00
	योग	1,20,000.00			1,20,000.00

7. शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार)

एक नमूना अध्ययन : शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों और विकसित राज्यों में निरीक्षण

पद्धति और अभ्यास तथा प्रपत्र

रोकड़ जमा वर्ष के दौरान	शून्य				
प्राप्त राशि	25,000.00	25,000.00	किया गया खर्च		शून्य
			अंतिम शेष :		25,000.00
	योग	25,000.00			
				योग	25,000 00

8. **जनसंख्या शिक्षा परियोजना**
(एन सी ई आर टी)

रोकड़ जमा वर्ष के दौरान प्राप्त	शून्य				
			किया गया खर्च		28,483.95
राशि	44,250.00	44,250.00	अंतिम शेष		15,766.05
	योग	44,250 00		योग :	44,250.00

(एस० सुन्दरराजन)
लेखा अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

(जे० वीरराघवन)
कार्यपालक निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

(मुनिस रजा)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

4. हरियाणा सरकार					
स्कूल भवन के निर्माण					
के लिए नए मानकों का					
विकास					
रोकड़ शेष	(—) 350.20				
समायोजन द्वारा					
प्राप्त राशि	350.20	शून्य	अंतिम शेष		शून्स
	योग	शून्य	योग		शून्य
5. भारतीय सामाजिक विज्ञान					
अनुसंधान परिषद					
(1) प्रो० एस. सी. दुबे को					
दी गई राष्ट्रीय			(1) राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति :	55,411.01	
अध्येतावृत्ति			(2) वरिष्ठ अध्येतावृत्ति :	8,416.55	63,828.46

रोकड़ जमा	24,355.30				
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	35,542.00	59,897.30			
(2) डा० जे० एल० आजाद को दी गई वरिष्ठ अध्येतावृत्ति			अंतिम शेष		
रोकड़ जमा	शून्य		(1) राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	4,485.39	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	10,450.00		(2) वरिष्ठ अध्येतावृत्ति	2,033.45	6,518.84
	योग	70,347.30		योग	70,347.30

6. **गृह मंत्रालय (भारत सरकार)**

अनुसंधान परियोजनायें

(i) आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन तथा

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण

रोकड़ जमा	50,000.00				
वर्ष के दौरान					
प्राप्त राशि	30,000.00	80,000 00	किया गया खर्च		1,01,799.25
			अंतिम शेष	(—)	21,799.25
	योग	80,000 00			
				योग	80,000.00

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर अध्ययन

रोकड़ जमा	शून्य				
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	1,20,000.00	1,20,000.00	व्यय		शून्य
			अंतिम शेष		1,20,000.00
	योग	1,20,000.00			1,20,000.00

7. **शिक्षा मंत्रालय** (भारत सरकार)

एक नमूना अध्ययन : शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों और विकसित राज्यों में निरीक्षण

पद्धति और अभ्यास तथा प्रपत्र					
रोकड़ जमा	शून्य				
वर्ष के दौरान					
प्राप्त राशि	25,000.00	25,000.00	किया गया खर्च		शून्य
			अंतिम शेष :		25,000.00
	योग	25,000.00		योग	25,000 00

8. **जनसंख्या शिक्षा परियोजना**
(एन सी ई आर टी)

रोकड़ जमा	शून्य				
वर्ष के दौरान प्राप्त					
			किया गया खर्च		28,483.95
राशि	44,250.00	44,250.00	अंतिम शेष		15,766.05
	योग	44,250 00		योग :	44,250.00

(एस० सुन्दरराजन)
लेखा अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

(जे० वीरराघवन)
कार्यपालक निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

(मुनिस रजा)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन सस्थान
नई दिल्ली

वर्ष 1981-82 के लिए जी० पी० एफ० / सी० पी० एफ० लेखों का लेखा प्रपत्र

आय			भुगतान		
			वर्ष के दौरान भुगतान	1,26,540.00	
रोकड़ जमा	3,29,681.00		पूंजी निवेश	2,98,357.50	4,24,897.50
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	1,91,506.00	5,21,187.00	अंतिम शेष		96,289.50
	योग :	5,21,187.00		योग :	5,21,187.00

160

(एस० सुन्दरराजन)
लेखा अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

(जे० वीरराघवन)
कार्यपालक निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

(मुनिस रज़ा)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली (पहले शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कालिज, नई दिल्ली) के वर्ष 1981-82 के पूर्ववर्ती लेखाओं की जांच कर ली है और सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखा परीक्षा में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और मुझे दिए गए उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और संस्थान के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ताक्षर
(एम० एम० मेहता)
निदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

दिनांक : 11 जनवरी 1983
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के वर्ष 1981-82 पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1. **सामान्य** : संस्थान मुख्यत: भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों से वित्तपोषित होती है। इसको वर्ष 1981-82 के दौरान 45.84 लाख रु० की राशि अनुदानों के रूप में प्राप्त हुई।

2. **तुलन-पत्र**

2.1 **देयताएं**—31 मार्च, 1982 को बिजली तथा जल प्रभार 4,33,708.26 रुपये थे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, बिजली तथा अनुरक्षण प्रभारों के संबंध में 4.34 लाख रुपये की ऋणी थी जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

		रुपये
जनवरी 1979 से फरवरी 1981 की अवधि तक बिजली प्रभार		1,64,988.30
अप्रैल 1979 से मार्च 1981 तक अनुरक्षण प्रभार		29,054.70
अंतिम बिल के अनुसार शेष		2,89,665.26
	जोड़	4,83,708.26
घटाएँ—1981-82 के दौरान की गई अदायगी		50,000.00
शेष जिसका भुगतान करना था		4,33,708.26

देयताएं तुलन-पत्र में नहीं दर्शायी गई थी।

2.2 संस्थान के भवन में, वर्ष के दौरान निम्नलिखित अतिरिक्त निर्माण किया गया था।

	लाख रुपये
भवन का द्वितीय तल	5.72
मनोरंजन कक्ष तथा गैरेज	2.15
जोड़	7.87

यद्यपि संस्थान के भवन में अतिरिक्त किए गए निर्माण का इस्तेमाल शुरू कर दिया था तथापि उसकी लागत को पूंजीगत नहीं किया गया था। 31 मार्च 1982 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जमा के अन्तर्गत तदनरूपी कमी करते हुए उनकी निर्माण लागत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रभारित व्यय के रूप में तुलन-पत्र में "भूमि तथा भवन" के अन्तर्गत परिसम्पत्ति में जमा कर दी गई थी।

2.3 प्राप्ति और भुगतान लेखाओं में निम्नलिखित प्राप्तियां बेकार वस्तुओं की बिक्री आय के अन्तर्गत दिखाई गई थी :

		रुपये
1.	वाहनों की बिक्री	34,300.88
2.	अन्य वस्तुएं	28,695.11

किन्तु तुलन-पत्र में परिसम्पत्ति से संबंधित अंकित मूल्य की 57,655.09 रुपये की राशि को बेकार परिसम्पत्तियों (अन्य वस्तुएं) को जो 28,695.11 रु० में बेच दी गई थी, के नाम पर बट्टे खाते डाल दिया था। 34,300.88 रु० में बेचे गए बेकार वाहनों का अंकित मूल्य तुलन-पत्र में से बट्टे खाते नहीं डाला गया था।

संस्थान ने बताया (नवम्बर 1982) कि 1981-82 में बिक्री किए गए वाहन शुरू में यू.एन.ई.एस.सी.ओ. द्वारा उपहार में दिए गए थे। 1975 में ये वाहन भारत सरकार द्वारा संस्थान को हस्तान्तरण कर दिए गए थे तथा कुल हस्तान्तरित परिसम्पत्तियों के मूल्य को (रुपयों में) लेखाओं में शामिल कर लिया था। किन्तु प्रत्येक वाहन का अन्तरण के समय अंकित मूल्य विदेशी मुद्रा में बताया गया जिसके समतुल्य रुपयों में राशि बट्टे खाते डाली गई राशि के प्रति समायोजन करने हेतु संस्थान द्वारा सरकार से सुनिश्चित की जा रही थी।

हस्ताक्षर

दिनांक : 11 जनवरी 1983 (एम० एम० मेहता)
नई दिल्ली निदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

...ARY & DO... ...
...ational Institute ... Educational
Planning and Administration.
17 B Sri Aurobindo Marg,
New Delhi 110016
...No ... D-9362
... 5-12-96